योजना

वर्ष : 61 • अंक 06 • जून 2017 • ज्येष्ठ-आषाढ़, शक संवत् 1939 • कुल पृष्ठ : 64

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971
ईमेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह
(प्रसार एवं विज्ञापन)
ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: गजानन पी. धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनी. ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महा. निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही www.publicationsdivision.nic.in तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस अंक में

- **संपादकीय** 7
- भारतीय युवा: उभरती ताकत
  ए के दूबे 9
- भारत में युवाओं के लिए रोजगार सृजन की चुनौतियां
  अलख एन शर्मा, बलवंत सिंह मेहता 13
- **विशेष आलेख**

  रोजगार प्रदाताओं के देश का निर्माण
  सौरभ सान्याल, रंजीत मेहता 17
- **क्या आप जानते हैं?** 20
- युवा: परिवर्तन के वाहक
  सुनीता सांघी 21
- भारतीय युवाओं की वैश्विक मौजूदगी
  शीतल शर्मा, भास्कर ज्योति 27
- **फोकस**

  योग, युवा और स्वास्थ्य
  ईश्वर एन आचार्य, राजीव रस्तोगी.... 31
- युवा सशक्तीकरण और योग
  ईश्वर वी बसवरेड्डी 35
- स्वास्थ्य की कसौटी पर युवा
  आशुतोष कुमार सिंह 39
- सशक्त युवा के लिए समन्वित नीतियां जरूरी
  श्याम सुन्दर प्रसाद 43
- युवा आकांक्षाओं के समक्ष चुनौतियां
  ऋतु सारस्वत 47
- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवा केंद्रित योजनाएं
  शुभम वर्मा 51
- युवा शक्ति और विज्ञान
  मनीष मोहन गोरे 55
- जीएसटी: परिवर्तन का वाहक
  डी एस मलिक 59
- नये प्रकाशन 62

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नयी	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	50080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी	781003	030-2665090

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

आपकी राय

श्रमिक कल्याण अंक: सजग प्रयास

श्रमिक दिवस से एक माह पूर्व ही योजना पत्रिका में श्रमिकों की दशा-दिशा पर केंद्रित अंक छपवाकर संपादकीय मंडली ने अपनी सजगता और संकल्प का परिचय दिया है। इसके लिए आप सभी को आभार। आज जब नागरिकों को वृद्धि के नाम पर विकास के भ्रम में रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर बुद्धिजीवी लोग लफ्फाजी और विवाद में लगे हैं, उस दौर में संवाद और सूचनाओं के नये पट खोलती योजना पत्रिका का अप्रैल अंक भी वैचारिक विशिष्टता और तथ्यात्मक सुदृढ़ता से परिपूर्ण था।

इस अंक के प्रत्येक लेख का अपना अलग ही महत्व है। इस पत्र में हर लेख पर विस्तृत चर्चा तो नहीं की जा सकती किंतु कुछ पंक्ति और विचार ऐसे थे, जिन्हें शब्द देना आवश्यक है। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से तो परिचय था किंतु उनकी वैचारिक स्पष्टता ने उनका मुरीद बना दिया। "बाल मजदूरी की वजह से ही गरीबी है'' इस विश्लेषण के बाद जाना कि बाल मजदूरी मात्र सामाजिक ही नहीं आर्थिक विकृति भी है।

नीता एन. के अनुसार "ग्रामीण व शहरी दोनों परिवारों में यद्यपि लड़कियों को पढ़ाने की इच्छा शक्ति बढ़ी है किंतु फिर भी उसे रोजगार हेतु निवेश के रूप में नहीं देखते'' यह पंक्ति आज की हर लड़की का अनुभवजन्य सत्य है। इस मसले पर हम सबको संजीदा होने की जरूरत है। इस अंक का प्रत्येक लेख अपने आप में विशिष्ट है सभी लेखों में तटस्थता के साथ समस्याओं को उजागर ही नहीं किया गया है अपितु समाधान की राह भी दिखायी गयी है। आकर्षक आवरण, रंगीन पृष्ठ और आंकड़ा तालिकाओं के संयोजन ने विचारों और तथ्यों को आकर्षक रूप में संवारा है। योजना पत्रिका के सभी सदस्यों को साधुवाद। इस दिशा में संवाद जारी रखें।

– राखी सिंह
रामानुजन महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)

सुरक्षित बचपन से ही सुरक्षित देश

योजना का श्रमिक कल्याण पर केंद्रित अप्रैल 2017 का अंक पढ़ा। अंक से कई रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में समर्पित छात्रा हूं तथा इस पत्रिका का अध्ययन विगत 1 वर्ष से कर रही हूं। किसी देश को वृद्धि और विकास के लिए श्रमिक कार्यबल पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विश्व के जिन देशों ने श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण करने के साथ-साथ कार्यबल के विकास पर ध्यान दिया है, वे विकास के पथ पर तीव्र गति के साथ अग्रसर हैं। भारत में लगभग 1.3 अरब की आबादी में लगभग 70 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं और 54 फीसदी लोग किसान या मजदूर के रूप में काम करते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है, जिससे लोग विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग कर जीवन को बेहतर बना पाएंगे। भारत में जितने बाल मजदूर हैं, उतने ही बेरोजगारों की भी संख्या है। यदि कानूनों को कठोरता के साथ लागू किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या स्वत: समाप्त हो जाएगी क्योंकि बाल मजदूरों के हटने से बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। अंत में

बचपन बचाएं, देश बचाएं।

– खुशबू कुमारी
हाजीपुर वैशाली, बिहार

उपयोगी व ज्ञानवर्द्धक

श्रमिक कल्याण पर आधारित अप्रैल, 2017 का अंक पढ़ा। यह अंक ज्ञान में वृद्धि करने वाला और श्रमिक समस्या की ओर ध्यान दिलाने वाला रहा। कोई भी देश विकास के पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है अथवा विकसित बन सकता है, जब उस देश का बचपन सुरक्षित हो। यहां बात बाल श्रम की हो रही है, जो भारत के लिए एक शर्मनाक सच्चाई है। वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने इस पत्रिका में प्रकाशित अपने आलेख में बाल श्रमिकों

की संख्या लगभग 5 करोड़ बतायी है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत सरकार ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए वर्ष 1986 में बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम पारित कर 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूर के रूप में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया था। वर्ष 2016 में इस कानून में संशोधन कर बाल श्रम से संबंधित अनेक प्रावधान किये गये हैं। प्रथम, बाल श्रम के लिए प्रतिबंधित खतरनाक उद्योगों की संख्या 8 से घटाकर 3 कर दी गयी है। दूसरा, बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में कार्य करने की अनुमति दी गयी है। तीसरा, बच्चे के माता-पिता के अलावा चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी आदि सभी बच्चे के रिश्तेदार ही माने जाएंगे।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़े गये इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विधि बनाए गा। भाग 4 का अनुच्छेद 45 भी शिक्षा का उपबंध करता है। स्पष्टत: भारतीय संविधान ने बालकों को व्यापक सुरक्षा प्रदान किया है। बाल श्रम को रोकने के लिए कानूनों व संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन बेहतर रूप में करना होगा। साथ ही शिक्षा पर ध्यान देने के साथ-साथ बाल श्रम के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। हम तभी *न्यू इंडिया* का सपना साकार कर पाएंगे, जब बचपन को सुरक्षित कर पाएंगे।

– अमित कुमार गुप्ता, रामपुर, नौसहन, हाजीपुर, वैशाली, बिहार

जीवन मूल्य प्रबंधन में उपयोगी

आपकी गुणवत्तापूर्ण पत्रिका का नियमित पाठक हूं एवं जीवन संध्या में भी मुझे आपकी पत्रिका से प्राप्त नवीनतम जानकारी शिक्षण संस्थानों में बच्चों से समक्ष करियर जीवन मूल्य प्रबंधन पर वार्ता देते समय उपयोगी होती है। कृतज्ञ हूं संपादन परिवार के सदस्यों का। पढ़ने, मनने के बाद पत्रिका किसी स्कूल के पुस्तकालय में सदुपयोग हेतु भेंट कर देता हूं।

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर शिक्षण संस्थानों में ग्रीष्मावकाश रहता है। इसलिए आपकी पत्रिका के माध्यम से इस पत्र द्वारा पाठकों, विशेषरूप से बाल पाठकों से अनुरोध प्रार्थना कर रहा हूं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु घर में ही एक पौधा लगाएं। बिजली, पानी, ऊर्जा, पेट्रोल, खाद्यान्न का दुरुपयोग नहीं करें। पिछले वर्ष की नोट बुक्स से बचे खाली पन्ने अलग कर अगले सत्र हेतु रफ वर्क के लिए नोट बुक्स बनाकर कागज एवं पेड़ बचाएं, कचरा निश्चित स्थान पर ही फेंके एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु मम्मी-पापा के सुझावों का पालन करें।

– दिलीप भाटिया,
रावतभाटा, राजस्थान

प्रभावशाली प्रस्तुति

बदलते भारत पर आधारित योजना का मई 2017 का अंक पढ़ा, जो ज्ञानपयोगी एवं सरल था। सरकार के कार्ययोजना एवं प्रतिबद्धता का सटीक विवरण था। भारत के विकास गाथा एवं उपलब्धियों के बारे में मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया गया जिसे सरलता से समझा जा सकता है।

सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एवं उसके लाभ, नोटबंदी के उद्देश्य तथा नगदरहित अर्थव्यवस्था अपनाने से होने वाली पारदर्शिता का तार्किक विश्लेषण किये गये। ग्रामीण विकास, महिला एवं अल्पसंख्यकों के लिये सरकारी स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की वास्तविकता योजना के आलेखों में लेखकों के द्वारा प्रभावशाली ढंग से किया गया जो स्वागतयोगय है।

आज *योजना* पत्रिका हर महीने नवीन मुद्दे पर तथ्यपरक ज्ञान प्रदान करके ग्रामीण भारत में सामाजिक जागरूकता एवं नवचेतना फैला रही है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार को मजबूत कर रही है।

– प्रकाश कुमार
बिठौली, बहेरी, दरभंगा

सुंदर प्रस्तुति

योजना के मई, 2017 अंक के संपादकीय आलेख में 'भारत की विकास गाथा' प्रस्तुत की गयी। एम. वैंकेया नायडू केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 'समसामयिकी' मुद्दा है। सशक्त डिजिटल माज बनता भारत, कौशल विकास नवाचार युवा-सशक्तीकरण 'विकास योजनाओं के केन्द्र में महिलाएं' सशक्त बनने की ओर अग्रसर हैं।

'मानव विकास के पथ पर भारत' हमेशा विकास की ओर अग्रसर है, अग्रसर रहेगा। कुल मिलाकर यह अंक बहुत अच्छा लगा।

– देवेश त्रिपाठी
शिक्षा संकाय दी.द.उ.,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

योजना
आगामी अंक

जुलाई 2017

सामाजिक सुरक्षा

आपकी राय व सुझावों की प्रतीक्षा है...

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

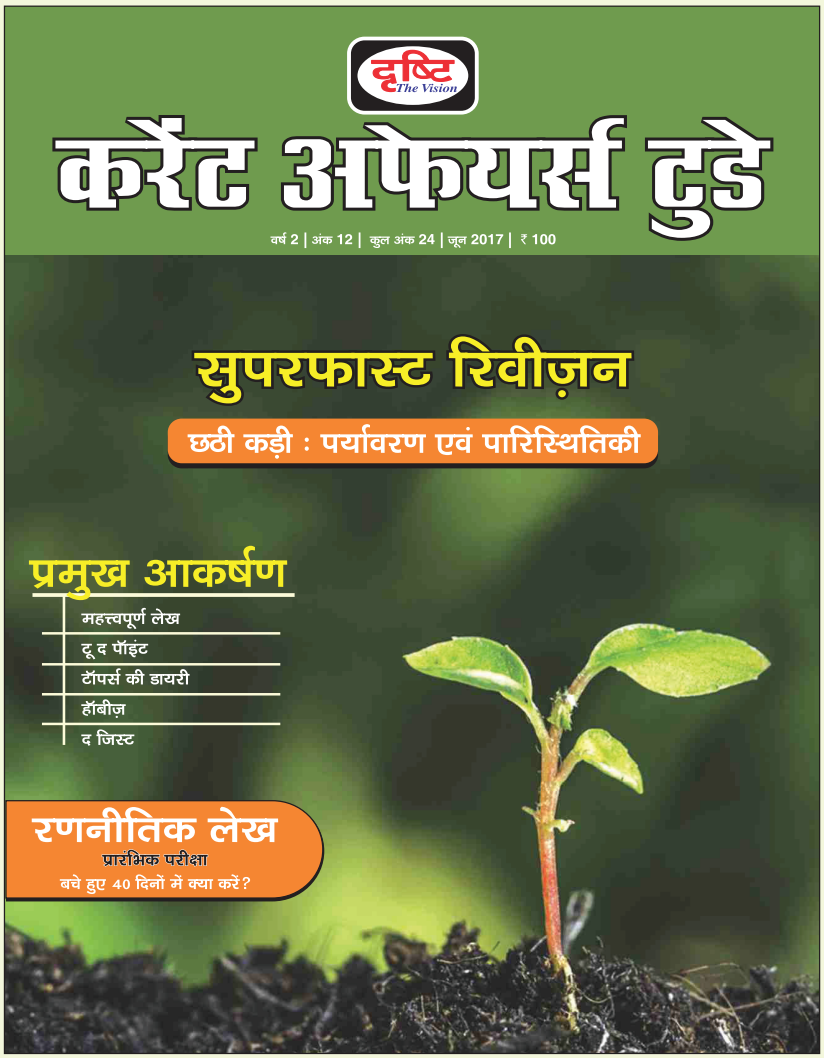

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिन्दू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 59
For business/advertising enquiry, Call - 8130392355
Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

संपादकीय

युवा: भविष्य की आस

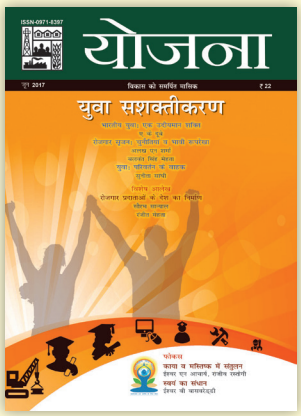

किसी भी राष्ट्र के युवा उसकी संपन्नता के रखवाले होते हैं। विकसित दुनिया के अधिकतर देश बूढ़ी होती जनसंख्या वाले राष्ट्र बनते जा रहे हैं, लेकिन भारत 2020 तक दुनिया का सबसे युवा देश बनने जा रहा है। भारत की आबादी में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली यह युवा शक्ति सबसे जीवंत और गतिशील वर्ग तो है, हमारे देश का सबसे कीमती मानव संसाधन भी है। दुनियाभर के अर्थशास्त्री और नीति निर्माता भारत के जनांकिकीय लाभांश की बात करते आ रहे हैं। देश के भविष्य के रूप में युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अद्भुत भूमिका निभानी है। उनका रचनात्मक सामर्थ्य, उत्साह, ऊर्जा और बहुमुखी प्रतिभा किसी भी देश के लिए आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है।

इंजीनियर, चिकित्सक, वकील, बैंकर, उद्यमी, खिलाड़ी के रूप में युवाओं के भीतर सभी क्षेत्रों में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्हें सही दिशानिर्देश और संसाधन प्रदान कर सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि वे वृद्धि कर सकें और देश के विकास में योगदान कर सकें। बच्चे को स्वस्थ विकास एवं अच्छी शिक्षा वाला अनुकूल घरेलू वातावरण प्रदान करना इस दिशा में पहला कदम है। *शिक्षा का अधिकार* अधिनियम 2009 इसे सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक क्षण है। *सर्व शिक्षा अभियान, ई-पाठशाला, उड़ान* आदि सभी स्तरों पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख सरकारी कार्यक्रम हैं। देश के पर्वतीय और सुदूरवर्ती क्षेत्रों, जहां अच्छी शिक्षा प्राप्त करना समस्या है, में दूरस्थ शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे युवाओं तक शिक्षा को पहुंचाने में दूरस्थ शिक्षा के मूल्य को अब मान्यता दी जा रही है। *ज्ञान, स्वयं* एवं *राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय* जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान करने में प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है।

किंतु इस शिक्षित युवा को विशिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है। आज की प्रतिस्पर्द्धी एवं उच्च तकनीक वाली दुनिया में स्कूल अथवा कॉलेज की सामान्य शिक्षा संभवत: युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। इसलिए समुचित एवं पर्याप्त कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो इस शक्ति को तकनीकी कौशल वाले सबसे बड़े मानव संसाधन स्रोत में बदल सकेगी। सरकार द्वारा आरंभ किया गया *कौशल भारत अभियान* ऐसा ही एक कार्यक्रम है, जो युवाओं को रोजगार बाजार की मांग के अनुसार कौशल बढ़ाने में मददगार होगा। अभियान का लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रदान करना और उन्हें उनकी पसंद के कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए उनकी योग्यता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास करने वाले दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम भी आते हैं।

अंत में युवाओं को सशक्त करने का अर्थ उन्हें लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है। रोजगारविहीन युवाओं का देश अर्थव्यवस्था पर बोझ और समाज के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए पिछले कुछ समय में सरकार को जोर *स्टार्ट अप इंडिया* और *स्टैंड अप इंडिया* कार्यक्रमों के जरिए स्टार्ट अप को बढ़ावा देने पर रहा है। *मुद्रा, सेतु,* एवं (अटल इनोवेशन मिशन) कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनका उद्देश्य नवाचार एवं उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

युवा राष्ट्र निर्माण के स्तंभ हैं। उनके हाथों में भाग्य बदल देने की शक्ति होती है। अपना भाग्य बदलने के लिए प्रयत्नशील प्रत्येक देश के पास इस अद्भुत संसाधन की ऊर्जा एवं महत्वाकांक्षाओं का उपयोग करने के रास्ते और तरीके होने चाहिए। फैंकलिन रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, ''हम हमेशा अपने युवाओं का भविष्य निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम भविष्य के लिए अपने युवाओं का निर्माण कर सकते हैं।'' ❑

CHANAKYA IAS ACADEMY®

24 Years of Excellence, Extraordinary Results every year, more than 3000 selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

under the direction of Success Guru AK Mishra

IAS 2018

Upgraded Foundation Course™

A Complete solution for Prelims, Mains & Interview

- Special modules on administrative traits by Success Guru AK Mishra & retired civil servants
- Intensive Classes with online support
- Offline/ Online test series for Prelims & Mains
- Pattern proof teaching
- Experienced faculty
- Hostel assistance

Separate classes in Hindi & English medium

Batches Starting From

10th JUNE, 10th JULY , 10th AUGUST - 2017

Weekend Batches & Postal Guidance Also Available

To Reserve your seat - Call: 1800-274-5005 (Toll Free)

www.chanakyaiasacademy.com | enquiry@chanakyaiasacademy.com

HO/ South Delhi Centre: • 124, Satya Niketan, Opp. Venkateshwara College, Near Dhaula Kuan, Delhi-21, Ph: 011-64504615, 9971989980/ 81

North Delhi Centres: • Near Gate No.1, GTB Nagar Metro Station, 103 & 105, Kingsway Camp, Mall Road, Delhi-09, Ph: 9711494830

Also at

• 1596, Outram Line, Kingsway Camp, Delhi-09, Ph: 011-27607721, Ph: 9811671844/ 45

Our Centres:

Ahmedabad: 301, Sachet III, 3rd Floor, Mirambika School Road, Naranpura, Ahmedabad-380013, Ph: 7574824916
Chandigarh: S.C.O :- 47 - 48, Sector 8 C, Madhya Marg, Chandigarh -160009 Ph: 8288005466
Guwahati: Building No. 101, Maniram Dewan Road, Silpukhuri, Near SBI evening branch, Kamrup, Assam - 781003, Ph: 8811092481
Hazaribagh: 3rd Floor, Kaushaliya Plaza, Near Old Bus Stand, Hazaribagh (Jharkhand)-825301, Ph: 9771869233
Jammu: 47 C/C, Opposite Mini Market, Green Belt, Gandi Nagar, Jammu-180001, Ph: 9419108240
Jaipur: Felicity Tower,1st floor,Plot no- 1, Above Harley Davidson Showroom, Sahakar Marg, Jaipur-30201, Ph: 9680423137
Ranchi : 1st Floor, Sunrise Form, Near Debuka Nursing Home, Burdhwan Compound, Lalpur, Ranchi-834001, Ph: 9204950999, 9771463546
Rohtak: DS Plaza, Opp. Inderprasth Colony, Sonipat Road, Rohtak- 124001, Ph: 8930018881
Patna: 304, 3rd Floor, above Reliance Trends, Navyug Kamla Business park, East Boring Canal Road, Patna, Bihar 800001, Ph: 8252248158
Allahabad: 10B/1, Data Tower 1st Floor, Tashkand, Patrika Chauraha Allahabad-211001, Ph: 9721352333

चेतावनी

छात्रों/अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि कुछ असम्बद्ध संस्थाएं ऐसे टेडमार्क/टेडनेम का इस्तेमाल कर रही हैं जो चाणक्य आईएएस एकेडमी/चाणक्य एकेडमी (1993 से सक्सेस गुरु एके मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रोन्नत) के टेडमार्क/टेडनेम के समरूप/भ्रामक समान हैं। हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ये संस्थाएं हमसे सम्बद्ध नहीं हैं तथा ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गयी है। सभी छात्रों को नामांकन कराने के पूर्व ऐसी एकेडमी/अध्ययन केन्द्र/संस्थान की प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेनी चाहिए और अनुरोध किया जाता है कि समरूप/भ्रामक रूप से समान टेडमार्क/टेडनेम के तहत हो रही ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में 09650299662/3/4 पर फोन कर तथाinfo@chanakyaacademygroup.comपर ईमेल भेजकर हमें सूचित करें।

भारतीय युवा: उभरती ताकत

ए के दूबे

वर्तमान सरकार ने बहुमुखी कार्यक्रम आरंभ किये हैं, जिनमें युवाओं से प्रतिभागिता करने के लिए कहा गया है और उनके संपूर्ण सर्वांगीण विकास में सहायता की जा रही है। उदाहरण के लिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियां तैयार करने और युवाओं को उनसे जोड़ने का जिम्मा नेहरू युवा केंद्र संगठन को सौंपा गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वैच्छिक समाज सेवा के जरिये नैतिक बल तथा मानवीय व्यक्तित्व का विकास करती है

यूनेस्को की परिभाषा के अनुसार "युवावस्था वह समय है, जब बाल्यावस्था की निर्भरता वयस्कता के स्वावलंबन में बदल जाती है और समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी स्वाधीनता का बोध होता है। किसी निर्धारित आयु वर्ग की अपेक्षा युवावस्था अधिक गतिमान श्रेणी है।"

युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय (युवा मामलों के विभाग) की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन के किसी भी संस्थान के लिए युवा सर्वाधिक उत्साहजनक श्रेणी होते हैं। उनके जीवंत और गतिशील दृष्टिकोण के कारण भारत युवा देश बन गया है, जिसकी लगभग 65 प्रतिशत आबादी *35 से कम* के आयु वर्ग में आती है। इसलिए यह युवा देश कहलाता है। अनुमान है कि वर्ष 2020 तक भारतीय जनसंख्या की औसत आयु 28 वर्ष होगी, जबकि दक्षिण एशियाई देशों और चीन में आंकड़ा 38 वर्ष होगा। भारत की कुल आबादी में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग वालों की 27.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिससे भारत का जनांकिकीय खाका बहुत अनुकूल बन जाता है।

इस जनांकिकीय बढ़त का सार्थक लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि युवाओं को लाभप्रद एवं रचनात्मक परिणाम तैयार करने वाले दायरे में डाल दिया जाए। वैश्विक स्तर पर भारत की सहायता करने वाली संभावित ताकत के रूप में युवाओं को आवश्यक नीतिगत आधार तथा समर्थन देना होगा। युवा ऐसी प्रयोगशाला नहीं हैं, जहां सरकारी तंत्र के सह-उत्पादों का परीक्षण किया जा सके। बल्कि वे परिवर्तनशील हैं, जिनका प्रयोग समसामयिक प्रासंगिकता वाले कौशलों पर आधारित नये अवसर सृजित करने के लिए होना चाहिए।

माइकल ग्रीन *यूथ इज एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज* में कहते हैं, "युवाओं के सकारात्मक विकास की लगातार विस्तार लेती तथा प्रभावशाली गति को देखते हुए ताकतों तथा रुचियों पर हमारा ध्यान होना चाहिए, उन्हें कमियां दूर करने का साधन नहीं माना जाना चाहिए और समस्याओं पर केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय समस्याओं का समाधान करने वाला दृष्टिकोण होना चाहिए।"

विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं नागरिक आंदोलनों के साथ युवा सदैव गतिविधियों के केंद्र में रहे हैं। समलैंगिकों के एलजीबीटीक्यू आंदोलन से लेकर *महिलाओं के लिए समान अधिकार* तक और पर्यावरण संबंधी चिंता से लेकर मानवाधिकारों तक युवा सदैव ही सार्वजनिक जीवन के विविध क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों के केंद्र में रहे हैं तथा अक्सर वह कारगर दबाव समूह साबित हुए हैं। अपने व्यापक हित तथा चिंताएं दिखाने के लिए मीडिया के नये साधनों का लगातार तथा व्यापक उपयोग किया गया है ताकि सोशल मीडिया जनमत को सामने रखे, चर्चा करे और उसका प्रसार करे। मीडिया के नये साधन विचार के सृजन में ही मदद नहीं करते बल्कि विचारों के समन्वय और संचार में भी सहायक होते हैं और अंत में उसे जनता की व्यापक स्वीकार्यता दिलाते हैं। युवाओं को आर्थिक/सामाजिक रूप से सार्थक गतिविधियों के केंद्र में इसलिए होना

लेखक भारत सरकार के खेल एवं युवा मामले मंत्रालय में युवा कार्य विभाग के सचिव हैं। वह भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वह लोक प्रशासन, सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास आदि विषयों से संबंधित शोध पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे हैं। ईमेल: sesy-ya@nic.in

चाहिए क्योंकि उनके भीतर लगातार बदलते सामाजिक ढांचे के अनुकूल ढल जाने की नैसर्गिक क्षमता होती है।

आदर्श रूप से युवा दो पीढ़ियों के बीच सेतु का काम करते हैं। यदि इस आयु वर्ग को ठीक से समझाया जाए तो वह समझ सकता है कि अपनी वृद्धि तथा विकास को आसान बनाने के लिए उसे लचीला बनना पड़ेगा। वैचारिक जिद और पाश्चात्य संस्कृति की बेवकूफी भरी नकल जैसे अतिवाद से लंबे समय में राष्ट्र पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज युवा समझता है कि पूर्ण मुक्ति अथवा स्वायत्तता से ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं मिल सकता। यह काम इकाइयों को कसकर गूंथते हुए करना होगा ताकि एक कारगर इकाई तैयार हो सके। युवा मूलत: नवीन सामाजिक विचार, आर्थिक विकास एवं राजनीतिक गतिविधियों के उत्प्रेरक हैं।

आज युवा ऐसी स्थिति में हैं, जहां वह सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्राप्त कर सकते हैं तथा विचारों की परीक्षा ले सकते हैं। सार्थक उद्देश्य के लिए, विशेषकर भारतीय लोकतांत्रिक नमूने के भीतर बहिष्कार के चलन की बहुलता वाली पृष्ठभूमि के खिलाफ इसे सही अनुपात में मिला भी सकते हैं।

तर्क और बहस तथा जांच-पड़ताल की भावना ही दृढ़ सामाजिक व्यवस्था की दीवारों पर प्रहार करती है, जिसका इस्तेमाल युवा करते हैं। आज के युवा दूसरे समुदाय के साथ भोजन करने और दूसरे समुदाय में विवाह करने के मामले में उतने सख्त नहीं रह गये हैं जितने पहले थे। वे दूसरे मनुष्यों के जाति, वर्ग, नस्ल एवं लिंग को आधार बनाये बिना ही उनके साथ अपमानजनक तथा संवेदनहीन व्यवहार पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। हालांकि ऐसा व्यापक स्तर पर नहीं हो रहा है फिर भी सही दिशा में मजबूती के साथ छोटे कदम उठाये जा चुके हैं।

युवाओं को उनकी जड़ें तलाशने में मदद करने वाला एक सबसे अहम कारक है प्रौद्योगिकी का उपयोग और उस पर दिया जा रहा जोर। *नकदरहित अर्थव्यवस्था* तथा *डिजिटल इंडिया* जैसे कदमों और विचारों के साथ डिजिटलीकरण की वकालत करने के सरकार के प्रयासों को देखें तो अर्थव्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने के सभी प्रयासों में प्रौद्योगिकी प्रभावशाली विकल्प बनकर उभर रही है। जैसा कि हम जानते हैं और रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, प्रौद्योगिकी विकास का साधन है। प्रौद्योगिकी ने असंभव दिखने वाली उपलब्धियां हासिल करने में मानव की सहायता की है और हम रोजाना नयी उपलब्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। विकासशील देशों में विशेष तौर पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग जीवन को बेहतर बनाने में भी किया गया है।

भारत में डिजिटल वातावरण ने युवाओं को अधिक संगठित तरीके से विश्व के सामने खड़े होने की शक्ति प्रदान की है। इसके कारण संचार अधिक तेज हुआ है, सीखने की प्रक्रिया तेज हुई है और भौगोलिक रूप से बहुत दूर स्थित दो स्थान भी एक ही मंच पर जोड़े जा रहे हैं। यह समान सोच वाले विचारों के संग्रह जैसी है और संभावित समाधान एवं परिणाम लाती है। एक बटन दबाते ही हम विचार साझा कर सकते हैं, सलाह-मशविरा कर सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं और विचार तथा कार्य को स्पष्ट कर सकते हैं। हमें जो दिखता है, प्रौद्योगिकी उससे कहीं बढ़कर है। किसी भी छात्र के सामने अध्ययन सामग्री का भंडार लग सकता है और वह विशेषज्ञतायुक्त अध्ययन केंद्रों वाले संस्थानों में आवेदन कर सकता है। प्रौद्योगिकी ने कम से कम उपलब्धता के मामलों में समान अवसर उत्पन्न किये हैं और इसका श्रेय एक बार फिर युवाओं को जाता है क्योंकि वे प्रौद्योगिकी के नये विकल्पों को सीखने और अपनाने में सबसे आगे रहे हैं।

भारत में डिजिटल वातावरण ने युवाओं को अधिक संगठित तरीके से विश्व के सामने खड़े होने की शक्ति प्रदान की है। इसके कारण संचार अधिक तेज हुआ है, सीखने की प्रक्रिया तेज हुई है और भौगोलिक रूप से बहुत दूर स्थित दो स्थान भी एक ही मंच पर जोड़े जा रहे हैं। यह समान सोच वाले विचारों के संग्रह जैसी है और संभावित समाधान एवं परिणाम लाती है।

जोखिम उठाने की भावना और स्टार्ट अप के उदय को युवाओं तथा प्रौद्योगिकी के गठबंधन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। कौशल को निखारने वाले और अधिक लक्षित एवं विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ स्टार्ट अप ने विशिष्ट वर्ग के मुट्ठीभर लोगों का उद्यम आरंभ करने और सेवा प्रदान करने का एकाधिकार खत्म कर दिया है। युवाओं के साहस ने प्रौद्योगिकी का साथ पाकर उद्यमशीलता को सभी के लिए सहजता से उपलब्ध करा दिया है।

सरकार ने युवा मामले तथा खेल मंत्रालय के जरिये भारतीय युवाओं की आवश्यक एवं लाभप्रद वृद्धि के लिए विकास एवं प्रगति के पहलुओं पर लगातार नजर रखी है। नियमित समीक्षाओं के साथ ही उसने युवाओं से जुड़े मसलों पर नयी योजनाएं/कार्यक्रम और कार्यशालाएं भी आरंभ की हैं और नियमित जीवनशैली/नेतृत्व से जुड़े कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रस्ताव तैयार किये हैं।

2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, "राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 भारत के युवाओं के सर्वांगीण विकास के प्रति संपूर्ण राष्ट्र के संकल्प को दोहराता है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से परिचित हो सकें और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उत्पादकता भरा योगदान कर सकें। राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 भारत के युवाओं के लिए सर्वांगीण दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है, जो देश के युवाओं को उनकी पूरी क्षमता प्राप्त करने योग्य शक्ति दे और उनके जरिये भारत को राष्ट्र समुदाय में अपना सही स्थान प्राप्त करने योग्य बनाए।"

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के अंतर्गत उद्देश्य तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

(1) उत्पादक कार्यबल तैयार करना, जो भारत के आर्थिक विकास में सत्त योगदान कर सके।

इसके लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:

- शिक्षा
- उद्यमशीलता
- रोजगार एवं कौशल विकास

(2) भावी पीढ़ियों को संभालने के लिए योग्य, मजबूत, स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना। यह कार्य करने के साधन होंगे:

- स्वास्थ्य - स्वस्थ जीवनशैली
- खेल

(3) तर्कशीलता उत्पन्न करने के लिए

सामाजिक मूल्य सिखाना तथा सामुदायिक सेवाओं को बढ़ावा देना। इसके लिए अधिकार संबंधी तथा कामकाजी साधन इस प्रकार हैं:

- सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहन
- सामुदायिक कार्य

(4) प्रशासन के सभी केंद्रों पर प्रतिभागिता एवं नागरिक कार्यों में सहायता करना। इसके लिए जरूरी है:

- राजनीति एवं प्रशासन में प्रतिभागिता
- युवाओं की सहभागिता

(5) जोखिम में पड़े युवाओं की सहायता करें तथा वंचित एवं हाशिये पर पड़े युवाओं के लिए न्यायोचित अवसर सृजित करें। समावेश एवं सामाजिक न्याय इसके लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

वर्तमान सरकार ने बहुमुखी कार्यक्रम आरंभ किये हैं, जिनमें युवाओं से प्रतिभागिता करने के लिए कहा गया है और उनके संपूर्ण सर्वांगीण विकास में सहायता की जा रही है। उदाहरण के लिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियां तैयार करने और युवाओं को उनसे जोड़ने का जिम्मा नेहरू युवा केंद्र संगठन को सौंपा गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनयेसएस) स्वैच्छिक समाज सेवा के जरिये नैतिक बल तथा मानवीय व्यक्तित्व का विकास करती है।

'राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम' भी है। इसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए *राष्ट्रीय युवा महोत्सव* एवं पुरस्कार भी हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 41 प्रतिशत भारतीय जनता की आयु 20 वर्ष से कम है। व्यक्तित्व विकास के मामले में यह आयु वर्ग सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें सही दिशानिर्देश, संरचना एवं निर्देशों की बहुत आवश्यकता होती है। खेद की बात है कि आज के युवा तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दुष्प्रभाव झेल रहे हैं और रोजी-रोटी तक के लिए अपराधों की तरफ बढ़ रहे हैं। सुविधा एवं सुलभता के बीच की खाई ही इस नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रमुख कारण है। सरकार के कार्यक्रम एवं योजनाएं बेशक होंगी, लेकिन उन्हें प्राप्त करने की पद्धति अथवा साधन आसान नहीं रहे हैं। *वित्तीय बाधाएं* अथवा *सामाजिक ढांचा* इन सुविधाओं को प्राप्त करने की राह में प्रमुख रोड़े हैं। युवाओं के संकटों तथा उनसे निपटने के तरीके की जानकारी नहीं होने का प्रमुख कारण भी यही है कि व्यापक शैक्षिक मंच पर इस समस्या के विषय में विचार नहीं किया गया है। शिक्षाविद *युवाओं की पहचान के बढ़ते संकट*, उनके सामर्थ्य तथा आवश्यक योगदान के संबंध में पूरी तरह संवेदनशील नहीं रहे हैं और उसे स्वीकार भी नहीं करते रहे हैं, जबकि शिक्षा देने में बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने भर से इसके बहुत से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। युवा मानस के काम करने के तरीके को पहचानने, स्वीकार करने तथा सराहना करने की त्वरित आवश्यकता है। उसे यह मान्यता उस सख्त एवं अड़ियल मानसिकता से नहीं देनी चाहिए, जो युवाओं से तमाम अपेक्षाएं रखती है। उसके बजाय संवाद एवं अन्य तरीकों से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले परिवर्तनों पर ध्यान रहना चाहिए। व्यापक सराहना प्राप्त करने वाले एनयेसएस के अलावा नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंतर्गत अधिक विशेषज्ञता वाले कार्यक्रम भी हैं, जो इन समस्याओं के कई समाधान देने का प्रयास करते हैं।

जोखिम उठाने की भावना और स्टार्ट अप के उदय को युवाओं तथा प्रौद्योगिकी के गठबंधन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। कौशल को निखारने वाले और अधिक लक्षित एवं विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ स्टार्ट अप ने विशिष्ट वर्ग के मुट्ठी भर लोगों का उद्यम आरंभ करने और सेवा प्रदान करने का एकाधिकार खत्म कर दिया है। युवाओं के साहस ने प्रौद्योगिकी का साथ पाकर उद्यमशीलता को सभी के लिए सहजता से उपलब्ध करा दिया है।

मंत्रालय की 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के सफल क्रियान्वयन के लिए उसके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ ही कुछ सुझावों की भी सूची है। उनमें से कुछ सुझाव हैं:

- शिक्षा में संस्थागत क्षमता एवं गुणवत्ता का सृजन करना।
- युवाओं तक पहुंच एवं जागरुकता का लक्ष्य रखना, रोजगार एवं कौशल विकास में प्रणालियों तथा हितधारकों के बीच संपर्क तैयार करना।
- उद्यमशीलता के अनुकूल कार्यक्रम तैयार करना।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा आपूर्ति सुधारना।

अब नेहरू युवा संगठन केंद्र का लक्ष्य अधिक सर्वांगीण एवं समग्र विकास प्रदान करना है क्योंकि अब वह वर्गीकृत दृष्टिकोण के बजाय बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है।

सरकार की युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहल नीचे दी गयी हैं:-

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

इसका लक्ष्य प्रशिक्षित शिक्षकों के जरिये व्यावसायिक प्रशिक्षण का कौशल विकसित करना है ताकि अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिले और आत्मविश्वास भी बढ़े। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं को पहचानना और उसी के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

लोक कला, संस्कृति एवं युवा कृति का संवर्द्धन

पश्चिम के प्रति नयी पीढ़ी की आसक्ति देखते हुए इस कार्यक्रम की बहुत आवश्यकता है, जो ग्रामीण युवाओं को उनकी संस्कृति तथा प्रतिभा दिखाने एवं बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

महात्मा गांधी युवा स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम

युवाओं को स्वच्छता अभियान एवं जल संरक्षण के प्रति सतर्क करता है और योगदान करने के लिए साथ जोड़ता है। देशभर में फैली विषमता और प्रतिभागिता में कमी के बीच कुछ समावेशी कार्यक्रमों से सरकार की सद्भावना दिखी है और यह भी दिखा है कि सामाजिक समावेश तथा समावेशी वृद्धि की नीतियों पर वह कितना जोर दे रही है।

किशोरों के सशक्तीकरण हेतु जीवनोपयोगी कौशल प्रशिक्षण

यह महत्वपूर्ण और प्रमुख पहल है क्योंकि यह युवाओं में आजकल सामान्य हो चुके मनोवैज्ञानिक विपथन की ओर ध्यान आकर्षित कराती है और युवाओं को इस तरह प्रशिक्षण देती है कि वे दबाव से निपटने और स्वास्थ्यप्रद जीवनशैली चुनने योग्य बनें। इस योजना का उद्देश्य किशोरों को प्रजनन-यौन स्वास्थ्य, उससे जुड़ी समस्याओं और चिंताओं के विषय में बताना और जागरूक बनाना भी

है। समस्या के समाधान की उनकी क्षमता को एक स्थान पर लाकर सहमति तैयार करना भी इसका लक्ष्य है।

भौगोलिक एवं सामाजिक अवरोध दूर करना

इस दिशा में निम्नलिखित दो कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जा सकता है:

आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी): इसका लक्ष्य वाम उग्रवाद से प्रभावित आदिवासी पट्टी से संभावनाशील युवाओं को चुनना तथा उन्हें देश के दूसरे भागों की यात्रा कराना है। इससे उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रभावी विचारधारा के प्रभाव के बगैर ही अपने मानस का विकास करने और उसे राष्ट्रीय भावना में ढालने का अवसर मिलता है। टीवाईईपी उन्हें अपने अनुभवों को अपने-अपने आदिवासी गृहनगरों में आजमाने का अवसर भी प्रदान करती है क्योंकि वे विकास, बुनियादी ढांचागत वृद्धि और कौशल विकास के जादू को पहले ही देख चुके हैं।

पूर्वोत्तर युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम: युवा मामलों के मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से नेहरू युवा केंद्र संगठन के तहत पूर्वोत्तर के युवाओं का मेल-जोल महाराष्ट्र के युवाओं से कराने का लक्ष्य है ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक रूप से अलग-अलग जीवनशैलियों की प्रकृति को समझा जा सके।

2012 के अधिनियम को लागू कर *राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान* की स्थापना की गयी। इसका लक्ष्य स्वयं को *युवा विकास के क्षेत्र में शैक्षिक उत्कृष्टता के वैश्विक मान्यता प्राप्त एवं सम्मानित संस्थान* के रूप में स्थापित करना है।

इसमें विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें परामर्श मनोविज्ञान में एमएससी, सामाजिक नवाचार एवं उद्यमशीलता में एमए, जेंडर स्टडीज में एमए, विकास नीति एवं व्यवहार में एमए जैसे स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम शामिल हैं। यह युवाओं से संबंधित विषयों में डॉक्टरल उपाधि अर्जित करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

आर्थिक रूप से व्यावहारिक, सामाजिक रूप से विश्वसनीय एवं सुगमता से उपलब्ध कराए जाने के विचार के साथ सरकार ने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि वाले शहरों - शहरों के केंद्र तथा पर्यटन स्थलों - में विभिन्न यूथ हॉस्टल खोले हैं, जिनमें पूरे समय बिजली और पानी की आपूर्ति होती है। इनका लक्ष्य रहने की सुगम सुविधा उपलब्ध कराते हुए देशभर में विविधता भरी संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव कराना तथा संवाद का अवसर प्रदान करना है।

सरकार ने प्रत्येक युवा की क्षमता तथा सामर्थ्य को पूरी तरह निखारने के लिए विभिन्न तरीकों से हरसंभव प्रयास किये हैं, जिनसे न केवल व्यक्तित्व विकास में मदद मिलती है बल्कि उभरते हुए राष्ट्रीय विश्वव्यापी प्रभावी स्वर को भी मजबूती मिलती है। बदलते हुए युवा अधिक संवेदनशील, चैतन्य और सौहार्दपूर्ण विश्व के पथप्रदर्शक बन जाएंगे। युवाओं तथा उनके अदम्य उत्साह का महत्व बताने के लिए स्वामी विवेकानंद के शब्द एकदम सटीक हैं - "उठो! जगो! और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको।" ❑

संदर्भ

- 2011 की जनगणना रिपोर्ट
- भारत 2017, प्रकाशन विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
- वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

भारत में युवाओं के लिए रोजगार सृजन की चुनौतियां

अलख एन शर्मा
बलवंत सिंह मेहता

एक तरफ विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में महिलाओं की भागीदारी दर बहुत कम है, दूसरी ओर युवतियों में बेरोजगारी की दर भी बहुत अधिक हैं। ऐसे में सरकार ने वांछित दिशा में पहल की है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वृहद और अन्य आर्थिक नीतियों में रोजगार सृजन को महत्व दिया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं किया है। रोजगार सृजन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को अपने सभी कार्यक्रमों और नीतियों में नौकरी सृजन करने को महत्व देना चाहिए

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है जो विश्व की कुल युवा जनसंख्या का पांचवां हिस्सा है। श्रम बाजार में सही ढंग से समायोजित होने पर भारतीय युवा उच्च आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। भारत की जनसंख्या का आधे से ज्यादा हिस्सा (60.3 प्रतिशत) 15-59 वर्ष के श्रमशील आयु वर्ग और एक चौथाई हिस्सा (27.5 प्रतिशत) 15-29 वर्ष की युवा श्रेणी के भीतर आता है (भारत की जनगणना, 2011)। वर्ष 2001 और 2011 के बीच भारत में युवा जनसंख्या आबादी की समूची दर (1.6 प्रतिशत) की तुलना में सालाना 2 प्रतिशत की उच्च दर से बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप हर वर्ष भारत के लगभग 1 करोड़ युवा श्रम बाजार का हिस्सा बनते हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में युवाओं की बड़ी संख्या है जिनमें से बहुत से उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के पिछड़े राज्यों से आते हैं। हालांकि, प्रत्येक वर्ष श्रम बाजार में सृजित होने वाली नौकरियां युवाओं की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कई रोजगार सृजन योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि *प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरआई), मेक इन इंडिया* और *स्किल इंडिया*। यह लेख देश में युवा रोजगार की चुनौती को स्पष्ट करता है और सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों की समीक्षा करता है। इसमें इस्तेमाल किये गये आंकड़े भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा पांचवें वार्षिक रोजगार सर्वेक्षण, 2015-16 से उद्धृत हैं। हालांकि, आमतौर पर युवा जनसंख्या में 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं, इस लेख में हम 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों पर विचार करेंगे। इसका कारण यह है कि 15-17 वर्ष के आयु वर्ग के सिर्फ कुछ ही लोग श्रम बाजार में स्वयं को दर्ज कराते हैं। इस प्रकार 18-29 वर्ष के युवा ही बड़े पैमाने पर रोजगार की चुनौती का सामना करते हैं।

तालिका 1: आयु समूह के अनुसार श्रम भागीदारी दर (यूपीएस), 2015-16

क्षेत्र	15-17 वर्ष			18-29 वर्ष			30+ वर्ष		
	पु	म	व्य	पु	म	व्य	पु	म	व्य
ग्रामीण	11.1	4.3	8.0	63.1	19.1	42.3	89.0	29.8	60.1
शहरी	4.0	1.4	2.8	48.6	11.8	30.7	82.6	16.7	50.4
कुल	9.3	3.6	6.7	59.3	17.1	39.2	87.1	26.0	57.3

यूपीएस- यूजवल प्रिंसिपल स्टेटस, पु- पुरुष, म- महिला, व्य- व्यक्ति

स्रोत: श्रम ब्यूरो, युवा रोजगार एवं बेरोजगारी के परिदृश्य पर रिपोर्ट, खंड II, 2015-16, भारत सरकार

अलख एन शर्मा नयी दिल्ली स्थित मानव विकास संस्थान में बतौर निदेशक और प्रोफेसर कार्यरत हैं। ये श्रम और विकास प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इन क्षेत्रों में बहुत सी किताबों और शोधपत्र का लेखन और संपादन किया है। इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (आईजेएलई) के संपादक भी हैं। ईमेल: alakh.sharma@indindia.org

बलवंत सिंह मेहता नयी दिल्ली स्थित मानव विकास संस्थान में फेलो और पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं। इन्होंने मानव विकास के विभिन्न मुद्दों रोजगार, गरीबी, असमानता, बाल आरोग्य और विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्य किया है। इनकी 3 पुस्तकें और 30 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में इनके शोध को मान्यता दी है। ईमेल: balwant.mehta@indindia.org

तालिका 2: विभिन्न आयु वर्गों में गतिविधिवार श्रमिकों का वितरण, 2015-16

	15-17 वर्ष			18-29 वर्ष			30 वर्ष और अधिक		
	ग्रा	श	ग्रा+श	ग्रा	श	ग्रा+श	ग्रा	श	ग्रा+श
स्वरोजगार प्राप्त	40.8	30.9	39.7	40.5	33.3	39.0	51.2	43.4	49.2
वैतनिक कर्मचारी	5.1	18.9	6.5	14.1	37.6	19.0	10.5	33.8	16.5
अनुबंध पर श्रमिक	3.6	7.7	4.0	4.6	8.4	5.4	2.4	4.9	3.0
आकस्मिक श्रमिक	50.6	42.6	49.7	40.8	20.7	36.6	35.9	17.9	31.0
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

ग्रा-ग्रामीण, श-शहरी

स्रोत: श्रम ब्यूरो, युवा रोजगार एवं बेरोजगारी के परिदृश्य पर रिपोर्ट, खंड II, 2015-16, भारत सरकार

श्रमिकों की भागीदारी दर

श्रमिक भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) श्रमिकों/कर्मचारियों की कुल आबादी के अनुपात को दर्शाती है। 2015-16 में युवाओं के लिए डब्ल्यूपीआर 39.2 थी, जो 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 57.3 थी (तालिका 1)। संभव है कि 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाई कर रही हो। तालिका 1 से भी प्रदर्शित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूपीआर शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त 18-29 वर्ष के आयु वर्ग वाली युवतियों की तुलना में युवकों का डब्ल्यूपीआर करीब 3.5 गुना अधिक है।

18-29 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों में लगभग 2/5 व्यक्ति स्वरोजगार कर रहे थे, जबकि 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों में ऐसा करने वाले लगभग आधे थे। तालिका 2 से अनुमान भी लगाया जा सकता है कि अधिक से अधिक युवा श्रम बाजार में नियमित और आकस्मिक कर्मचारियों के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में दिखाई देती है।

औद्योगिक वितरण

श्रमिकों के औद्योगिक वितरण से पता चलता है कि 18-29 वर्ष की आयु वर्ग के अधिकांश व्यक्ति (38.1 प्रतिशत) कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद व्यापार, होटल और रेस्तरां (19.4 प्रतिशत), निर्माण (15.1 प्रतिशत), मैन्यूफैक्चरिंग (13.1 प्रतिशत) और अन्य सेवाएं आती हैं। 30 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों की तुलना में 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे कि निर्माण, मैन्यूफैक्चरिंग और व्यापार एवं संबंधित गतिविधियों में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इस परिवर्तन का एक बड़ा कारण यह है कि कृषि क्षेत्र अधिक श्रमिकों को समाहित करने में सक्षम नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि यह क्षेत्र उन युवाओं को अधिक फायदेमंद नहीं लगता, जो बेहतर शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं।

बेरोजगारी दर

बेरोजगारी की दर उन लोगों का अनुपात होती है जो काम के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा और वे अब भी काम की तलाश कर रहे हैं। 2015-16 के दौरान 18-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की बेरोजगारी दर 13.2 प्रतिशत थी, (तालिका 3) जोकि 30 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों की बेरोजगारी दर से 8 गुना अधिक थी (1.6 प्रतिशत)। इनमें युवतियों की बेरोजगारी दर 20 प्रतिशत थी, जो युवकों की तुलना में (11.3 प्रतिशत) लगभग दोगुनी है। ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों में और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बेरोजगारी दर अधिक है। शहरी इलाकों में युवतियों की बेरोजगारी दर 28 प्रतिशत के साथ बहुत अधिक उच्च है (शहरी इलाकों में युवकों में बेरोजगारी दर 11.5 प्रतिशत थी)। यहां इस बात की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि 15-17 वर्षों के आयु वर्ग के कुछ ही लोग रोजगार करना चाहते हैं, इस आयु वर्ग के लिए लोगों की बेरोजगारी दर 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के समान ही उच्च है। चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों में हों, या शहरी क्षेत्रों में या वे महिला हों अथवा पुरुष।

शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी और बढ़ रही है। शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ युवाओं में बेरोजगारी भी बढ़ रही है (तालिका 4)। स्नातक से नीचे के स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स या स्नातक स्तर के डिप्लोमा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी 23 प्रतिशत है, जबकि स्नातक होने वाले युवाओं में बेरोजगारी की दर लगभग 35 प्रतिशत है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि शिक्षित युवतियों को शिक्षित युवकों की तुलना अधिक बेरोजगारी झेलनी पड़ती है।

18-29 वर्ष के आयु वर्ग की एक-तिहाई शिक्षित युवतियां, जिन्होंने स्नातक स्तर से नीचे सर्टिफिकेट कोर्स या स्नातकोत्तर स्तर की डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है, बेरोजगार हैं। स्नातक और उससे अधिक की शिक्षा प्राप्त करने वाली युवतियों में तो बेरोजगारी दर लगभग 48 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय श्रम बाजार न केवल पर्याप्त नौकरियों का सृजन नहीं कर पा रहा, बल्कि श्रम बाजार में प्रवेश और भर्ती प्रक्रियाओं में

तालिका 3 : विभिन्न आयु वर्गों में गतिविधिवार श्रमिकों का वितरण, 2015-16

उद्योग	15-17 वर्ष	18-29 वर्ष	30+ वर्ष
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	53.4	38.1	47.2
खनन और उत्खनन	1.9	0.9	1.1
मैन्यूफैक्चरिंग	14.5	13.2	9.6
बिजली, गैस और जल आपूर्ति	0.2	0.6	0.6
निर्माण	14.8	15.1	10.0
व्यापार, होटल और रेस्तरां	12.2	19.4	17.5
परिवहन, भंडारण और संचार	1.1	3.7	3.9
वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, और व्यापार सेवाएं	1.4	8.3	9.2
सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	0.6	0.7	0.8
कुल	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत: युवा रोजगार एवं बेरोजगारी के परिदृश्य पर रिपोर्ट, अंक-II, 2015-16

तालिका 4 : विभिन्न आयु वर्गों में बेरोजगारी दर (यूपीएस), 2015-16

क्षेत्र	15-17 वर्ष			18-29 वर्ष			30+ वर्ष से अधिक		
	पु	म	व्य	पु	म	व्य	पु	म	व्य
ग्रामीण	18.4	22.8	19.5	11.2	17.9	12.7	0.9	3.7	1.6
शहरी	22.1	21.4	22.0	11.5	27.9	15.1	0.7	5.3	1.5
कुल	**18.8**	**22.7**	**19.8**	**11.3**	**20.0**	**13.2**	**0.9**	**4.0**	**1.6**

यूपीएस- यूजअल प्रिंसिपल स्टेटस, पु- पुरुष, म- महिला, व्य- व्यक्ति

स्रोतः श्रम ब्यूरो, युवा रोजगार एवं बेरोजगारी के परिदृश्य पर रिपोर्ट, खंड II, 2015-16, भारत सरकार

उनके साथ अब भी भेदभाव किया जाता है। एक अतिरिक्त कारण यह हो सकता है कि महिलाओं के लिए उपयुक्त नौकरियों नहीं किया जा रहा है या उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे कि परिवहन, क्रेश सुविधाएं इत्यादि। इनसे महिलाओं के लिए नौकरियां कर पाना सुविधाजनक होता है। कुल मिलाकर, यह स्पष्ट है कि भारत अपनी युवा आबादी के लिए पर्याप्त नौकरियों का सृजन नहीं कर रहा है। शहरी युवतियों के मामले में तो यह विशेष रूप से चुनौती भरा मसला है।

सरकार की हालिया पहल

सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन इनके परिणाम बहुत संतोषजनक नहीं हैं। हाल के वर्षों में युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई नयी योजनाएं शुरू की गयी हैं, जैसे *स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम।* इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया

कर लाभ और 10,000 करोड़ रुपये के मेगा स्टार्ट अप जैसी सहायता प्रदान करके उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जनवरी 2016 में *स्टार्ट अप इंडिया* और *स्टैंड अप इंडिया* की शुरुआत की है। स्टार्ट अप्स के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए सरकार ने कई उपाय किये जैसे पंजीकरण के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना, कानूनी औपचारिकताएं और विनियामक नियंत्रण कम करना, कर रियायत देना, इत्यादि। इसका उद्देश्य यह था कि स्टार्ट अप्स के लिए काम करना आसान हो। दिसंबर, 2016 तक भारत में लगभग 4,700 स्टार्ट अप थे। हालांकि, इन योजनाओं का अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हुआ क्योंकि एक वर्ष के भीतर ही लगभग 200 से अधिक स्टार्ट अप बंद हो गये। हालांकि तर्क यह दिया जाता है कि यह स्वाभाविक प्रगति है और 20 प्रतिशत से अधिक स्टार्ट अप्स प्रतिस्पर्धी बाजार को झेल नहीं पाते, (भारत स्टार्ट अप आउटलुक रिपोर्ट, 2017)। (एट्रिशन रेट) कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जनवरी, 2016 में *स्टैंड अप इंडिया* योजना भी शुरू की गयी, जिसका उद्देश्य महिलाओं जैसे हाशिए पर पड़े समूहों में उद्यमिता को बढ़ावा देना था। दिसंबर 2016 तक, *स्टैंड अप इंडिया* स्कीम के अंतर्गत मंजूर किये गये ऋणों की कुल संख्या 15341 थी जिसमें 2055 महिलाएं, अनुसूचित जातियों के 2568 लोग तथा अनुसूचित जनजाति के 718 लोगों को दिया गया ऋण शामिल है (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 2017)।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

अप्रैल 2015 में सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत की, ताकि सूक्ष्म/लघु कारोबारी इकाइयों को संस्थागत वित्त प्रदान किया जा सके। पीएमएमवाई के तहत तीन प्रकार के ऋण स्वीकृत किये जा सकते हैं जो कारोबारी इकाई के वृद्धि/विकास और धन की जरूरतों को दर्शाते हैं - शिशु (50,000 रुपये), किशोर (50,000 से 5,00,000 रुपये), और तरुण (5,00,000 से 10,00,000 रुपये)। पीएमएमवाई कार्यक्रम के तहत वितरित किये गये ऋण की कुल राशि मार्च 2016 तक 1.25 खरब पहुंच गयी थी। 3 करोड़ 27 लाख ऋणकर्ताओं में 3 करोड़ 3 लाख शिशु वर्ग में आते हैं।

स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार *स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम* (एसवीईपी) शुरू करने की योजना बना रही है। एसवीईपी का उद्देश्य जमीनी स्तर यानि गांवों के स्तर पर टिकाऊ स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना और आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं सुगम बनाना है। उम्मीद की जा रही है कि एसवीईपी के अंतर्गत चार वर्षों, यानि 2015-19 के दौरान चार राज्यों के 125 ब्लॉकों में लगभग 1.82 लाख ग्राम उद्यमों का सृजन और सबलीकरण किया जाएगा। इससे 3.78 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। अगर इस कार्यक्रम को उचित प्रकार से कार्यान्वित किया जाए तो यह कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के लिए उद्यमशीलता के अवसरों को बेहतर बनाएगा।

निष्कर्ष

युवाओं की बढ़ती संख्या के साथ भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के एक

तालिका 5: शिक्षा के स्तर और आयु वर्ग पर आधारित बेरोजगारी दर (यूपीएस), 2015-16

वर्ग	18-29 वर्ष			30+ वर्ष		
	पु	म	व्य	पु	म	व्य
निरक्षर	4.0	6.2	4.9	0.6	3.0	2.2
अधूरी प्राथमिक शिक्षा	4.8	5.8	5.1	0.6	1.9	1.6
प्राथमिक शिक्षा	5.5	8.0	6.2	0.6	2.3	1.0
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	9.2	17.1	10.4	0.7	4.8	1.6
स्नातक से पूर्व सर्टिफिकेट कोर्स	21.3	31.3	23.5	0.6	11.2	2.4
स्नातक स्तर पर डिप्लोमा	20.9	33.1	23.0	1.0	7.6	1.4
स्नातक और अधिक	29.7	47.7	34.8	2.3	13.5	6.2
कुल	**11.3**	**20.0**	**13.2**	**0.9**	**4.0**	**1.6**

पु- पुरुष, म- महिला, व्य- व्यक्ति

स्रोतः श्रम ब्यूरो, युवा रोजगार एवं बेरोजगारी के परिदृश्य पर रिपोर्ट, अंक II, 2015-16, भारत सरकार

दौर से गुजर रहा है। युवाओं की संख्या बढ़ने का अर्थ है, अच्छी शिक्षा और इसके बाद अच्छी नौकरियां। जैसा कि विश्लेषण से स्पष्ट होता है, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, खासकर शिक्षित युवाओं के संदर्भ में। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में महिलाओं की भागीदारी दर बहुत कम है, दूसरी ओर युवतियों में बेरोजगारी की दर भी बहुत अधिक हैं। ऐसे में सरकार ने वांछित दिशा में पहल की है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वृहद और अन्य आर्थिक नीतियों में रोजगार सृजन को महत्व दिया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं किया है। रोजगार सृजन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को अपने सभी कार्यक्रमों और नीतियों में नौकरी सृजन करने को महत्व देना चाहिए।

यहां यह उल्लेख भी किया जाना चाहिए कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत की तुलना में मध्य और पूर्वी भारत का एक बड़ा हिस्सा वृद्धि और रोजगार सृजन करने में सफल नहीं हुआ है। ऐसी क्षेत्रीय असमानता को संतुलित किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को भी रोजगार मिले। देश को तेजी से विकास करना चाहिए ताकि बढ़ती आबादी का लाभ उठाया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाएगा। ❑

संदर्भ

- **इंडिया स्टार्ट अप आउटलुक रिपोर्ट, (2017):** इनोवेशन कैपिटल: इंडिया स्टार्ट अप आउटलुक रिपोर्ट, 2017, http://www.innovencapital.com/sites/default/files/
- **मानव विकास संस्थान (2014):** भारतीय श्रम और रोजगार रिपोर्ट 2014, दिल्ली
- **भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2016,** दिल्ली
- **श्रम ब्यूरो (2017):** युवा रोजगार एवं बेरोजगारी के परिदृश्य पर रिपोर्ट, अंक II, 2015-16, 10 मई, 2017 को http://labourbureau.nic.in/EUS_5th_Vol_2.pdf
- **वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (2017):** वर्षात समीक्षा, वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय, 12 मई 2017 को http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.asp.relid=156054
- **मित्रा, अरुप, वेरिक, शेर (2013):** युवा रोजगार और बेरोजगारी: भारतीय परिदृश्य, आईएलओ, एशिया प्रशांत, डीडब्ल्यूटी फॉर साउथ एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया, नयी दिल्ली, आईएलओ वर्किंग पेपर सीरीज
- **नैसकॉम और जिनोव (2016):** इंडियन स्टार्ट अप इको सिस्टम मैच्योरिंग नैसकॉम 2016, नयी दिल्ली, 12 मई 2017 को www.nasscom.in/download/summary_file/fid/135625

योजना हिंदी से जुड़ें अपडेट्स के लिए फेसबुक पर हमसे जुड़े।
हमारा पता है: wwww.facebook.com/yojanahindi

SARVODAYA IAS
सामान्य अध्ययन
भारतीय अर्थव्यवस्था
GS MAINS PAPER-III
by A.K. ARUN
Fee @9500 only
NEW BATCH STARTS
जुलाई प्रथम सप्ताह से
SPECIAL FOCUS ON
• Daily Answer Writing
• निश्चित समयावधि में कोर्स समापन
PH.: 8130953963

रोजगार प्रदाताओं के देश का निर्माण

सौरभ सान्याल
रंजीत मेहता

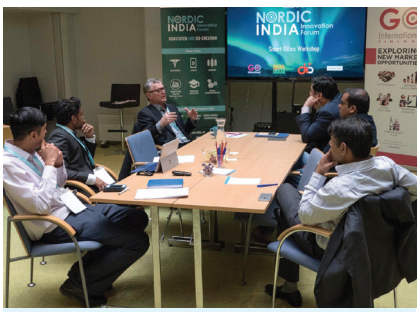

उद्यमिता या स्टार्ट अप्स देश में एक नयी तरह की घटना है। स्टार्ट अप शुरू करना मुश्किल काम है और हर देश को इसमें सफलता से ज्यादा विफलता मिलती है। एक उद्यमी को कड़ी मेहनत करने और असफलता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उद्यमिता उत्सव की पृष्ठभूमि में पनपती है। स्टार्ट अप की असफलता को भी सहज रूप से लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की असफलताएं एक नये उद्यमी को यह सिखाती हैं, कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं

भारत को एक साल में एक करोड़ नौकरियों की जरूरत है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि किसी भी देश में नयी नौकरियों की संभावनाएं बड़े-बड़े उद्योगों में नहीं, बल्कि स्टार्ट अप्स के जरिये पैदा होती हैं। स्टार्ट अप्स नये विचारों का केंद्र भी होते हैं और अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका भी। प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2016 को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन से स्टार्ट अप इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का लक्ष्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्टार्ट अप्स की प्रगति के लिए एक पूरा तंत्र तैयार करते हुए नये विचारों का प्रसार करना है।

उद्देश्य यह है कि भारत नौकरी तलाशने वाले लोगों का एक देश बनने की बजाय एक ऐसा देश बने जहां नौकरियां मिलती हैं। प्रधानमंत्री के स्टार्ट अप इंडिया से भारत में उद्यमियों के बीच काफी सकारात्मकता पैदा हुई है। उद्योग जगत में इस बात को लेकर काफी उल्लास का मौहाल है कि भारत वैश्विक रूप से स्टार्ट अप्स की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। देश में नये विचारों के प्रसार को बढ़ावा देना एक लंबी और अहम यात्रा की तरह है। यह अभियान भारत को नये विचारों और स्टार्ट अप्स के केंद्र के रूप में विकसित करने के भारत सरकार के वचन को दोहराने में काफी अहम भूमिका अदा करेगा।

एक स्टार्ट अप कंपनी या स्टार्ट अप एक युवा कंपनी होती है, जो विकसित होने के शुरुआती स्तर पर होती है। स्टार्ट अप्स सामान्य तौर पर छोटे और शुरुआत में किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के पैसों से शुरू की गयी कंपनी होती है। इस तरह की कंपनियां किसी ऐसे एक उत्पाद या सेवा का वादा करते हैं, जो बाजार में अन्य जगहों पर नहीं मिल रही होती या इसके संस्थापकों को लगता है कि इसे किसी अन्य जगह बड़े स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। शुरुआत में स्टार्ट अप कंपनियों का खर्च उनके राजस्व से ज्यादा होने की संभावना रहती है, क्योंकि वह अपने आइडिया को लेकर बाजार में प्रयोग कर रहे होते हैं। उन्हें अक्सर आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। स्टार्ट अप्स को पारंपरिक रूप से बैंकों या ऋण केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले लघु उद्योग लोन या सरकार प्रायोजित लघु उद्योग प्रबंधनों द्वारा राशि दी जा सकती है या फिर उन्हें गैर लाभकारी संगठनों और राज्य सरकारों द्वारा भी वृत्ति दी जा सकती है।

स्टार्ट अप्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक वह, जो किसी ऐसी चीज की शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं गया होता और वह ऐसी चीज बनाते हैं, जिससे एक नयी शुरुआत होती है। इस तरह के स्टार्ट अप शुरु करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जब ये शुरु हो जाते हैं, तो इनकी प्रगति भी बेमिसाल और अनोखी ही होती है।

दूसरी तरह के स्टार्ट अप्स ऐसे होते हैं, जो पहिए का दोबारा अविष्कार नहीं करना चाहते , लेकिन पहिए को नये तरीके से घुमाने का आइडिया जानते हैं। वे पुरानी

सौरभ सान्याल के पास सशस्त्र बलों और कॉरपोरेट में काम करने का 33 वर्षों का अनुभव है और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीएचडी चैम्बर में एक सेकरेट्री जनरल के पद पर काम कर रहे हैं। ईमेल: saurabh.sanyal@phdcci.in
रंजीत मेहता नयी दिल्ली स्थित पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में निदेशक हैं। अवसंरचना, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल एवं गैस, भूमि अधिग्रहण बिल, रियल एस्टेट बिल, दिल्ली मास्टर प्लान, राष्ट्रीय जल नीति आदि नीतिगत विषयों के अलावा आवासन व लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में नीति निर्माण में सक्रिय रहे हैं। ईमेल: ranjeetmehta@gmail.com

शराब को नयी बोतल में पेश करने में माहिर होते हैं।

उद्यमिता या स्टार्ट अप्स देश में एक नयी तरह की घटना है। स्टार्ट अप शुरू करना मुश्किल काम है और हर देश को इसमें सफलता से ज्यादा विफलता मिलती है। एक उद्यमी को कड़ी मेहनत करने और असफलता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उद्यमिता उत्सव की पृष्ठभूमि में पनपती है। एक ऐसा समाज जो व्यवसाय में होने वाली असफलताओं को लेकर हमेशा ही उदासीन रुख अपनाता है, वहां नये विचार और रचनात्मकता शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देती है। स्टार्ट अप की असफलता को भी सहज रूप से लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की असफलताएं एक नये उद्यमी को यह सिखाती हैं, कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

एक स्टार्ट अप के तौर पर, आपके सह संस्थापक भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका व्यवसाय सफल ही होगा। एक अच्छा आइडिया होना और उस आइडिया से अच्छा बिजनेस करना, दोनों ही अलग-अलग बाते हैं। एक स्टार्ट अप के लिए ऐसे मार्गदर्शक होना जरूरी है, जो कि इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरे हों या जिन्हें बिजनेस का अनुभव हो। एक अच्छा मार्गदर्शक जरूरी जानकारी देकर असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। हालांकि देश में स्टार्ट अप्स का मार्गदर्शन करने के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं है। इस तरह का कुछ भी अनौपचारिक रूप से होता है। जिस स्टार्ट अप की शुरुआत चंदा जमा करके होती है, उसमें निवेशकों से कुछ मार्गदर्शन जरूर मिलता है, लेकिन इस सबके बीच ईमानदार और अच्छे बिजनेस मेंटर मिलना बहुत दूर की बात है। स्टार्ट अप्स के लिए एक अच्छा मेंटर मिलना या ढूंढना बहुत दूर की कौड़ी जैसा है।

फंडिंग संबंधी चुनौतियां

देशभर में पहली पीढ़ी के ज्यादातर उद्यमी उनके बिजनेस को स्टार्ट अप के बैनर तले पहचान दिलवाने के लिए सरकार के इस अभियान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन फंडिंग, पेटेंट और बौद्धिक संपति बनाने जैसे मुद्दे और चुनौतियां वैसे की वैसे ही हैं। इसी तरह पेटेंट्स के रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रक्रिया और शोध व विकास के लिए जरूरी प्रोत्साहन की कमी एक अन्य समस्या है। ज्यादातर जानकारों के अनुसार यही वजह है कि कुछ लोग स्टार्ट अप्स की शुरुआत विदेशी पहचान के आधार पर करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2,46,495 पेटेंट आवेदन और 5,32,682 ट्रेडमार्क आवेदन एक नवंबर 2015 तक लंबित थे। स्टार्ट अप्स के लिए 90 प्रतिशत फंडिंग विदेशी पूंजी से आती है। घरेलू निवेशक इनोवेशन की प्रकृति की भी बदल सकते हैं। ग्रांड थोर्टन द्वारा किये गये हालिया शोध के अनुसार 2015 में 600 ऐसी कंपनियों को 2 बिलियन डॉलर का फंड पीई और वीसी फंड्स से मिला था।

हालिया शोध के अनुसार, 94 प्रतिशत से ज्यादा नये व्यवसाय शुरुआत के पहले साल ही असफल हो जाते हैं। फंडिंग की कमी इसका एक बड़ा कारण है। धन किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है। एक आइडिया से राजस्व एकत्र करने तक की कड़ी मेहनत से जुड़ी लेकिन रोमांचक बिजनेस यात्रा को पूंजी नामक ईंधन की जरूरत होती है। यही कारण है कि बिजनेस के प्रत्येक स्तर पर उद्यमी खुद को इस सवाल से घिरा पाते हैं कि अब मैं अपने इस स्टार्ट अप में पूंजी कहां से लगाऊंगा? स्टार्ट अप्स के लिए बाजार में विभिन्न प्रकार की फंडिंग व्यवस्थाएं हैं। यहां इनमें से कुछ विकल्प दिये गये हैं, जो उनके बिजनेस में पूंजी एकत्र करने में मदद करेंगे:

स्टार्ट अप्स के लिए 90 प्रतिशत फंडिंग विदेशी पूंजी से आती है। घरेलू निवेशक इनोवेशन की प्रकृति की भी बदल सकते हैं। ग्रांड थोर्टन द्वारा किये गये हालिया शोध के अनुसार 2015 में 600 ऐसी कंपनियों को 2 बिलियन डॉलर का फंड पीई और वीसी फंड्स से मिला था।

मुद्रा

इसकी 20,000 करोड़ रुपये की राशि से शुरुआत की गयी ताकि 10 लाख एसएमई तक लाभ पहुंचाया जा सके। आप अपना बिजनेस प्लान इन्हें सौंप सकते हैं और एक बार स्वीकृत होने के बाद, लोन भी स्वीकृत हो जाता है। आपको एक मुद्रा कार्ड मिलता है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। इसका इस्तेमाल आप कच्चा माल खरीदने और अन्य खर्च निकालने के लिए कर सकते हैं।

शिशु, किशोर और तरूण नाम से लोन की तीन प्रकार की श्रेणियां है, जिनसे आशाजनक योजनाओं के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है।

सेल्फ फंडिंग स्व-निधिकरण

स्व-निधिकरण स्टार्ट अप में पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। खासतौर पर तब जब आप अपना बिजनेस शुरू ही कर रहे हैं। पहली बार जब उद्यमी बनते हैं, तो फंड जुटाना मुश्किल हो जाता है।

क्राउड-फंडिंग

क्राउड फंडिंग लोन, प्री-ऑर्डर या एक से ज्यादा लोगों से मिले निवेश की तरह होता है। इसमें किसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट अप शुरू करने वाला व्यक्ति, अपने बिजनेस का विस्तृत ब्यौरा लिखता है। वह अपने बिजनेस का लक्ष्य, लाभ कमाने की योजना और उसे कितना फंड चाहिए और इसका कारण इत्यादि जानकारी भी लिखता है। इसके बाद उपभोक्ता इसके बारे में पढ़ते हैं और अगर उन्हें ये आइडिया पसंद आता है, तो वे इसके लिए एक निश्चित राशि देते हैं। जो लोग पैसा लगाते हैं, वह ऑनलाइन यह वादा भी करते हैं कि वह प्रोडक्ट की प्री-बुकिंग कराएंगे। एक बिजनेस की मदद करने के लिए कोई भी पैसा लगा सकता है। क्राउड फंडिंग की कुछ मशहूर साइट्स हैं- इंडेइगोगो, विशबेरी, केट्टो, फंडलाइंड।

एंजल इनवेस्टमेंट

एंजल इनवेस्टर्स वे लोग होते हैं, जिनके पास एक निश्चित धन राशि होती है, जिसे वे किसी नये स्टार्ट अप में निवेश करना चाहते हैं। वह कई तरह के समूहों में काम करते हैं, जिसमें निवेश करने से पहले वह अलग-अलग आवेदनों पर विचार करते हैं। पूंजी लगाने के अलावा वह स्टार्ट अप्स में सलाह देने और मार्गदर्शन का कार्य भी करते हैं। एंजल इनवेस्टर्स ने कई नामी कंपनियों की शुरुआत में मदद की है। इनमें गूगल, याहू और अलीबाबा जैसे नाम शामिल हैं। निवेश की यह वैकल्पिक व्यवस्था आमतौर पर कंपनी की शुरुआती स्थिति में मदद करती हैं। इसमें निवेश 30 प्रतिशत तक इक्विटी की उम्मीद करते हैं। वह अच्छे और बेहतर रिटर्न पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जोखिम लेने को तरजीह देते हैं।

वेंचर कैपिटल

यह व्यावसायिक रूप से प्रबंधित पूंजी होती है, जो उन कंपनियों में लगायी जाती है, जिनमें भविष्य में एक सुनिश्चित प्रगति होने की उम्मीद होती है। वे आमतौर पर इक्विटी से इतर निवेश करते हैं और जब कोई आईपीओ इत्यादि शामिल होता है, तो वे इससे बाहर निकल जाते हैं। वेंचर कैपिटल, सलाह, विशेषज्ञ सुझाव देने के अलावा किसी भी संगठन के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह काम करते हैं। वह किसी भी बिजनेस का बारीकी से अवलोकन करते हैं।

बिजनेस इनक्यूबेटर्स एवं एक्सलेटर्स

फंडिंग का एक विकल्प बिजनेस इनक्यूबेटर्स भी हो सकते हैं। इनकी उपस्थिति लगभग हर बड़े शहर में होती है। ये हर साल सैंकड़ों स्टार्ट अप बिजनेस को सहायता प्रदान करते हैं। इनक्यूबेटर्स की भूमिका वैसी ही होती है, जैसी कि एक बच्चे के लिए उसके अभिभावकों की होती है। वे बिजनस को जरूरी सुविधाएं देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और नेटवर्क भी प्रदान करते हैं। एक्सलेटर्स भी लगभग इसी भूमिका में होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इनक्यूबेटर्स बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और एक्सलेटर्स उसे आगे तेज छलांग लगाने का आत्मविश्वास देते हैं।

माइक्रोफाइनेंस प्रदाता या एनबीएफसी

माइक्रोफाइनेंस मूल रूप से उन लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाना है, जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। ये उन लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिनकी जरूरतें सीमित हैं और बैंकों द्वारा जिन्हें ऋण नहीं दिया जाता। इसी तरह एनबीएफसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, जो कि बैंक होने की प्राथमिकताएं पूरी न होने के बावजूद भी बैंकिंग सुविधाएं देते हैं।

स्टार्ट अप्स के प्रसार के अभियान

स्टार्ट अप एक्शन प्लान का 19-सूत्रों का लक्ष्य है। इसमें श्रम एवं पर्यावरण नियमों का पालन करने के लिए स्व मान्यकरण, पेटेंट फाइल करने के लिए मददकर्ताओं का एक समूह और इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी एप्लीकेशंस, कर में छूट, पूंजी लाभ और आयकर में तीन साल की छूट और साथ ही चार साल के लिए फंड के फंड से 10,000 करोड़ का वित्तीय सहयोग जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं।

स्वयं प्रमाणन: नियामक देनदारियों को कम करने के लिए स्टार्ट अप स्वयं प्रमाणन की प्रक्रिया को अपनाएंगे। स्वयं प्रमाणन ग्रैच्युटी का भुगतान, श्रम अनुबंध, प्रोविडेंट फंड प्रबंधन, पानी एवं वायु प्रदूषण एक्ट इत्यादि नियमों पर लागू होगा।

स्टार्ट अप इंडिया हब: एक ऑल-इंडिया हब तैयार किया जाएगा, जो भारत में स्टार्ट अप फाउंडेशंस के लिए एक साझा संपर्क केंद्र होगा। यह उद्यमियों को जानकारी और पूंजी तक पहुंच के रास्ते तलाशने में मदद करेगा।

स्टार्ट अप इंडिया की 19-सूत्री योजना

- स्वयं-प्रमाणन अनुपालन
- स्टार्ट अप इंडिया हब: एकल संपर्क बिंदु
- रजिस्ट्रेशन और सूचना इत्यादि के लिए कानूनी सहायता, फास्ट ट्रैकिंग और पेटेंट पंजीकरण शुल्क में 80% की कमी
- सार्वजनिक प्रोक्योर्मेंट में छूट से जुड़े मानदंड
- आसान और तेज निकास
- फंड के फंड राशि से 10000 करोड़ रुपये का पूंजी सहयोग
- क्रेडिट गारंटी फंडिंग
- पूंजीगत लाभ पर कर छूट
- तीन साल तक कर में छूट उचित बाजार मूल्य से ऊपर निवेश पर कर छूट
- वार्षिक स्टार्ट अप फेस्ट
- अटल इनोवेशन मिशन के तहत विश्वस्तरीय नवाचार केंद्रों का शुभारंभ
- ऊष्मायन और अनुसंधान एवं विकास बढ़ाने के लिए नवाचार केंद्र
- नवाचार प्रोत्साहन के लिए अनुसंधान पार्क
- जैव प्रौद्योगिकी में उद्यमिता को बढ़ावा देना
- छात्रों के लिए नवप्रवर्तन केंद्रित कार्यक्रम
- वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रांड चैलेंज

एप से रजिस्ट्रेशन: मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाना है, ताकि स्टार्ट अप शुरू करने वाले लोग आसानी से रजिस्टर कर सकें।

पेटेंट सुरक्षा: केंद्र सरकार द्वारा कम कीमत पर पेटेंट परीक्षण के लिए एक फास्ट ट्रैक व्यवस्था का खाका तैयार होना है। यह व्यवस्था स्टार्ट अप फाउंडेशंस द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स (आईपीआर) के स्वीकरण और जागरुकता का प्रसार करेगी।

10000 करोड़ रुपये का फंड: सरकार शुरुआती ढाई हजार करोड़ की राशि और कुल दस हजार करोड़ की राशि के साथ चार साल के लिए एक पूंजी सुरक्षित करेगी, ताकि स्टार्ट अप उद्योगों को सहयोग किया जा सके। यह पूंजी जुटाने में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन काफी अहम भूमिका निभाएगी। स्टार्ट अप इंडस्ट्री द्वारा चुने गये निजी कुशल लोगों की एक समिति इस फंड का प्रबंधन संभालेगी।

राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी: राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी (एनसीजीटीसी) को अगले चार साल के लिए प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये के बजट से तैयार किरया गया है, ताकि स्टार्ट अप्स में पूंजी निवेश के प्रवाह को सहयोग किया जा सके।

कोई पूंजी लाभ कर नहीं: वर्तमान में, उद्यम पूंजी निधि द्वारा निवेश को पूंजी लाभ कर से छूट प्राप्त है। यही नीति स्टार्ट अप्स में प्राथमिक स्तर पर किये जाने वाले निवेश में भी लागू होगी।

तीन साल तक कोई आयकर नहीं: स्टार्ट अप्स तीन साल तक कोई भी आयकर नहीं देंगे। यह नीति भविष्य में स्टार्ट अप्स को आगे बढ़ने में गति देगी।

उच्च मूल्य के निवेश के लिए कर छूट: बाजार मूल्य से अधिक के निवेश के मामले में इसे कर से छूट दी जाएगी।

उद्यमी तैयार करना: पांच लाख से ज्यादा स्कूलों में छात्रों के लिए इनोवेशन संबंधी पाठ्यक्रम योजनाएं। इसके अलावा विश्वस्तरीय इनक्यूबेटर्स तैयार करने के लिए एक वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज भी होगा।

अटल इनोवेशन मिशन: नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा।

इनक्यूबेटर्स की व्यवस्था: राष्ट्रीय संस्थानों में 35 नये इनक्यूबेटर और 31 नवाचार केंद्रों के लिए एक निजी-सार्वजनिक साझेदारी मॉडल पर विचार किया जा रहा है।

शोध उद्यान: सरकार ने सात नये अनुसंधान पार्क स्थापित करने की योजना बनायी है, जिनमें से छह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में हैं और एक भारतीय विज्ञान संस्थान में 100 करोड़ रुपये निवेश के साथ हैं।

जैव प्रौद्योगिकी में उद्यमिता: सरकार देश में पांच नये बायोटेक समूहों, 50 नये जैव इन्क्यूबेटरों, 150 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

कार्यालयों और 20 जैव-कनेक्ट कार्यालयों की स्थापना करेगी।

स्कूलों में समर्पित कार्यक्रम: सरकार 5 लाख से अधिक स्कूलों में छात्रों के लिए नवाचार संबंधी कार्यक्रम पेश करेगी।

कानूनी सहायता: सुविधाकर्ताओं का एक पैनल पेटेंट आवेदन और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में कानूनी समर्थन और सहायता प्रदान करेगा।

छूट: कुल मूल्य का 80 प्रतिशत की छूट राशि उद्यमियों को पेटेंट आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए प्रदान की जाएगी।

आसान नियम: स्टार्ट अप के लिए सार्वजनिक खरीद और व्यापार के नियमों के नियम सरल किये गये हैं।

तेज निकास: अगर कोई स्टार्ट अप असफल हो जाता है, तो सरकार उद्यमी को उनकी समस्याओं को उचित समाधान तलाशने के लिए सहायता देती है। यदि वह फिर से असफल होते हैं, तो सरकार उन्हें बाहर निकलने का आसान तरीका उपलब्ध कराएगी। भारतीय स्टार्ट अप्स में साल 2016 की तीन तिमाहियों तक 3.5 अरब डॉलर की एंजल और वेंचर पूंजी का निवेश देखा गया। इनमें 815 डील शामिल थी। यह बीते साल हुई डील की कीमतों से काफी कम था। *योर स्टोरी* के शोध के मुताबिक जनवरी और सितंबर 2015 के मध्य 7.3 अरब डॉलर 639 डील्स में निवेश किये गये थे। इस साल जबकि डील्स की संख्या 27 प्रतिशत तक बढ़ गयी है, डील का मूल्य और टिकट का आकार कम हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो 2014 में पूरे साल सिर्फ 300 वेंचर कैपिटल और एंजल डील हुई थीं।

यह कहा जा सकता है कि आर्थिक व्यवस्था में नये प्रतियोगी आयाम लाकर स्टार्ट अप कंपनियां बाजार में सबसे ज्यादा गतिशील आर्थिक संगठन हैं, क्योंकि ये किसी भी आर्थिक व्यवस्था में अतिरिक्त गति और प्रतिस्पर्धा लाते हैं। यह बदलाव के लिए एक प्रेरक का कार्य करते हैं, जिससे कि एक प्रकार का चेन रिएक्शन होता है।

एक बार जब उद्योग स्थापित हो जाता है, औद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह सभी गतिविधियां उद्यमिता को बढ़ाने में मदद करती हैं और विभिन्न प्रकार की इकाइयों की मांग पैदा करती हैं। मांग में वृद्धि के कारण पूरे क्षेत्र का विकास होता है और ज्यादा से ज्यादा इकाइयां बनती हैं। स्वदेशी स्टार्ट अप्स न सिर्फ लोगों की जिंदगी को आसान बनाते हैं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति और विकास के लिए भी मुख्य कारक साबित होते हैं।

हम मानते हैं कि स्टार्ट अप इंडिया का उद्देश्य भारत में संपन्नता लाना है। बहुत से युवा जो अपना खुद का उद्यम शुरू करना चाहते हैं, उनके पास संसाधनों का अभाव होता है। नतीजतन उनके आइडिया, टैलेंट और क्षमताएं व्यर्थ हो जाती हैं और देश अर्थव्यवस्था की वृद्धि, रोजगार जैसे अवसर खो देता है।

स्टार्ट अप इंडिया उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जिन लोगों के पास नये विचार हैं और उनके आधार पर वह अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उन्हें विभिन्न स्तरों पर सहयोग और प्रोत्साहन के जरिए मदद की जाए। ❑

क्या आप जानते हैं?

एंजल फंडिंग

एंजल फंडिंग विशेष रूप से स्टार्ट अप कंपनियों में किये गये प्राचीनतम इक्विटी निवेश हैं। एंजल निवेशक छोटे स्टार्ट अप्स या उद्यमियों में निवेश करते हैं और प्राय: कारोबार की व्यवहार्यता के बजाय उद्यमियों में निवेश करते हैं। वे स्टार्ट अप्स के शुरुआत में मदद करते हैं और कारोबार से होने वाले संभाव्य लाभ की चिंता नहीं करते।

एंजल शब्द रंगमंच (थियेटर) से लिया गया है जहां इसका प्रयोग धनी व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्होंने रंगमंचीय प्रस्तुतियों के लिए धन दिए, जिसके बिना वे रंग-समूह बन्द हो जाते। एंजल निवेशक प्राय: हमेशा धनी होते हैं और निवेशकों के नेटवर्क में सामान्य रूप से जुड़ जाते हैं। ये नेटवर्क प्राय: क्षेत्रीय, औद्योगिक या अकादमिक संबंधन पर आधारित होते हैं। हाल के वर्षों में, शुरू किये गये स्टार्ट अप्स की संख्या के आधार पर भारत वैश्विक धरातल पर शीर्ष तीन देशों में से एक के रूप में उभरा है और भारतीय स्टार्ट अप्स परिदृश्य काफी प्रभावी जान पड़ता है।

इंडिया वेंचर कैपिटल व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा तैयार निजी इक्विटी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-15 की अवधि के दौरान स्टार्ट अप्स में किया गया कुल अनुमानित वेंचर निवेश रु. 1117 अरब (2015 को आधार वर्ष मानते हुए) है। वास्तविक निवेश इससे काफी अधिक रहा होगा क्योंकि कई डील्स के लिए निवेश राशि के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2005-15 की अवधि के दौरान निवेश प्रवाह में औसत वार्षिक संवृद्धि दर लगभग 42 प्रतिशत है। वर्ष 2005-15 के दौरान 10,000 से अधिक स्टार्ट अप्स को फंडिंग प्राप्त हुई। वर्ष 2005-15 की अवधि के दौरान फंड किये गये स्टार्ट अप्स की संख्या में औसत वार्षिक संवृद्धि 16 प्रतिशत रही। अधिकांश क्षेत्रों में विदेशी स्टार्ट अप्स के समांतर एक समतुल्य भारतीय स्टार्ट अप्स रहा है। यद्यपि कई विदेशी स्टार्ट अप्स ने भी भारत में परिचालन आरंभ किया है, तथापि भारतीय स्टार्ट अप की उपस्थिति का अभिप्राय यह रहा कि भारतीय उपभोक्ता को विदेशी कंपनी के भारत में परिचालन शुरू करने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

मौजूदा सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को देखें तो एंजल्स अपनी दृष्टि और ऊंची रखकर पांच से सात वर्षों की धारिता अवधि के भीतर न्यूनतम 20 से 30 गुना रिटर्न प्रदान करने की संभावना वाले कंपनियों को ढूंढ़ते हुए और बेहतर कर सकते हैं। असफल निवेश कवर करने तथा सफल निवेशकों के लिए भी बहु वर्ष धारिता समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एंजल निवेश के खास सफल पोर्टफोलियो के लिए रिटर्न की वास्तविक प्रभावी आंतरिक दर वास्तव में 20-30 प्रतिशत तक कम है। यद्यपि किसी भी दत्त निवेश पर रिटर्न के उच्च दर के लिए निवेशकों की आवश्यकता एंजल वित्तपोषण को फंड्स का खर्चीला स्रोत, पूंजी का सस्ता स्रोत, मसलन बैंक वित्तपोषण, बना सकता है पर यह अधिकांश शुरुआती उपक्रमों के लिए प्राय: उपलब्ध नहीं होता।

इंडियन एंजल नेटवर्क देश के एंजल निवेशकों का प्राचीनतम नेटवर्क है, जो कि वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। गत वर्ष, इसने 18 टर्म शीट्स को स्वीकार किया और सहकारी व समुदाय आधारित उत्पादकों गोकूप के लिए फूड टेक स्टार्ट अप मुकुंडा से ऑनलाइन मार्केटप्लेस की व्यापक परिधि में 11 डील्स को पूरा किया। कुछ अन्य एंजल ग्रुप में मुंबई ऐंजल्स, हार्वर्ड ऐंजल्स, चेन्नै ऐंजल्स तथा इंडिया कोशेंट शामिल हैं। युवा उद्यमी एंजल निवेशकों से वित्त जुटाने को लेकर आशान्वित हो सकते हैं क्योंकि सफलता की काफी लोकप्रिय कहानियां कई एंजल निवेशकों को स्टार्ट अप में पूंजी लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ❑

युवा: परिवर्तन के वाहक

सुनीता सांघी

''कौशल विकास बेहतर भारत का निर्माण कर रहा है। यदि हम भारत को विकास के पथ पर बढ़ाना चाहते हैं तो कौशल विकास हमारा ध्येय होना चाहिए'' – **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (15 अगस्त 2014)**

कौशल जरूरतों की पूर्ति के लिए कुल 13 हजार से अधिक संस्थान, 4000 से अधिक पोलिटेक्निक एवं 20 हजार से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संलग्न हैं। ये संस्थान जीवनपर्यंत सीखने की प्रक्रिया के जरिये लोगों को अपनी भरपूर क्षमता के दोहन की सुविधाएं प्रदान करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में सीमित कौशल वाले कामगार बड़ी संख्या में कार्यरत हैं तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत पूर्व में प्राप्त प्रशिक्षण के प्रमाणन के लिए उनके आकलन की जरूरत होती है

भारत आबादी की दृष्टि से बदलाव के कगार पर खड़ा है, जिसकी 65 फीसदी आबादी 15 से 59 वर्ष के कामकाजी उम्र के लोगों की है। यह भारत को कुशल कामगारों की राजधानी बनाने का बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है, जो सर्वमान्य मानकों के अनुरूप कौशल विकास करके कुशल कामगारों की दुनिया की जरूरतें पूरी कर सकें।

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार, 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति युवाओं में शामिल होते हैं। यह भिन्न-भिन्न जरूरतों और अपेक्षाओं वाला विविध समूह होता है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार, युवाओं की आबादी 28 प्रतिशत है, जिसकी भारत की सकल राष्ट्रीय आय में भागीदारी करीब 34 प्रतिशत रही है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में युवाओं की भागीदारी उनकी श्रमशक्ति और उत्पादकता में वृद्धि करके बढ़ायी जा सकती है। युवाओं की भरपूर क्षमता का दोहन करने और कुशल कामगारों की आपूर्ति के मामले में भारत को अगुआ बनाने के लिए युवा शक्ति का सशक्त बनाया जाना समय की मांग है।

आबादी संबंधी यह विशेषता भारत के सभी हिस्सों में एक समान नहीं है। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले प्रायद्वीपीय भारत तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे पश्च प्रदेशों के बीच स्पष्ट अंतर दिखने को मिलता है। यद्यपि प्रायद्वीपीय राज्यों में चीन एवं कोरिया की तरह ही कामकाजी उम्र वाली आबादी में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन पश्च प्रदेश अपेक्षाकृत युवा एवं ऊर्जावान नजर आते हैं। इस तरह आबादी की दृष्टि से दो प्रकार का भारत नजर आता है। एक ऐसा प्रायद्वीपीय भारत जहां की आबादी जल्द ही उम्र के ढलान पर पहुंचने वालों की होगी, जिनकी जरूरतों का पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा, दूसरा ऐसे पश्च प्रदेशों वाला युवा भारत जहां शिक्षा, कौशल एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।

हालांकि स्थान बदलने की इच्छा शक्ति की कमी और प्रशिक्षण के पैसे न दे पाने के कारण नियोक्ता के समर्थन के अभाव में, निम्न साक्षरता के कारण एवं अन्य प्रकार की जानकारियों के प्रति जागरूकता के अभाव में इन राज्यों में युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित कर पाना कठिन है। युवाओं को सशक्त बनाने का सवाल बाजार में युवाओं की भागीदारी पर एक नजर डालने को अनिवार्य बना देता है।

युवा और श्रम बाजार

नीचे दी गयी तालिका 1 में श्रम बाजार के विभिन्न संकेतक जैसे- श्रमबल भागीदारी की दर (नौकरी वाले या काम की तलाश करने वाले), कामगारों की आबादी का अनुपात और बेरोजगारी दर आदि भारत में युवाओं के श्रम बाजार की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि लिंग एवं स्थानीय भेदभाव से इतर सभी आयु समूहों के लिए एलएफपीआर में गिरावट दर्ज की गयी है। हालांकि ग्रामीण महिलाओं के संबंध में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गयी है, इसका मुख्य कारण सामाजिक/धार्मिक परंपराओं के कारण ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों की कमी है। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में कम आयु वर्ग के युवाओं में गिरावट इस बात को दर्शाती है कि ऐसे युवक श्रम बाजार में प्रवेश से पहले अपने कौशल विकास से संबंधी शिक्षण-प्रशिक्षण लेने में जुट जाते हैं, जिससे इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है। 15 से 29 वर्ष के आयुवर्ग के विभिन्न दस्ते के युवाओं की कार्यबल सहभागिता दर (डब्ल्यूपीआर) का रुझान भी श्रमबल सहभागिता दर के समान ही है।

लेखिका नीति आयोग में कौशल विकास, रोजगार और नगरीकरण प्रबंधन मामलों की सलाहकार पद पर कार्यरत हैं। ईमेल: sunitasanghi1960@gmail.com

तालिका 1: श्रम बल हिस्सेदारी दर (एलएफपीआर), कामगार आबादी अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और विभिन्न आयु वर्ग के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर (यूआर)

ग्रामीण पुरुष						
आयुवर्ग	**1999-2000**			**2011-12**		
	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर
15-19	532	503	6.5	333	303	11.4
20-24	889	844	6.2	788	742	6.9
25-29	975	950	3.2	963	942	2.8
15-29	-	741	5.1	-	616	6.1
कुल	**540**	**531**	-	**553**	**543**	-
ग्रामीण महिलाएं						
15-19	314	304	3.1	164	156	8.0
20-24	425	409	4.9	297	278	9.9
25-29	498	491	2.4	369	357	5.8
15-29	-	400	3.7	-	258	7.8
कुल	**302**	**299**	-	**253**	**248**	-
शहरी पुरुष						
15-19	366	314	15.4	256	223	14.4
20-24	755	658	13.9	664	594	11.6
25-29	951	883	7.5	951	906	5.3
15-29	-	593	11.5	-	558	8.9
कुल	**542**	**518**	-	**563**	**546**	-
शहरी महिलाएं						
15-19	121	105	15.5	89	78	15.3
20-24	191	155	25.8	197	160	21.9
25-29	214	194	15.8	253	231	10.8
15-29	-	149	19.9	-	157	15.6
कुल	**147**	**139**	-	**155**	**147**	-

स्रोत: *रोजगार एवं बेरोजगारी को लेकर एनयेसएसओ सर्वेक्षण (विभिन्न चरण)*

टिप्पणी: (1). श्रमबल हिस्सेदारी दर (एलएफपीआर) का अर्थ श्रमबल (रोजगार प्राप्त एवं बेरोजगार दोनों) में प्रति 1000 व्यक्तियों की तुलना में व्यक्तियों/व्यक्ति-दिवस की संख्या। (2). कामगार आबादी अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का अर्थ रोजगार प्राप्त प्रति 1000 व्यक्ति की तुलना में व्यक्तियों/व्यक्ति-दिवस। (3). बेरोजगारी दर का अभिप्राय श्रमबल में प्रति 1000 व्यक्तियों/ व्यक्ति-दिवसों की संख्या की तुलना में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या।

इस प्रकार सभी श्रेणियों के विभिन्न आयुवर्गों में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत से 15.6 प्रतिशत के बीच है। 15 से 29 वर्ष की शहरी महिलाओं में सर्वाधिक 15.6 प्रतिशत बेरोजगारी दर होती है और इसका मुख्य कारण संभवत: महिलाओं को परिवार का समर्थन मिलना है। सभी श्रेणियों के विभिन्न आयु वर्गों में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक शुरुआती आयु वर्ग यानि 15-19 वर्ष के युवाओं में नजर आयी। आयु बढ़ने के साथ बेरोजगारी दर घटने लगती है, फिर भी यह राष्ट्रीय औसत से अधिक ही है।

युवाओं, खासकर शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर उच्च स्तर पर है, जिसके कारण जनसंख्या संबंधी लाभ मिल पाने में अड़चनें आ रही हैं। ईयूएस 2011-12 आंकड़ों के अनुसार, शिक्षित युवाओं में उच्च बेरोजगारी दर की मुख्य वजह श्रम बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बेहतर नौकरी पाने की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं में व्यापक अंतर है। ऐसा देखा गया है कि बेरोजगारी की दर न केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं में है, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण हासिल कर चुके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट धारकों के बीच भी है।

उपरोक्त व्याख्या से एक विरोधाभासी स्थिति उभरकर सामने आयी है। युवा जहां नौकरी ढूंढ़ रहे हैं, वहीं उद्योगों को कुशल कामगारों की जरूरत है, इसके बावजूद न तो युवाओं को नौकरी मिल रही है, न उद्योगों को कामगार। कौशल में इस तरह का अंतर युवाओं में बेरोजगारी का सबब बनता है। ऐसा अंतर खास प्रकार के कौशल वाले लोगों की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक होने या समान मजदूरी पर बेहतर योग्यता वाले युवा उपलब्ध होने अथवा नौकरी के लिए जरूरी योग्यता से इतर योग्यता के कारण होता है। प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण संबंधित कौशल के अप्रचलित होने के कारण भी यह अंतर हो सकता है।

भारत में कुल बेरोजगारों की संख्या का 49 प्रतिशत हिस्सा नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं का होता है, जबकि औपचारिक क्षेत्र द्वारा 93 प्रतिशत काम उपलब्ध कराया जाता है। भारत में सुशिक्षित युवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या तो बेरोजगार है अथवा अपनी शिक्षा के अनुरूप उसे नौकरी नहीं मिल सकी है। ऐसे लोग या तो रोजगार चाह रहे हैं अथवा नौकरी या असुरक्षित कार्य के बीच झूल रहे हैं। भारत में कौशल विकास से संबंधित 2017 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, करीब 40 फीसदी शिक्षित युवा रोजगार पाने योग्य हैं। कामकाज के खराब माहौल की समस्या, कार्यस्थल पर असुरक्षा, बाजार से संबद्ध कौशल, सूचनाओं की विषमता एवं कौशल विकास के संबंध में लोगों के बीच खराब अवधारणा से निपटना बहुत बड़ी चुनौती है। उपरोक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि (1) कौशल को लेकर मौजूदा मांग और आपूर्ति के बीच सामंजस्य होना चाहिए, (2) बदलाव के लिए कामगारों एवं उद्यमियों के बीच सामंजस्य बिठाने में मदद की आवश्यकता है और (3) भविष्य के श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप क्षमता का विकास करना एवं सतत बनाये रखना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि रोजगार के क्षेत्र में सुधार की रणनीति कैसे बनायें?

रोजगार पाने योग्य बनाने के लिए पहल

आबादी से जुड़ी इस विशेषता का दोहन करने एवं युवाओं को रोजगार पाने के लायक बनाने के लिए *राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन* के साथ ही कौशल विकास एवं उद्यमिता से जुड़ी नयी राष्ट्रीय नीति वर्ष 2015 में शुरू की गयी थी। इस मिशन का उद्देश्य कुशल कामगारों की फौज खड़ा करना, मांग और आपूर्ति में सामंजस्य बिठाने के लिए अपस्किलिंग और रिस्कीलिंग का काम करना, सामान्य एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता मसौदे की वकालत करना, मांग और

तालिका 2: वर्ष 2011-12 के शिक्षा स्तर के अनुसार सामान्य स्थिति में (समायोजित) बेरोजगारी दर

सामान्य शिक्षा स्तर	बेरोजगारी दर (15-29 वर्ष)			
	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
निरक्षर	2.3	0.8	2.5	1.6
प्राथमिक	3.2	0.6	4.8	4.3
मध्य विद्यालय	4.2	4.6	5.1	5.8
माध्यमिक	4.6	8.6	5.5	15.1
उ. माध्यमिक	6.5	13.8	12.0	14.6
डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट	15.9	30.0	12.5	17.3
स्नातक/अधिक	19.1	29.6	16.3	23.4
कुल	**5.0**	**4.8**	**8.1**	**13.1**

आपूर्ति को पाटना तथा उद्यमशीलता को गति प्रदान करना है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल, लामबंदी एवं जुड़ाव, वैश्विक साझेदारी, आईसीटी का इस्तेमाल, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा विभिन्न वंचित समूहों तक संबंधित कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से व्यावसायिक शिक्षा में बड़ा सुधार किया गया है, इसके लिए कक्षा 9 से ऊपर की स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण को फिर से दिशा दी गयी है, पाठ्यक्रम में उद्योग, व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण, उद्योग आधारित प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की दृष्टि से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईआईटी) में सुधार लाना एवं नयी दिशा देना, औद्योगिक घरानों के साथ लचीले एमओयू करना आदि भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, डिलीवरी में प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल, समर्पित वेब पोर्टल के साथ एप्रैण्टिशशिप प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने तथा एप्रेण्टिश के लिए लोगों को रखने के वास्ते लचीचा रुख अपनाने, उद्योगों को बेहतर तरीके से जोड़ने और बदलती दुनिया की कौशल जरूरतों की पूर्ति के लिए पीपीपी मॉडल पर बहुकौशल संस्थान खोलने आदि के भी प्रयास किये गये हैं। योग्य इंस्ट्रक्टर्स का व्यापक दायरा विकसित करन, पाठ्यक्रमों में शोध करने, व्यावसयिक शिक्षा में शिक्षाशास्त्र समाहित करने तथा कौशल संस्थान पर निगरानी के लिए कौशल विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी दी गयी है।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने के वास्ते कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय सहित 20 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा शुरू की गयी पहल को सामान्य कार्यक्रम, क्षेत्र विशेष से संबंधित एवं सेक्टर विशेष से संबंधित कार्यक्रम के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। विभिन्न कौशल जरूरतों की पूर्ति के लिए कुल 13 हजार से अधिक संस्थान, 4000 से अधिक पोलिटेक्निक एवं 20 हजार से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संलग्न हैं। ये संस्थान जीवनपर्यंत सीखने की प्रक्रिया के जरिये लोगों को अपनी भरपूर क्षमता के दोहन की सुविधाएं प्रदान करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में सीमित कौशल वाले कामगार बड़ी संख्या में कार्यरत हैं तथा *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना* (*पीएमकेवीवाई*) के तहत पूर्व में प्राप्त प्रशिक्षण के प्रमाणन के लिए उनके आकलन की जरूरत होती है। ऐसे कामगारों के कौशल उन्नयन एवं फिर से कुशल बनाने की योजना के लिए पीएमकेवीवाई एक महत्वपूर्ण पहल है। पीएमकेवीवाई हाईस्कूल की पढ़ाई छोड़ चुके लोगों को रोजगार हासिल करने की दक्षता के साथ श्रम बाजार में दोबारा प्रवेश का अवसर उपलब्ध कराती है। हालांकि कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए श्रम बाजार में बड़े बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी प्रक्रियागत कदमों को आगे बढ़ा रही है, यथा- राष्ट्रीय कौशल योग्यता मसौदा, जो लागत, अवधि एवं पाठ्यक्रमों में एकरूपता के लिए विभिन्न केंद्रीय कार्यक्रमों के लिए एक समान मानक बनाता है, उसी प्रकार श्रम बाजार सूचना प्रणाली विभिन्न पक्षों के बीच सूचना लामबंदी तथा देश में कौशल विकास की निगरानी करती है। *राष्ट्रीय कौशल विकास निगम* बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के निजी क्षेत्र के प्रयासों को तेज करता तो है ही, 2015 की नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में महती भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय कौशल परिषदों के आकलन एवं प्रमाणन में मदद करती हैं। सरकार ने कौशल ऋण की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल हो रहे गरीब विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

यद्यपि आवश्यक नीति एवं कार्यक्रम शुरू किये गये हैं, लेकिन आर्थिक विकास के लिए समुचित कौशल विकास के जरिये युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए कुछ और किये जाने की जरूरत है। युवा शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रमुख तत्वों के बारे में अगले सत्र में बताया गया है।

युवाओं की आकांक्षा का पता लगाना

स्थायी कौशल विकास के लिए युवाओं की आकांक्षाओं का पता लगाना महत्वपूर्ण है ताकि सामाजिक-आर्थिक समावेशन के लिए रोजगार के सम्मानजनक अवसर तक आसानी से उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध आंकड़े (ईयूएस, 2011-12) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में किसी खास व्यवसाय को तरजीह देने का संकेत करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, 22.3 प्रतिशत पुरुषों ने *ड्राइविंग एवं मोटर मैकेनिक कार्यों* में प्रशिक्षण लिया वहीं शहरी पुरुषों में 26.3 ने कंप्यूटर से जुड़े कारोबार का प्रशिक्षण ग्रहण किया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में 32.2 प्रतिशत ने वस्त्रों से जुड़े कारोबार जबकि शहरी महिलाओं में 30.4 प्रतिशत ने कंप्यूटर कारोबार में प्रशिक्षण लिया। हालांकि इन आंकड़ों की तुलना एनयेसडीसी की कौशल अंतराल रिपोर्ट से की जाये तो प्रशिक्षण संस्थानों से आवश्यकता के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने जैसे असंतुलन प्रदर्शित होते हैं। *राष्ट्रीय कौशल विकास निगम* की रिपोर्ट के अनुसार, रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करने वाले क्षेत्र कुशल कार्यबल की कमी जैसी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तालिका 3 में *एनयेसडीसी कौशल अंतराल रिपोर्ट* पर आधारित आकांक्षा मैट्रिक्स भी इसका समर्थन करते हैं और मांग के अनुरूप आपूर्ति की जरूरतों को प्रभावशाली तरीके से पूरा करने के लिए युवाओं की आकांक्षाओं का पता लगाने की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं। मैट्रिक्स दर्शाता है कि अधिकांश राज्यों के निर्माण, परिवहन एवं लॉजिस्टिक, खाद्य प्रसंस्करण समेत कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त मांग है लेकिन अधिकांश राज्यों में इन व्यवसायों में मांग कम है।

अत: मांग एवं आपूर्ति के बीच संतुलन बनाये रखने और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए आकांक्षाओं का पता लगाने की जटिलता को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि कौशल के क्षेत्र में पहचान और विशिष्टता के लिए सम्मानित किया जाना युवाओं को प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करेगा। मजदूरों के मान-सम्मान के प्रति जागरुकता आने से युवाओं के ऐसे कार्यों के प्रति समझ एवं विचार में बदलाव आयेगा। युवाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने और आकांक्षाओं का सृजन करने के लिए अलग तरह की प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा। इससे उनकी गतिशीलता में सुधार आयेगी।

कौशल उन्नयन के उत्प्रेरक

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 के अनुसार वर्ष 2022 तक देश में 11

तालिका 3: एस्पायरेशन मैट्रिक्स

विशिष्ट राज्य*	श्रमशक्ति की मांग वाले क्षेत्रक	यूथ एस्पायरेशन		
		उच्च	औसत	निम्न
उत्तर प्रदेश	भवन निर्माण, रियल एस्टेट, संगठित खुदरा एवं बैंकिंग वित्तीय सेवाएं तथा बीमा	आईटी/ आईटीईएस, संगठित खुदरा एवं मीडिया एवं मनोरंजन	बीएफएसआई, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य एवं खाद्य प्रसंस्करण	भवन एवं निर्माण, परिवहन, कृषि एवं अन्य, कपड़ा, अन्य विनिर्माण एवं औषधि
दिल्ली	खुदरा, निर्माण, परिवहन, घरेलू नौकर, आईटी एवं आईटीईएस, आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं और बीमा	खुदरा, आईटी एवं बीपीओ, शिक्षा, ऑटो एवं ऑटो पार्ट्स, लोक प्रशासन, इलेक्ट्रिक औजार, कपड़ा एवं परिधान, इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर	निर्माण, परिवहन, आतिथ्य, मीडिया व मनोरंजन, बीएफएसआई, वाहन रखरखाव, स्वास्थ्य सेवा, धातु व अधातु उत्पाद, प्रिंटिंग एवं पब्लिशिंग, फूड प्रोसेसिंग, रसायन एवं औषधि	घरेलू नौकर, सुरक्षाकर्मी, थोक कारोबार, लकड़ी एवं फर्नीचर, रियल एस्टेट सेवाएं
झारखंड	भवन एवं निर्माण, पर्यटन आतिथ्य, यात्रा, कारोबार, खाद्य प्रसंस्करण, रियल एस्टेट सेवाएं, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, अभियांत्रिकी उत्पाद, परिवहन एवं लॉजिस्टिक	खाद्य प्रसंस्करण, बैंकिंग एवं वित्तीय, अभियांत्रिकी उत्पाद, कपड़ा एवं वस्त्र, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास आईटी-आईटीईएस.	पर्यटन, आतिथ्य, यात्रा एवं कारोबार, रियल एस्टेट एवं बिजनेस सेवाएं, मीडिया एवं संचार, बिजली, गैस एवं जलापूर्ति	भवन एवं निर्माण, खनन, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, संगठित खुदरा, चमड़ा एवं इसके उत्पाद, रसायन एवं औषधि
मध्य प्रदेश	निर्माण, खुदरा, कृषि व अन्य, कपड़ा, परिवहन एवं लॉजिस्टिक, खनिज प्रसंस्करण	आईटी-आईटीईएस, स्वास्थ्य, शिक्षा व कौशल विकास, ऑटो एवं अन्य, मीडिया एवं मनोरंजन	आतिथ्य, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, कपड़ा, परिवहन एवं लॉजिस्टिक, खनिज प्रसंस्करण	निर्माण, खुदरा, कृषि, कपड़ा, परिवहन एवं लॉजिस्टिक एवं खनिज प्रसंस्करण
राजस्थान	इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटरीकृत लेखा, आईटी, मोबाइल रिपेयरिंग, वायरिंग एवं रिपेयरिंग (घरेलू), वाहन मेकेनिक, कूरियर, मार्केटिंग, आभूषण, हस्तशिल्प, हथकरघा	इलेक्ट्रिशियन	हस्तशिल्प एवं हथकरघा	मोबाइल मरम्मत, कंप्यूटर आधारित एकाउंटेंसी, आईटी, वायरिंग एवं मरम्मत (घरेलू) कुरियर डिलीवरी, बिक्री एवं मार्केटिंग, जेम्स एवं ज्वैलरी
पश्चिम बंगाल	निर्माण, खुदरा, कृषि एवं अन्य, एमएसएमई, जूट-टेक्सटाइल, एग्रो-फुड प्रोसेसिंग	आईटी/आईटीईएस, स्वास्थ्य, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, मरम्मत एवं निगरानी, इंजीनियरिंग-ऑटो, शिक्षा एवं प्रशिक्ष, रत्नाभूषण	पर्यटन, यात्रा एवं आतिथ्य, परिवहन एवं लॉजिस्टिक, संचार, रबर एवं प्लास्टिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर	निर्माण, खुदरा, कृषि एवं अन्य, एमएसएमई, जूट-कपड़ा, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण
महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस, संगठित खुदरा, निर्माण, कृषि एवं अन्य, रसायन एवं औषधि, जेम्स एवं ज्वैलरी	आईटी/आईटीईएस, संगठित खुदरा, पर्यटन, यात्रा एवं आतिथ्य, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो एवं ऑटो कंपानेण्ट	मीडिया एवं मनोरंजन, बीएएफएसआई, परिवहन, लॉजिस्टिक, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास तथा कपड़ा	भवन एवं निर्माण, अन्य विनिर्माण, कृषि एवं अन्य, रसायन तथा औषधि, जेम्स एवं ज्वैलरी
तमिलनाडु	निर्माण, खुदरा एवं यात्रा, आतिथ्य एवं पर्यटन तथा बीएफएसआई, ऑटोमोबाइल	ऑटोमोबाइल, आईटी/आईटीईएस, पर्यटन, यात्रा, आतिथ्य, खुदरा, शिक्षा, बीएफएसआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर	कपड़ा, मीडिया, मनोरंजन, परिवहन, लॉजिस्टिक, स्वास्थ्य सेवा, रियल एस्टेट	खाद्य प्रसंस्करण, चर्म, निर्माण, रत्नाभूषण, रसायन एवं औषधि, फर्नीचर, कृषि, हथकरघा व शिल्प

*आबादी की दृष्टि से विशिष्ट राज्य

स्रोत: *एनयेसडीसी स्किल गैप रिपोर्ट 2012, नीति आयोग के डॉ. साक्षी खुराना द्वारा तैयार आंकड़े*

करोड़ लोगों को कुशल बनाने एवं 29 करोड़ लोगों के कौशल में सुधार लाने की आवश्यकता है। इतने बड़े कार्य को पूरा करने के लिए छात्रों एवं युवाओं को पूरे क्षेत्र में कौशल विकास के लिए तैयार करने की जरूरत है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता इस बात निर्भर करती है कि हम युवाओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से तैयार करने में कितने सक्षम हैं। वर्तमान परिदृश्य में प्रशिक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों को तैयार करना बीच में ही छोड़ दिया जाता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं श्रम बाजार के बारे में सूचना का अभाव, इन पाठ्यक्रमों की उपलब्धता, दूसरे स्थानों पर जाने की अनिच्छा के साथ ही पुरानी और उबाऊ गतिविधियां इस कार्य में बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाने के बड़े कारण हैं। भावी प्रशिक्षार्थियों को गतिशील बनाने के लिए विस्तृत रणनीति मौजूदा समय की मांग है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार का *कौशल सखी मॉडल* का उदाहरण लिया जा सकता है।

इसके तहत युवतियों को समुदाय की अन्य महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस कार्य में स्थानीय निकाय के कर्मचारी बदलाव के वाहक बनने के साथ ही युवाओं का डाटाबेस तैयार करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस डाटाबेस को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बैंक खाते से जोड़कर एसएसडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। स्थानीय निकाय के कर्मचारियों से हर घर जाकर कौशल विकास के लिए युवाओं की सूची तैयार करने, अभिभावकों को समझाने तथा अभियान चलाने जैसे कार्य कराये जा सकते हैं।

विद्यालयों, महाविद्यालयों एव अन्य शैक्षणिक संस्थानों में संपर्क कार्यक्रम के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर चलाये जाने वाले जागरुकता कार्यक्रम से श्रम बाजार के परिणाम प्रदर्शित हो सकेंगे और इससे कौशल विकास के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थियों को आकर्षित किया जा सकेगा।

विविधता संतुलन

भारतीय श्रम बाजार क्षेत्र, लिंग एवं स्थान आधारित विविधताओं के समावेश को प्रदर्शित करता है। इस बाजार के अनौपचारिक क्षेत्र में 93 प्रतिशत वहीं औपचारिक क्षेत्र में केवल 8 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार प्राप्त है। इन दोनों क्षेत्रों के कर्मियों को प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है। इनमें किसी क्षेत्र विशेष में मजदूरों के कुशल नहीं होने के कारण अनौपचारिक क्षेत्र का प्रदर्शन काफी खराब है, जो उत्पादकता को प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में कम पढ़े-लिखे और अप्रशिक्षित मजदूरों की भरमार है। ऐसे में इस क्षेत्र में कुशल कार्यबल के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता कार्यक्रम चलाये जाने की जरूरत है।

देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी 48 प्रतिशत है लेकिन श्रम बाजार में उनका योगदान महज 22 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री ने कहा था, "यदि महिलाओं की क्षमता का संवर्द्धन कर उसे विकास प्रक्रिया से जोड़ दिया जाए तो किसी भी देश के आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हो सकती है।" मौजूदा समय में महिलाओं के कौशल विकास पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है ताकि वह श्रम बाजार में योगदान देने के लिए तैयार हो सकें। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें पर्याप्त लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध कराने, उनका कौशल विकास करने या उनकी कुशलता को और बढ़ाने के साथ ही नियोजक द्वारा अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि वह कार्यशील आबादी का हिस्सा बन सकें। इसके अलावा श्रम बाजार में किसी विशेष लिंग के वर्चस्व को भी तोड़ने की जरूरत है। साथ ही उन्हें कौशल विकास के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में इस्पात क्षेत्र में महिलाओं के कौशल विकास के लिए जिंदल स्टील की मदद से हरियाणा सरकार द्वारा की गयी की पहल सराहनीय है।

देश में केवल क्षेत्र और लिंग के आधार पर ही विविधता नहीं है बल्कि दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बुनियादी ढांचा विकास में भी बड़ा अंतर है। दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्र में निजी और सरकारी क्षेत्र के 67 प्रतिशत भारतीय तकनीकी संस्थान (आईटीआई) हैं, जिसमें 51 प्रतिशत आबादी के लिए 60 प्रतिशत सीट की क्षमता है। वहीं, उत्तर एवं पूर्वी क्षेत्र में केवल 33 प्रतिशत आईटीआई हैं, जहां महज 49 प्रतिशत आबादी के लिए 40 प्रतिशत सीट की व्यवस्था है। केवल इतना ही नहीं प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के आधार पर भी बड़ा अंतर दिखायी देता है। इसलिए इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है और जहां तक संभव हो पश्चिम एवं दक्षिणी क्षेत्र में पलायन कर आये मजदूरों के लिए कौशल विकास की जो व्यवस्था की गयी वैसी ही व्यवस्था उत्तर एवं पूर्वी क्षेत्र में भी की जानी चाहिए। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास, प्रशिक्षण, प्रशिक्षुकों का प्रशिक्षण और भविष्य में कुशल कार्यबल तैयार करने के क्षेत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निजी क्षेत्रों का हस्तक्षेप होना जरूरी है।

पुनर्कौशल विकास पर ध्यान

देश में युवाओं की एक बड़ी संख्या माध्यमिक शिक्षा (12वीं) पूरी होने से पहले ही कॉलेज छोड़ देती है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अनुसार, 47 प्रतिशत छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा पूरी होने से पहले पढ़ायी छोड़ दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब उन्होंने श्रम बाजार में प्रवेश किया तो उनकी कुशलता का स्तर काफी नीचे था और उन्हें काफी कम मजदूरी पर काम करना पड़ा। ऐसे में कौशल क्षमता विकास के जरिये उनके कौशल में सुधार करने के लिए अवसर उपलब्ध कराये जाने की जरूरत है। केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय नीति में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए *कौशल विकास, कौशल पुनर्विकास* और *कौशल संवर्द्धन* कार्यक्रमों के बीच स्पष्ट भेद करने की आवश्यकता है। ऐसे मजदूरों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की स्पष्ट पहचान करने की जरूरत है। इसके अलावा कौशल-अंतर विश्लेषण, कौशल विकास के लिए कंटेंट तैयार करने और प्रत्येक घर के स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा ऐसे कर्मियों की पहचान करने की जरूरत है जो काफी पहले श्रम बाजार में प्रवेश कर गये और उनके पास काफी अनुभव तो है लेकिन प्रमाण-पत्र नहीं है। वैसे मजदूर खासकर कलाकार एवं हस्तशिल्प से जुड़े कर्मियों की पहचान जरूरी है जिनके पास उनके पेशे से जुड़ी जानकारियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं। इस संदर्भ में आरपीएल रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने, गतिशीलता, जीवनपर्यंत सीखना, सामाजिक समावेश एवं आत्मसम्मान की रक्षा करने में सक्षम है। भारत में कौशल विकास कार्यक्रम में तेजी लाने की जरूरत है, खासकर ऐसे समय में जब देश में 29.83 करोड़ मजदूरों का कौशल पुनिर्विकास, कौशल संवर्द्धन और आरपीएल किया जाना है। *कौशल विकास मंत्रालय* अपनी राष्ट्रीय नीति के तहत इस ओर ध्यान दे रहा है और इसमें तेजी लाने के लिए प्रयासरत है लेकिन उसके समक्ष आरपीएल की पहचान करने जैसी चुनौतियां भी हैं। फिलहाल कोई ऐसा आरपीएल मॉडल नहीं है जो सभी स्तर की शैक्षणिक योग्यता वाले एवं सभी परिस्थितियों खासकर अलग-अलग क्षेत्र अलग मॉडल विकसित कर सकें। आरपीएल को स्थानीय स्तर पर प्रभावी बनाया जा सकता है। आरपीएल की सफलता इसके बारे में जागरुकता अभियान चलाकर प्रभावशाली व्यावसायिक दिशा-निर्देश एवं काउंसलिंग सेवा, इसका नीति के साथ एकीकरण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली के लिए कानूनी एवं नियामकीय कार्ययोजना, सभी हिस्सेदारों की सक्रिय भागीदारी, आरपीएल के लिए प्रभावशाली कार्ययोजना और पेशा के मानकों के अनुरूप शैक्षणिक मानक तय करने आदि पर निर्भर करती है।

विद्यालय से रोजगार तक: संक्रमण सर्वेक्षण

युवाओं के लिए श्रम बाजार की सूचनाओं की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार की आवश्यकता है। मजदूर कार्यबल सर्वेक्षण रोजगार और बेरोजगारी के साथ ही बेरोजगारी के स्तर, रोजगार की वास्तविक स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। हालांकि यह रोजगार से संतुष्टि और स्कूल से श्रम बाजार में प्रवेश पर होने वाली कठिनाइयों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराता है। स्कूल से कार्यक्षेत्र में प्रवेश सर्वे (एसडब्ल्यूअएस) राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं डिजाइन तैयार करने की रणनीति के लिए श्रम बाजार की ससमय और प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। यह संवदेनशील समूह की पहचान करने में मददगार साबित होगा ताकि नीति निर्माता सही आबादी को लक्ष्य बनाने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकें। इस सर्वे से राष्ट्रीय करियर सर्विस में सुधार आयेगा और युवाओं को संतुष्टिजनक और सुरक्षित रोजगार पाने में मदद मिलेगी। इससे श्रम बाजार की अनेकों भिन्नताओं जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए किये जाने वाले उपायों में सुधार होगा। साथ ही सरकार को कर्मचारियों खासकर वैसे कर्मचारियों, जिन्होंने आमतौर पर प्रशिक्षण नहीं लिया है, को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाले उपक्रमों को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे औद्योगिक क्रांति के कारण रोजगार के क्षेत्र में उभरी चुनौतियों का सामना करने के लिए किये जाने प्रयासों में भी सुधार होगा।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे बदलाव और भविष्य के रोजगार परिदृश्य बेहतर जीवन के लिए रोजगार के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाने के संदर्भ में युवाओं के सामने चुनौती और अवसर दोनों पेश कर रहा है। रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में बढ़ोतरी युवाओं को रोजगार की

युवाओं के नाम प्रधानमंत्री का संदेश 'मन की बात' से कुछ पंक्तियां

- झुलसाती गर्मी के बावजूद गर्मी की छुट्टियां अच्छी लगती हैं। किन्तु एक दोस्त के नाते मैं छुट्टियों के सदुपयोग हेतु कुछ तरीके बताना चाहता हूं... कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिसके बारे में आपने पहले न सुना हो, न देखा हो, न सोचा हो फिर भी जिसके लिए आपके मन में जिज्ञासा हो। आपको नयी जगहों को देखने, नये अनुभव हासिल करने और कोई नया हुनर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस छुट्टी के दौरान आप कुछ नया करें और अपनी जिज्ञासा को शांत करें।

❖❖❖

- दोस्तों, जीवन में कुछ बड़ा करने का स्वप्न बहुत अच्छी बात है, जीवन में किसी उद्देश्य का होना काफी अच्छी बात है और आपको उन लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करना चाहिए परन्तु इस बात का मूल्यांकन अवश्य करें कि कहीं इस प्रक्रिया में आपका मानवीय पक्ष प्रभावित तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रक्रिया में हम अपनी मानवीय विशिष्टताओं से विरत हो रहे हैं।

❖❖❖

- क्या कौशल विकास में इस पहलू पर थोड़ा जोर नहीं दिया जा सकता? तकनीक से थोड़ा दूर जाएं और खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। कोई वाद्य-यंत्र सीखें या फिर किसी नयी भाषा के कुछ नये वाक्य सीखें। यह देश विविधताओं से भरा है और यदि हम देखें तो पाएंगे कि हमारे आस-पास कोई न कोई ऐसा होगा जो हमें कुछ नया सिखा सके। यदि आप तैरना नहीं जानते तो तैरना सीखें, चित्र बनाना सीखें। हो सकता है कि परिणाम बहुत सुन्दर न हो, पर फिर भी पन्ने पर कुछ उकेरने की कोशिश करते रहें। ये सभी नये अनुभव, ये हुनर ऐसे हैं जो आपको आनन्दित करेंगे और आपको उन सीमाओं से मुक्त करेंगे जिनसे आप बंधे हुए हैं।

❖❖❖

- कुछ नया करें। दोस्तों, यही वह समय है जब आप अपने जीवन को रच सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि सभी परीक्षाओं के पश्चात अपने करियर की नयी शुरुआत में आप कोई नया कौशल सीख लेंगे, तो आपको ऐसा अवसर तब नहीं मिलेगा... कुछ ऐसा सीखने का प्रयास करें जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। यह आपके लिए निश्चय ही लाभप्रद होगा। आपकी नैसर्गिक मानवीय क्षमता जागृत होगी और यह विकास के बड़े मौके प्रदान करेगी।

❖❖❖

- नयी पीढ़ी खुद को नकद की जकड़न से मुक्त कर रही है। इस पीढ़ी को नकद की आवश्यकता नहीं है। इस पीढ़ी ने डिजिटल मुद्रा को अपनाना शुरू कर दिया है। मुझे पता है कि आप ऐसा कर रहे हैं पर क्या आप जानते हैं कि इस योजना का प्रयोग करते हुए आप कमा भी सकते हैं? यह भारत सरकार की एक योजना है। आपने भीम एप को अवश्य ही डाउनलोड किया होगा और इसका प्रयोग कर रहे होंगे। इसके बारे में औरों को अवगत कराएं, औरों को भी इससे जोड़ें... आप नये भारत के प्रहरी बनेंगे। छुट्टी का आनंद आय के साथ जुड़ जाएगा। लोगों को जोड़ें व कमाएं!

❖❖❖

सुरक्षा देने के साथ ही उनकी तरक्की के द्वार भी खोलेगा, जिससे युवा सशक्त होकर देश के आर्थिक विकास में सहयोग दे सकेंगे और उस विकास से लाभांवित भी हो सकेंगे। युवाओं को बदलाव का वाहक बनाने के उद्देश्य से तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में शुरू की गयी पहल एवं कार्यक्रमों में पूरे राज्य में तेजी लाना अपेक्षित है। ❑

संदर्भ

- Planning Commission, Government of India (2013) Twelfth Five Year Plan (2012–2017) Social Sectors, Volume III SAGE Publications India Pvt Ltd. http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/12thplan/pdf/12fyp_vol3.pdf
- Planning Commission, Government of India (2008) Eleventh Five Year Plan (2007–2012) Oxford University Press http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/11th/11_v1/11th_vol1.pdf
- Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India (2014) National Youth Policy 2014 http://www.rgniyd.gov.in/sites/default/files/pdfs/scheme/nyp_2014.pdf
- Ministry of Finance, Government of India, Economic Survey, 2016-17, Chapter 1 Economic Outlook and Policy Challenges. http://indiabudget.nic.in/es2016-17/echap01.pdf
- Choudhary, Saahana Rai. "Skill Mismatches In Indian Labour Market; Policy Priorities and Challenges Ahead" Indian Journal of Industrial Relations Volume 49 No. 3 January 2015
- International Labour Organisation (2015) Recognition of Prior Learning: Key Success Factors and the Building Blocks of an Effective System, Ashwani Aggarwal file:///C:/Users/abc/Downloads/Recognition%20of%20prior%20learning-KSF%20(1).pdf
- International Labour Organisation (ILO) 2003 School to Work Transition Surveys http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/WCMS_191853/lang--ja/index.htm
- OECD Economics Department Working Papers No. 1209 (2015) Labour Market Mismatch and Labour Productivity: Evidence from PIACC Data by Müge Adalet McGowan and Dan Andrews
- https://www.oecd.org/eco/growth/Labour-Market-Mismatch-and-Labour-Productivity-Evidence-from-PIAAC-Data.pdf
- National Youth Policy 2014
- Chapter 1 Economic Outlook and Policy Challenges, Economic Survey, 2016-17
- Skill mismatches in Indian labour market; policy priorities and challenges ahead, Saahana Rai Choudhary, the Indian Journal of Industrial Relations Volume 49 No. 3 January 2015.
- 12Th Five Year Plan 2012-2017
- Recognition of prior learning: Key success factors and the building blocks of an effective system, Ashwani Aggarwal ILO
- School to work Transition Surveys, ILO

भारतीय युवाओं की वैश्विक मौजूदगी

शीतल शर्मा
भास्कर ज्योति

युवा प्रवासी भारतीय, भारत के लिए बेहद अहम हैं। पिछले कुछ समय में अमरीका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने उच्च कौशल वाले भारतीयों के लिए वर्क वीजा में कटौती का ऐलान किया है। चूंकि इन देशों में इस तरह के वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय थे, लिहाजा इस तरह के किसी भी कदम से न सिर्फ उनके करियर संबंधी अवसरों पर असर पड़ेगा, बल्कि भारती प्रवासियों की रिहायश और ठहराव भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। सऊदी अरब ने भी एक ऐसी स्कीम पेश की है, जिसके तहत देश से बाहर के लोगों से कामकाज के घरेलू अवसरों को बचाने की बात है

भारतीय नौजवानों ने हमेशा से दुनियाभर में भारतीय दर्शन, सभ्यता और संस्कृति के ध्वजवाहक की भूमिका अदा की है। जब दुनियाभर के धार्मिक और नस्लीय प्रतिनिधि इन आधारों पर अपने-अपने मतों की श्रेष्ठता के बारे में दावा करने में तल्लीन थे, तो एक युवा संन्यासी स्वामी विवेकानंद ने उन्हें धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। यह बात 1893 की है, जब अमरीका के प्रमुख शहर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। दक्षिण अफ्रीका गये युवा भारतीय वकील महात्मा गांधी ने उस मुल्क में पहली बार सत्य और अहिंसा के अपने सिद्धांतों को लेकर प्रयोग किये। बाद में गांधी के ये सिद्धांत दुनिया में शांति और सौहार्द का अमोघ अस्त्र बन गये। गांधी को भारत का पहला *प्रवासी भारतीय* माना जाता है, जिन्होंने दुनिया को ऐसी चीज से नवाजा जिसकी दरकार मानव सभ्यता के हर दौर में रहेगी। भारतीय मूल्यों और सिद्धांतों को दुनियाभर में फैलाने की परंपरा ईसा पूर्व दूसरी सदी से ही चलती आ रही है, जब मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के बेटे और बेटी श्रीलंका (सिलोन) गये और दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म को स्थापित किया। इन उत्साही नौजवानों की विरासत को अब भी लाखों-करोड़ों युवा आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने मौजूदा दौर में दुनिया के तकरीबन हर कोने में अपनी मौजूदगी का अहसास कराया है।

प्रवासी भारतीयः पूर्ण युवा टीम

संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय प्रवसन रिपोर्ट 2015 में कहा गया कि सभी अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की औसत आयु महज 39 साल है। चूंकि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, लिहाजा दुनियाभर में इधर-उधर जाने वाले भारतीय आव्रजक सबसे युवा प्रवासी है। दुनियाभर में कुल 2.5 करोड़ प्रवासी फैले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग (डीईएसए) की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी मुल्कों में रहने वाले भारतीयों की संख्या दुनिया के बाकी देशों की ऐसी किसी भी आबादी के मुकाबले ज्यादा है।

बेशक प्रवासी भारतीयों की वैश्विक मौजूदगी का एक खास भौगोलिक क्षेत्र है, मगर दक्षिण सूडान जैसे छोटे और नये देशों में भी उन्होंने पहचान बना रखी है, जहां उनकी संख्या 100 से भी कम है। सिर्फ संयुक्त राज्य अमरीका में 32 लाख भारतीय हैं जिन्होंने अलग-अलग तरह की नागरिकता और वीजा लिया हुआ है। अमरीका के अलावा खाड़ी देश भारतीय प्रवासियों के पसंदीदा ठिकाने हैं और दोनों को एक साथ मिला देने पर तकरीबन 70 लाख भारतीय प्रवासी हो जाते हैं।

मौजूदा वक्त में भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक स्तर पर विस्तार की जड़ें औपनिवेशिक विरासत से भी जुड़ी हैं। लिहाजा, प्रवासियों की विभिन्नता से जुड़े अहम पहलुओं की थोड़ी सी समीक्षा जरूरी जान पड़ती है। चूंकि, औपनिवेशिक काल में बाहरी दुनिया से भारत के रिश्ते मुख्य तौर पर ब्रिटिश हितों के मद्देनजर तैयार हुए, इसलिए वैसे देशों में भारतीय मूल के प्रवासियों की अच्छी-खासी मौजूदगी है, जहां उपनिवेशवादी ब्रिटिश सरकार का शासन था। लिहाजा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, वेस्टइंडीज समूह और पश्चिम अफ्रीकी देशों में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी हैरानी की बात नहीं है। ब्रिटिश शासकों की गुलामी के काल में हुआ पलायन मौके के

शीतल शर्मा नयी दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के यूरोपीय अध्ययन केंद्र में सहायक प्रोफेसर हैं। ईमेलः sheetal88@gmail.com
भास्कर ज्योति इसी केंद्र में रिसर्च फेलो हैं और उन्होंने 'ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की राजनीतिक भागीदारी' विषय पर एम. फिल किया है। ईमेलः bhaskar_jyoti@yahoo.com

बजाय मजबूरी की बात थी। ऐसे प्रवासियों में मजदूर, सैनिक, नाविक आदि शामिल थे। ये युवा तो थे लेकिन अपना करियर बनाने और अन्य देशों में मौजूद मौकों का फायदा उठाने में सक्षम नहीं थे।

अगले दौर के दूसरे प्रवासियों में अपेक्षाकृत संपन्न और पढ़े-लिखे भारतीय थे। इनमें छात्र, वकील और कारोबारी शामिल थे, जो ब्रिटेन और उसके गुलाम देशों में बस गये और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जरूरी रफ्तार दी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ऐसे ही एक वकील थे, जो ब्रिटेन में बस गये थे और उन्होंने वहां वैसे भारतीय छात्रों को शरण मुहैया कराने के लिए *इंडिया हाउस* खोल रखा था, जिनकी इच्छा ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों के जरिये आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा हासिल करने की थी। यहां तक कि उन्होंने प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी देना शुरू किया। सावरकर, मैडम भीकाजी कामा, मदनलाल ढींगरा उन अहम छात्रों और क्रांतिकारियों में शामिल हैं, जिनका नाम लंदन के *इंडिया हाउस* से जुड़ा है। लिहाजा, युवा छात्रों की एक फौज ने ब्रिटिश हुकूमत की तानाशाही प्रवृत्तियों के बारे में ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों में प्रमुखता से जिक्र किया और लंदन भारतीय युवाओं का प्रमुख केंद्र बन गया। मैडम कामा बाद में पैरिस में बस गयीं, लिहाजा उन्होंने भारतीयों की पहुंच के दायरे का और विस्तार किया। इसी तरह, युवा क्रांतिकारियों के एक समूह ने अमरीका और कनाडा में *गदर आंदोलन* की शुरुआत की और इस तरह से इन देशों को भी संपर्क और चीजों के नियमित आदान-प्रदान को प्रमुख केंद्रों के तौर पर विकसित किया गया।

हालांकि, भारतीयों के पलायन का सबसे अहम दौर औपनिवेशिक शासन के खात्मे के बाद शुरू हुआ। आईआईटी जैसे बेहतरीन संस्थानों के खुलने से युवा प्रतिभाशाली तकनीकी स्नातकों को पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमरीका के विकसित देशों में अवसर हासिल करने का मौका मिला। इन देशों ने इन छात्रों की संभावनाओं को पहचाना और विदेशी मुद्राओं में अच्छा भुगतान किया। ऐसे कुछ प्रतिभाशाली तकनीकी जानकार ब्रिटेन और अमरीका में स्थायी रूप से बस गये।

वैश्वीकरण: बढ़ते पलायन की मुख्य वजह

भारत में उदारीकरण के बाद के दौर में प्रतिभाशाली युवा भारतीयों के लिए विदेश में बड़े मौके पैदा हो गये। विकसित देशों में उत्पादन और श्रम की लागत में बढ़ोतरी से इन मुल्कों को सस्ते विकल्प का रुख करना पड़ा और भारतीय जमीन और यहां का श्रम उनकी जरूरतों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। अमरीका की बड़ी तकनीकी कंपनियों ने अमरीका के तकनीकी कामगारों से आधी कीमत पर, लेकिन उतने ही काबिल और प्रतिभाशाली तकनीकी जानकारों की भर्ती करनी शुरू की। इससे अमरीकी कंपनियों को लागत कम होने का फायदा मिला और उनके मुनाफे में बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ, तकनीकी शिक्षा से जुड़े बेरोजगार युवा भारतीय स्नातकों को अच्छे ढंग का रोजगार मिला। लिहाजा, यह दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा था।

सिलिकॉन वैली: सफल भारतीय उद्यमियों की कहानी

अमरीका में 1960 में सिर्फ 12,000 भारतीय मूल के लोग थे। इनमें से ज्यादातर अकुशल कामगार या कम कौशल वाले अशिक्षित किसान थे। हालांकि, *अमरीका आव्रजन कानून 1990* में हुए सकारात्मक बदलाव से बड़ी संख्या में उच्च कौशल वाले और पढ़े-लिखे भारतीय युवा अमरीका पहुंचे। 1980 से 2013 के बीच वहां कौशल वाले युवा भारतीयों की संख्या 2,06,000 से बढ़कर 20,40,000 हो गयी यानी मोटे तौर पर हर दशक में इस संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हुई। आज उच्च कौशल वाले वर्कर से जुड़े एच-1 वीजा लेने में भारतीय नागरिकों का स्थान बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2014 में अमरीका आव्रजन विभाग ने 3,16,000 एच-1बी वीजा को मंजूरी दी, जिसमें भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी 70 फीसदी थी। भारतीय मूल के तकरीबन 1,03,000 छात्रों ने 2013-14 में अमरीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिला लिया। अमरीका जनगणना ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीका में भारतीय प्रवासियों की औसत आयु 39 साल थी और अमरीका में मौजूद सभी भारतीयों में 83 फीसदी ज्ञान आधारित उद्योग (नॉलेज इंडस्ट्री) से जुड़े थे। अमरीका में मौजूद कुल भारतीय प्रवासियों में सिर्फ 11 फीसदी की उम्र 65 साल या इससे ज्यादा थी। भारतीय प्रवासियों की शिक्षा का स्तर भी सबसे ऊंचा था। यहां तक कि अमरीका मूल के लोगों के शिक्षा के स्तर से भी ऊपर। वर्ष 2015 में 82 फीसदी भारतीय प्रवासी (25 साल या उससे ऊपर के) के पास स्नातक या इससे ऊपर की डिग्री थी, जबकि अमरीका मूल के ऐसे वयस्कों का यह आंकड़ा 30 फीसदी था।

अमरीका का सिलिकॉन वैली इलाका सॉफ्टवेयर तकनीक और स्टार्ट अप फर्मों का सबसे बड़ा वैश्विक ठिकाना है। पिछले कुछ वर्षों में यहां भारतीय चेहरे भी प्रमुखता से उभरकर सामने आये हैं। सिलिकॉन वैली में मौजूद कुछ बड़ी कंपनियां मसलन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एएमडी, एडोबी आदि कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं। फेसबुक, मोटोरोला, रेकिट बेनकाइजर, मास्टर कार्ड आदि जैसी बड़ी कंपनियां और स्टार्ट अप के अहम वैश्विक कारोबार से जुड़े अहम पदों पर कई भारतीय प्रबंधक हैं। बेजोड़ प्रतिभा और भारतीय इंजीनियरों की काबिलियत के चलते भारत के युवाओं को पूरे अमरीका में वाहवाही मिली है।

ऑक्सफोर्ड-कैंब्रिज और लंदन: सदाबहार भारतीय सपने

ब्रिटेन के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से अभूतपूर्व रहे हैं। औपनिवेशिक काल की कटुता को छोड़ते हुए भारत और ब्रिटेन

आरेख 1: सिविल और सामान्य कामों में काम करने वाले कार्मिक

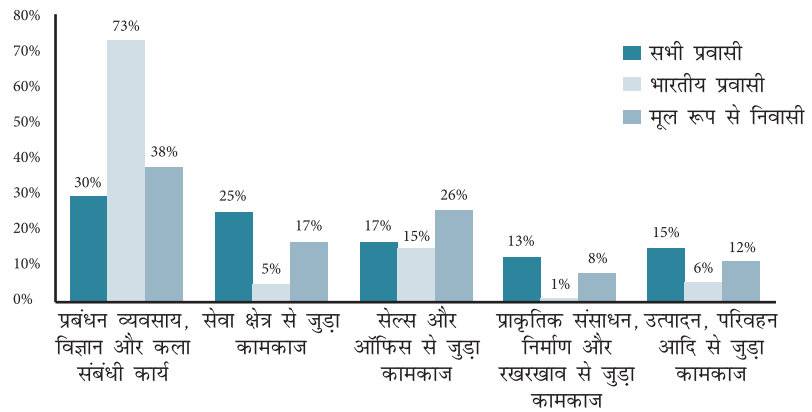

प्रबंधन व्यवसाय, विज्ञान और कला से संबंधित कामकाज

स्रोत: *अमरीकी जनगणना ब्यूरो रिपोर्ट, 2013*

एक-दूसरे को स्वीकार कर एक-दूसरे के विकास की कहानी में साझीदार बने हैं। ब्रिटेन में तकरीबन 20 लाख ब्रिटिश-भारतीय नागरिक हैं, जो अलग-अलग चरणों में ब्रिटेन में आये और इस देश में बस गये। इस आबादी का बड़ा हिस्सा युवा और उत्साही है और ये लोग तीसरी पीढ़ी के प्रवासी हैं, जो कारोबारी, तकनीकी कौशल से लैस और डॉक्टर आदि हैं। ये युवा भारतीय ब्रिटेन की राजनीतिक-सामाजिक संस्कृति में इस कदर घुल-मिल चुके हैं कि वे वहां चुनाव लड़ते हैं और देश की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ब्रिटेन में 2015 के संसदीय चुनावों में रिकॉर्ड संख्या में भारतीय मूल के 10 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार युवा हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की नेता प्रीति पटेल (45 साल) कैमरून सरकार में मंत्री बनीं। ब्रिटेन की किसी सरकार में मंत्री बनने वाली वह पहली ब्रिटिश-भारतीय महिला थीं।

खाड़ी देश और मलेशिया

भारत से दूसरे मुल्कों में लोगों का पलायन फिलहाल मुख्य तौर पर दो तरह का है। पहली श्रेणी के तहत उच्च कौशल वाले पेशेवर, कामगार और स्टूडेंट्स शामिल हैं, जो उच्च शिक्षा हासिल कर काम करते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाते हैं। हालांकि, प्रवासियों में बड़ी हिस्सेदारी आधे कुशल और अकुशल कामगारों की है, जिनके बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों और मलेशिया में पलायन करने का रुख देखने को मिला है। इन प्रवासियों की औसत आयु यूरोप और उत्तरी अमरीका जाने वाले प्रवासियों से भी कम है। पश्चिम एशियाई देशों में ऑयल बूम के बाद इन देशों में बड़े पैमाने में भारत से पलायन की शुरुआत हुई। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की आबादी तकरीबन 60 लाख है। इन लोगों में 90 फीसदी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) हैं। अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा के उलट खाड़ी देशों में भारतीय मूल के लोगों को कामकाज के लिए स्थायी वीजा नहीं के बराबर मिलता है। चूंकि यह कामकाज मुख्य तौर पर निर्माण या मैन्युअल किस्म का होता है, लिहाजा एक निश्चित उम्र के बाद ऐसे शख्स की काम करने की क्षमता सीमित हो जाती है। लिहाजा, ऐसे देशों में ज्यादा उम्र के लोगों की ज्यादा मांग नहीं होती है। हालांकि, भारत के कुछ रियल एस्टेट कारोबारियों ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों में सफलता के झंडे गाड़े हैं, लेकिन मोटे तौर पर इन देशों में भारतीय कारोबारियों के लिए सुनहरा अवसर नहीं है। जहां तक खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीयों का सवाल है, तो केरल राज्य से वहां सबसे ज्यादा प्रवासी हैं। खाड़ी देशों के बड़े अस्पतालों में केरल की युवा महिलाएं और लड़कियां सफलतापूर्वक नर्स और सहायक का काम कर रही हैं। इन देशों में बड़े पैमाने पर भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी होने के कारण यहां पर भारतीय संस्कृति और बॉलीवुड काफी लोकप्रिय है।

प्रतिभा का पलायन या सांस्कृतिक दूत?

दुनियाभर में रह रहे प्रवासी समुदाय की तरफ से भारत को तकरीबन 70 अरब डॉलर मिलते हैं। यह किसी भी देश की तरफ से इस मद में हासिल की गयी रकम के मुकाबले ज्यादा है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खाड़ी मुल्कों के प्रवासियों से सिर्फ केरल को जो रकम मिलती है, वह राज्य के *शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद* (एनयेसडीपी) का 36.3 फीसदी है। बहरहाल, पिछले कुछ दशकों में भारतीय प्रवासी समुदाय ने पूरी दुनिया में भारत की सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों और बुद्धिमता का परचम लहराया है। उन्हें न सिर्फ अपने क्षेत्र में सबसे तेज दिमाग का होने के लिए वाहवाही मिल रही है, बल्कि उन्होंने युवा भारतीय प्रतिभाओं को लेकर बेहतर छवि भी बनायी है। उन्होंने भारत की एक वैकल्पिक और मजबूत छवि बनाने में मदद की है, जिसे पहले सपेरों का देश माना जाता था। लिहाजा, भारत को अपने समुदाय से सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों तरह से फायदा हुआ है।

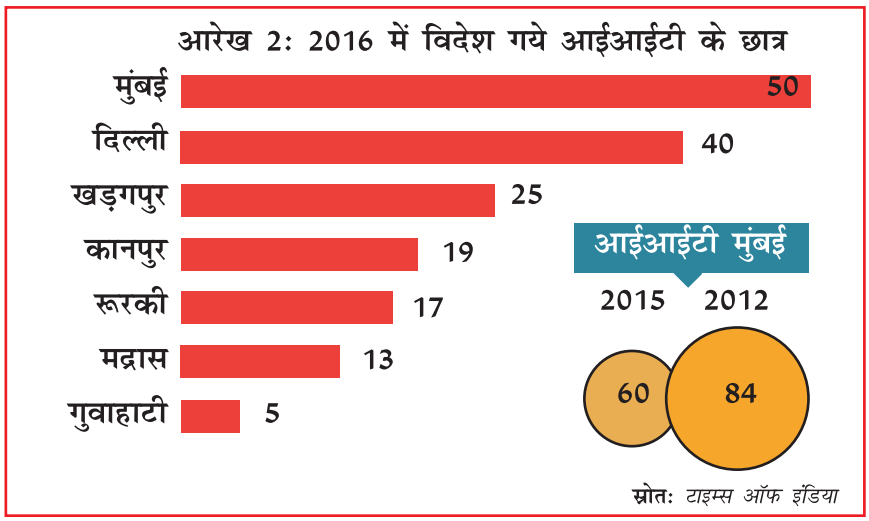

हालांकि, बड़ी संख्या में कुशल और प्रशिक्षित भारतीयों के विदेश पलायन करने से भारत में प्रतिभा पलायन को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। भारत ने 2010 में बाकी देशों को तकरीबन 60,000 डॉक्टर भेजे और इस मामले में उसकी पहली रैंकिंग रही। भारत सबसे ज्यादा प्रशिक्षित विदेशी डॉक्टरों की आपूर्ति ओईसीडी देशों को करता है। इस तरह के व्यापक पलायन से भारत पर बुरा असर पड़ता है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां पहले से ही काफी कम डॉक्टर हैं। भारतीय डॉक्टरों के पलायन की दर तकरीबन 10 फीसदी है, जबकि चीन में यही दर एक फीसदी है। जैव-इंजीनियरिंग और जैव-तकनीक में प्रशिक्षित 90 फीसदी पेशेवर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीका चले जाते हैं, जिससे भारतीय प्रयोगशालाओं यानी शोध व विकास केंद्रों में अच्छी गुणवत्ता वाले शोधकर्ताओं की भारी कमी रहती है।

जनांकिकीय लाभांश

जहां ज्यादातर एशियाई, यूरोपीय और उत्तर अमरीकी देशों में बूढ़े लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहीं भारत 2025 तक सबसे युवा देश बनने को तैयार है और यहां आबादी की औसत आयु सिर्फ 26 साल के आसपास होगी। साल 2020 तक पूरी दुनिया की कामकाजी आबादी का 20 फीसदी हिस्सा भारत में रहेगा। दुनियाभर में पहले से भारत के सबसे ज्यादा प्रवासी हैं। लिहाजा, भारत के पास घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बड़ी आबादी का फायदा उठाने की जिम्मेदारी होगी। दुनिया के तमाम प्रमुख देशों में मौजूद भारत के प्रवासी भारत के 'सॉफ्ट पावर' का सबसे बड़ा हथियार हैं। भारत को

न सिर्फ इन लोगों की तरफ से देश में बड़े पैमाने पर भेजी गयी रकम का फायदा मिलता है, बल्कि विदेश में बसे भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा शोध और विकास के क्षेत्र में किये गये कामों से भी हमारे मुल्क को लाभ मिला है। हालांकि, मौजूदा हालात में प्रवासियों की तरफ से शोध और विकास के क्षेत्र में किये गये कामों का लाभ देश तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार की तरफ से गंभीर कोशिश किये जाने की जरूरत है। कभी दुनियाभर में चीन के प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन सफल चीनी कारोबारी बाद में अपने देश लौट गये और उन्होंने वहां की घरेलू स्टार्ट अप और शोध व विकास से जुड़े काम को जरूरी मदद मुहैया करायी, लेकिन भारत में ऐसा ट्रेंड नहीं के बराबर देखने को मिलता है। *ब्रेन ड्रेन* यानि प्रतिभा पलायन की चुनौती से निपटने के लिए कुछ अभियान निम्नलिखित है।

प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों का जश्न मनाने और भारत तथा उनकी रिहायश वाले देशों के बीच कड़ी स्थापित करने की इन लोगों की कोशिशों के लिए उन्हें सम्मानित करने की खातिर हर साल सम्मेलन आयोजित किया जाता है। बाद में प्रवासी भारतीय दिवस का इस्तेमाल भारत के विकास की कहानी को बताने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर किया जाने लगा है, ताकि भारत में निवेश करने के लिए भारतीय प्रवासियों का हौसला बढ़ाया जा सके।

पीआईओ और ओसीआई कार्ड का विलय

इन दोनों कार्ड के विलय का मकसद भारतीय मूल के लोगों की बिना किसी बाधा के भारत में आवाजाही सुनिश्चित करना है। साथ ही, हर नियमित अंतराल पर पुलिस स्टेशन गये देश में लंबे वक्त तक उनके ठहराव के लिए सहूलियत प्रदान करना है।

युवा प्रवासी दिवस

युवा भारतीय प्रवासियों और भारत की विकास की कहानी से उन्हें जोड़ने की अहमियत को देखते हुए सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत की। इसका मकसद दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही नयी पीढ़ी के प्रवासियों से जुड़ना है।

प्रवासी भारतीय केंद्र

150 से भी ज्यादा देशों में रहे भारतीय प्रवासी अब नयी दिल्ली के एक नये घर में ठहर सकते हैं, जिसे प्रवासी भारतीय केंद्र के नाम से जाना जाता है। वे अपनी जड़ों की तलाश कर सकते हैं, निवेश व सलाह हासिल कर सकते हैं, बड़े सभागारों में कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं और बिजनेस बैठकों में शिरकत कर सकते हैं।

वज्र विजिटिंग ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी

देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के मकसद से इस स्कीम को पेश किया गया है।

नॉ इंडिया प्रोग्राम

इस अभियान का मकसद 18-26 साल के प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत की जमीन, उनके पूर्वजों से रूबरू कराना, उनके विचार, उम्मीदें और अनुभवों को साझा करना है और उन्हें समकालीन भारत से करीबी तौर पर जोड़ना है।

ब्रेन गेन और *मेक इन इंडिया* जैसे अभियान का दुनियाभर में बसे युवा भारतीय प्रवासी समुदाय पर असर हुआ है। वे भारत लौटकर अपने देश में अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक विशेषज्ञता निवेश करने की तैयारी में हैं। वर्ष 2000 में आईआईटी मुंबई और दिल्ली के युवा स्नातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय नौकरी के तकरीबन 100 फीसदी ऑफर थे। आज भी इस तरह के ऑफर काफी अहम हैं, लेकिन बेहतरीन संस्थानों से छात्रों के विदेश पलायन के मामलों में काफी कमी आयी है।

ब्रेन गेन और मेक इन इंडिया जैसे अभियान का दुनियाभर में बसे युवा भारतीय प्रवासी समुदाय पर असर हुआ है। वे भारत लौटकर अपने देश में अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक विशेषज्ञता निवेश करने की तैयारी में हैं। वर्ष 2000 में आईआईटी मुंबई और दिल्ली के युवा स्नातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय नौकरी के तकरीबन 100 फीसदी ऑफर थे।

आरेख में वैसे छात्रों की संख्या बताई गयी है, जिन्होंने 2016 में विदेशी पेशकश स्वीकार की। साथ ही, आईआईटी बॉम्बे के 2012 के इसी तरह के आंकड़े हैं।

निष्कर्ष

युवा प्रवासी भारतीय, भारत के लिए बेहद अहम हैं। पिछले कुछ समय में अमरीका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने उच्च कौशल वाले भारतीयों के लिए वर्क वीजा में कटौती का ऐलान किया है। चूंकि इन देशों में इस तरह के वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय थे, लिहाजा इस तरह के किसी भी कदम से न सिर्फ उनके करियर संबंधी अवसरों पर असर पड़ेगा, बल्कि भारती प्रवासियों की रिहायश और ठहराव भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। सऊदी अरब ने भी एक ऐसी स्कीम पेश की है, जिसके तहत देश से बाहर के लोगों से कामकाज के घरेलू अवसरों को बचाने की बात है। यमन, सूडान, केन्या और इराक जैसे बाकि देशों में अक्सर भारतीय मूल के लोग युद्ध जैसी स्थिति में फंसने के बाद बेसहारा हो जाते हैं। हालांकि, भारतीय सरकार ने इन बेसहारा नागरिकों को वहां से निकालने में बेहद गंभीरता दिखायी है, लेकिन अब भी सरकार को इससे जुड़ी एक समर्पित और ठोस नीति बनाने की जरूरत है, ताकि युवा भारतीय कामकाजी आबादी को भी इस तरह के अति-प्रतिकूल हालात से बचाया जा सके। *गार* की जटिल प्रक्रिया के कारण कई प्रवासी भारतीय यहां की स्टार्ट अप में निवेश करने से परहेज करते हैं, लिहाजा इन नियमों को सही तरीके से प्रक्रियाबद्ध करने और आसान बनाने की जरूरत है। युवा आबादी देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपत्ति है। इसलिए देश की खास जरूरतों के मुताबिक उन्हें प्रशिक्षित करने की जरूरत है। मसलन प्रवासी कौशल विकास योजना जैसी स्कीम तैयार करने की दरकार है। ❑

संदर्भ

- आव्रजन 2014-15 पर विदेश मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट सीएआरआईएम इंडिया-डिवेलपिंग ए नॉलेज बेस फॉर पॉलिसीमेकिंग ऑन इंडिया-ईयू माइग्रेशन पेपर- नतालिया बुगा, जे बी मेयर
- आंकड़ों में विश्व पलायन: यूएनडीईएसए रिपोर्ट 2013
- अमरीका में भारतीय प्रवासी, माइग्रेशन पॉलिसी रिपोर्ट, एमपीआई 2015
- अमरीका जनगणना ब्यूरो रिपोर्ट 2015
- संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय पलायन रिपोर्ट 2015
- हाउ इंडिया कैन गो फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, भगवान चौधरी, सैनफ्रांसिस्को क्रॉनिकल, 23 सितंबर, 2015
- ग्रोइंग अप टुगेदर: द नेक्स्ट इवॉल्यूशन फॉर द इंडिया-सिलिकॉन वैली रिलेशनशिप, मैथ्यू हार्वर्ड प्रमोद पी हक, 5 जनवरी, 2016
- द मोस्ट पावरफुल इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट्स इन सिलिकॉन वैली, सैम्युअल गिब्स, द गार्डियन, 11 अप्रैल, 2014
- भारतीय प्रवासियों पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, 14 जनवरी, 2016

योग, युवा और स्वास्थ्य

ईश्वर एन आचार्य
राजीव रस्तोगी

योग उपचार, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन की औषधि रहित पद्धति भी है। स्वास्थ्य एवं रोग के विषय में इसके अपने सिद्धांत एवं अवधारणाएं हैं। यह स्वास्थ्य के प्रति सर्वांगीण दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसमें जीवन के दैहिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पक्ष आते हैं। अच्छे स्वास्थ्य एवं रोग निवारण के लिए स्वस्थ जीवन के विभिन्न सरल एवं सुगम तरीके बताए गये हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुरूप दैनिक जीवन में भी शामिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है

योग अब विश्वभर में लोकप्रिय है। इसने क्षेत्र, धर्म, जाति, समुदाय और राष्ट्रीयता की सीमाएं पार कर ली हैं। इसको स्वास्थ्य संवर्द्धन, रोग निवारण में इसकी विशिष्ट भूमिका के कारण एवं जीवन शैली से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर प्रभावी तरीके से काबू पाने में इसकी उपचारात्मक भूमिका के कारण दुनियाभर में जाना जाता है। योग आध्यात्मिक विषय भी है, जो शरीर एवं मस्तिष्क के बीच पूर्ण सामंजस्य बिठाने पर जोर देता है।

वर्तमान युग को तकनीकी प्रगति के लिए जाना जाता है, जिससे हमारा जीवन आरामदेह बन गया है। किंतु गलत जीवन शैली, पर्यावरणीय स्थितियों, प्रदूषण, आधुनिक कार्य संस्कृति आदि ने जीवन को कठिन बना दिया है। इसने जीवन के सभी आयामों अर्थात् शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक आयामों पर समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, जिससे व्यक्ति पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। योग जीवन के सभी क्षेत्रों में सही दिशा प्रदान करता है। योग की विशिष्टता यह है कि वह स्वास्थ्य सेवा की किसी भी प्रणाली के साथ चल सकता है। इस कारण अन्य चिकित्सा पद्धतियों तथा पारंपरिक चिकित्सा के विशेषज्ञ रोगियों को योग चिकित्सा का परामर्श दे सकते हैं।

27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 69वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा, ''योग हमारी प्राचीन परंपरा का अनमोल उपहार है। यह मन एवं शरीर की; विचार एवं कार्य की; संयम एवं पूर्णता की एकता का; मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य का; स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि अपने साथ, विश्व के साथ और प्रकृति के साथ एकाकार हो जाने की भावना की तलाश है। यह हमें अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर तथा चेतना उत्पन्न कर जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। आइए, हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने का प्रयत्न करें।''

प्रधानमंत्री ने योग को दुनियाभर में लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया क्योंकि योग को अच्छी तरह स्वीकार किया जाता है और योग की उपयोगिता का बेहतर तरीके से प्रयोग किया जा सकता है।

इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 177 देशों के समर्थन के साथ 21 जून को *अंतरराष्ट्रीय योग दिवस* घोषित कर दिया। अब पूरा विश्व पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ *अंतरराष्ट्रीय योग दिवस* को मना रहा है। भारत में आयुष मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों के उपयुक्त एवं सक्रिय सहयोग के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का दायित्व दिया गया। इस वर्ष हम तीसरा *अंतरराष्ट्रीय योग दिवस* मना रहे हैं।

योग क्या है?

योग एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसका उद्भव भारत में प्राचीन मनीषियों द्वारा हुआ था। योग सर्वांगीण जीवन पद्धति है, जिसकी जड़ें भारत की परंपरा एवं संस्कृति में गहरे तक व्याप्त हैं। ऋषियों और मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व इसका विकास किया था।

ईश्वर एन आचार्य केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली में निदेशक हैं। ईमेल: ccryu.goi@gmail.com
राजीव रस्तोगी केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नयी दिल्ली में सहायक निदेशक (प्राकृतिक चिकित्सा) हैं। ईमेल: rrastogi2009@gmail.com

लगभग सभी प्राचीन ग्रंथों में योग साहित्य प्राप्त होता है। मध्यकालीन, आधुनिक एवं समसामयिक साहित्य में भी योग के समृद्ध भंडार प्राप्त हुए हैं। पतंजलि का *योगसूत्र* (400 वर्ष ईसा पूर्व) पहला व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है, जिस पर विभिन्न टीकाकारों ने टीकाएं लिखी हैं। पतंजलि ने योग का आठ अंगों वाला मार्ग बताया है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। यह अष्टांग योग व्यक्ति के सभी पक्षों का ध्यान रखता है।

योग उपचार, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन की औषधि रहित पद्धति भी है। स्वास्थ्य एवं रोग के विषय में इसके अपने सिद्धांत एवं अवधारणाएं हैं। यह स्वास्थ्य के प्रति सर्वांगीण दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसमें जीवन के दैहिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पक्ष आते हैं। अच्छे स्वास्थ्य एवं रोग निवारण के लिए स्वस्थ जीवन के विभिन्न सरल एवं सुगम तरीके बताए गये हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुरूप दैनिक जीवन में भी शामिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

मनुष्य की बदलती हुई स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए शोधकर्ता एवं साधक अब योग पद्धतियों का व्यापक प्रयोग कर रहे हैं। योग पर अब पूरी दुनिया का ध्यान जा चुका है। स्वास्थ्य की रक्षा एवं संवर्द्धन के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न रोगों पर नियंत्रण के लिए भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में योग पद्धतियों के प्रति जागरुकता बढ़ रही है। तनाव के कारण उत्पन्न होने वाली व्याधियों एवं मनोदैहिक विकारों के निवारण एवं नियंत्रण के लिए विभिन्न योग गुरु और चिकित्सा पेशेवर योग से जुड़ी जीवन शैली के कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं।

योगाभ्यास से स्वास्थ्य बढ़ता है, रोगों का निवारण होता है, मनोदैहिक विकारों पर प्रभावी नियंत्रण होता है और चेतना के उच्च स्तर की बेहतर समझ बनती है। योग प्रणाली का दृष्टिकोण सर्वांगीण है और यह व्यक्ति का संपूर्ण उपचार करने में विश्वास करती है। योग की लोकप्रिय पद्धतियां, क्रियाएं, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, विश्राम की विधियां, बंध एवं मुद्राएं, ध्यान आदि हैं।

सूर्य नमस्कार

सूर्य नमस्कार योगाभ्यास का अत्यंत उपयोगी एवं लोकप्रिय अंग है। इसमें 12 शारीरिक मुद्राएं होती हैं, जिन्हें प्रातः काल सूर्य की ओर मुख करके किया जाता है। यह शरीर के समूचे तंत्रिका-ग्रंथि एवं तंत्रिका-पेशी प्रणाली में ऊर्जा का संचार करता है। इसका नियमित अभ्यास करने से ऑक्सीजन युक्त रक्त की संतुलित आपूर्ति एवं शरीर की सभी प्रणालियों में पूर्ण सामंजस्य सुनिश्चित होता है, जिससे मानव शरीर की संपूर्ण मनोदैहिक प्रणाली सुदृढ़ बनती है।

आसन

ये मुद्राओं के विशेष क्रम होते हैं, जो एक ही स्थान पर ठहरते हुए शरीर को तानकर मस्तिष्क एवं शरीर को स्थिर करते हैं। आसनों का उद्देश्य पेशियों को सामान्य दशा में लाना एवं पुष्ट बनाना होता है। शारीरिक मुद्राओं के प्रदर्शन पर नियंत्रण का मूल सिद्धांत केवल दैहिक नहीं बल्कि मनो-तंत्रिका-दैहिक होता है। आसन सहजता के साथ करने चाहिए और उतने ही समय तक करने चाहिए, जितना सहज लगे।

प्राणायाम

प्राणायाम करने से श्वास की गति पर नियंत्रण होता है, जिससे तंत्रिका आवेगों के प्रवाह का एक मार्ग बनता है। श्वास को सहजता के साथ लंबे समय तक रोककर रखना योग श्वसन की आवश्यक तकनीक है। इस श्वसन का मुख्य उद्देश्य स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करना होता है एवं उसके प्रभाव से मस्तिष्क के क्रियाकलाप को भी नियंत्रित एवं नियमित किया जाता है। यह ध्यान जैसी उच्चतर योग क्रियाओं में भी उपयोगी होता है।

ध्यान

मस्तिष्क जिस दिशा में स्थिर होता है, उसी दिशा में मस्तिष्क का सत्त एवं निर्बाध प्रवाह ध्यान कहलाता है। ध्यान का मूलभूत सिद्धांत आंतरिक चेतना विकसित करना होता है। इस क्रिया में मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है, जो बाहरी वस्तुओं से इंद्रियों को दूर करने से आरंभ होता है और बाद में बाहरी वातावरण को पूरी तरह भूला दिया जाता है। यह समाहित करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। नियमित रूप से ध्यान करने से चित्त केंद्रित करने की गहन क्षमता प्राप्त होती है, जिससे अधिक शारीरिक ऊर्जा, मानसिक क्षमता, रचनात्मकता, शांति, स्मृति, मेधा, अलौकिक शक्तियां एवं अंतर्दृष्टि जैसे लाभ प्राप्त होते हैं।

स्वास्थ्य क्या है?

स्वास्थ्य की अनेक परिभाषाएं हैं किंतु स्वास्थ्य की सर्वाधिक प्रचलित आधुनिक परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के संविधान की प्रस्तावना में दी गयी थी, जिसे 19 से 22 जून, 1946 के बीच अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन द्वारा स्वीकार किया गया था। (61 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा) जिस पर 22 जुलाई, 1946 को हस्ताक्षर किये गये थे (विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक दस्तावेज संख्या 2, पृष्ठ 100) और जिसे 7 अप्रैल, 1948 को लागू किया गया था। यह कहती है:

स्वास्थ्य का अर्थ रोग अथवा दुर्बलता नहीं होना भर नहीं है बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है।

योग एवं युवा

योग को स्वस्थ जीवन का विज्ञान एवं कला माना जाता है। यह उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, जो स्वस्थ रहना चाहता है और रोगों से दूर रहना चाहता है। वास्तव में योग से अन्य लाभों के अलावा आंतरिक कौशलों का विकास होता है और आत्मविश्वास का स्तर भी बढ़ता है। इसे जीवनशैली का पूर्ण परिवर्तन कहा जाता है।

योग अब युवाओं के लिए आवश्यकता बन चुका है। चाहे शिक्षा हो या रोजगार, युवा अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। योग उन्हें दैनिक जीवन की चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना करने वाले वास्तविक योगी में बदल सकता है। योग व्यक्तित्व के सभी पहलुओं अर्थात् शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पहलुओं का एक साथ विकास करता है और अंत में व्यक्ति को एक अलग व्यक्ति में बदल देता है। यह पूरी प्रणाली पर प्रभाव डालता है, एकाग्रता एवं धैर्य बढ़ाता है तथा साधक को शांतचित्त एवं गंभीर बनाता है, जो आज के दैनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है।

भारत 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या

वाला विशाल देश है और देश का विकास मुख्यतया उसके स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। यदि देश का स्वास्थ्य खराब होगा तो उसकी प्रगति धीमी पड़ सकती है क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रखने में ढेर सारी ऊर्जा और संसाधन लगाने होंगे। दूसरी ओर यदि देश के युवाओं का स्वास्थ्य अच्छा और सुदृढ़ होगा तो देश थके बगैर लंबी दूरी तक दौड़ सकता है। इसलिए युवाओं का स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।

योग स्वस्थ जीवन का विज्ञान होने के साथ ही आध्यात्मिक विज्ञान भी है। इसमें रोग प्रतिरोध तथा स्वास्थ्य संवर्द्धन दोनों की क्षमता है। योग की सर्वांगीण प्रकृति जीवन के सभी क्षेत्रों में तारतम्य स्थापित करती है और हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है। इसके नियमित अभ्यास से व्यवहार एवं दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन होता है तथा घर एवं समाज में साधक के अंतरवैयक्तिक संबंध सुधारने में सहायता मिलती है। विश्वभर में हुए विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों में योग के चिकित्सा संबंधी लाभों का भी पता चला है। शारीरिक एवं मनोदैहिक विकारों समेत जीवनशैली से जुड़े अनेक विकारों के निवारण तथा नियंत्रण की अपनी शक्ति के कारण आज योग एक बार फिर से लोकप्रिय हो गया है।

योग एवं अनुसंधान

क्लिनिकल अध्ययनों में विभिन्न मनोदैहिक तथा जीवनशैली से संबंधित विकारों से प्रभावी तरीके से निपटने की योग की चिकित्सकीय क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। अब योग को असंक्रामक रोगों की सुगम उपचार पद्धति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। दैनिक जीवन में जीवनशैली संबंधी सकारात्मक परिवर्तनों के माध्यम से इन रोगों से बचा जा सकता है। उपवास चिकित्सा, खाद्य आहार (डाइट) चिकित्सा, मृदा चिकित्सा, जल चिकित्सा, मालिश, वायु चिकित्सा जैसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ षट्कर्म, आसन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान जैसी योग क्रियाएं रोगमुक्त, स्वस्थ एवं सुखी जीवन सुनिश्चित करती हैं।

उच्च रक्तचाप, हृदय विकार, मधुमेह, तनाव, बेचैनी, अनिद्रा आदि आजकल युवाओं की कुछ सामान्य समस्याएं हैं। इस संबंध में हुए अध्ययनों से पता चला है कि कोरोनरी धमनी रोग (सीएडी) योग हृदय के प्रति खतरे को कम करता है। मनचंदा एवं अन्य ने वर्ष 2000 में दिखाया कि कोरोनरी धमनी रोग की गंभीर स्थिति वाले रोगी में योग जीवनशैली का हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाना संभव है। कंठशूल (एंजाइन), शारीरिक भार, वसा के स्तरों, व्यायाम से होने वाले तनाव के परीक्षण में इसके अनुकूल प्रभाव होते हैं और कोरोनरी बाधा के प्रसार को यह कम करता है। ऐसा लगता है कि योग युक्त जीवनशैली एथरोस्क्लीरोटिक जमाव को रोक देती है और इस प्रकार कोरोनरी बाइपास सर्जरी अथवा एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता कम हो जाती है। इसलिए योग युक्त जीवनशैली कोरोनरी धमनी रोग के गंभीर चरणों वाले रोगियों में में व्यावहारिक एवं किफायती उपचार है।

इसलिए योग के सिद्धांतों को दैनिक जीवन में जीवनशैली संबंधी कार्यक्रम के रूप में अपनाकर कोरोनरी धमनी रोग, उच्च रक्तचाप जैसे असंक्रामक रोगों को रोका जा सकता है और उनसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

युवाओं के स्वास्थ्य में भोजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आचार्य एवं रस्तोगी (2016) ने अपने शोधपत्र *योग: स्वस्थ एवं तनावमुक्त जीवन में संतुलन* में इस बात पर जोर दिया कि खानपान की आदतें स्वास्थ्यप्रद नहीं हैं। डिब्बाबंद भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड, अधिक कैलोरी वाले भोजन तथा धूम्रपान, मद्यपान, नशीले पदार्थ ने एवं विश्राम तथा व्यायाम की कमी ने हमें अधीर बना दिया है, जिससे विभिन्न मनोदैहिक रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया, कमर दर्द आदि पैदा होने लगे हैं। इन्हीं कारणों से मानसिक रोगों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही हैं। देखा गया है कि बड़ी संख्या में लोग अवसाद, पागलपन से पीड़ित हैं, जो मदिरा एवं नशीले पदार्थों से होने वाले विकार हैं। सुगम उपचार पद्धति के रूप में योग आसन, प्राणायाम, षट्कर्म, सूर्य नमस्कार एवं ध्यान जैसी अपनी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से शरीर एवं मस्तिष्क का प्रभावी उपचार करता है।

इसलिए योग युवाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्त करने वाला एवं राष्ट्र की प्रगति में सहभागी बनने का अवसर देने वाला माध्यम है। योग सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है एवं सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। योग क्रियाएं शरीर एवं मस्तिष्क को पूर्णतया स्वस्थ एवं एकाकार बनाने का सटीक माध्यम है। ❑

प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों की कार्य-निष्पादन समीक्षा

प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा व आवास समेत प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की गयी। *प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना* ने अब तक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 1.98 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया है। प्राथमिक ऊर्जा भण्डार में गैस का योगदान 8 प्रतिशत तक बढ़ गया है। सिटी गैस संवितरण नेटवर्क के तहत 81 शहर कवर्ड हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है जिसके तहत 18,452 गांवों में से 13,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है और यह कार्यक्रम 1000 दिनों के निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य को पूरा होने की दिशा में अग्रसर है। 2016-17 में 22 लाख से अधिक ग्रामीण बीपीएल परिवारों तक बिजली पहुंचाई गयी और इस अवधि के दौरान 40 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब संवितरित किये गये। मई 2014 से 2017 तक के दौरान 41 गीगावाट संचरण क्षमता बढ़ाई गयी और इसके साथ कुल अंतरक्षेत्रीय संचरण क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। विगत वित्तीय वर्ष में 24.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कुल नवीकरणीय सृजन क्षमता 57 गीगावाट्स से अधिक हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान सौर ऊर्जा में क्षमता वृद्धि 81 प्रतिशत के साथ अधिकतम रही। 4 रु. प्रति किलोवाट-घंटा के काफी निम्न दर के साथ सौर व पवन टैरिफ ने ग्रिड समानता को प्राप्त कर लिया है। *प्रधानमंत्री आवास योजना* के अंतर्गत योजना की प्रगति के प्रबोधन हेतु आईटी व स्पेस आधारित ऐप्लिकेशंस का काफी प्रयोग हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान 32 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को पूरा कर लिया गया है। ❑

Mc Graw Hill Education

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका

UPSC सिविल सेवा परीक्षा

की तैयारी के लिए आपके सशक्तिकरण हेतु उपयोगी पुस्तकें

₹ 615/-

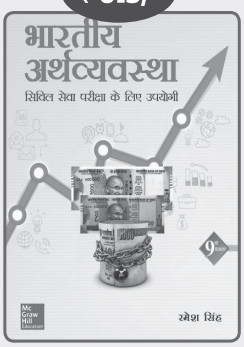

ISBN: 9789352606177

₹ 525/-

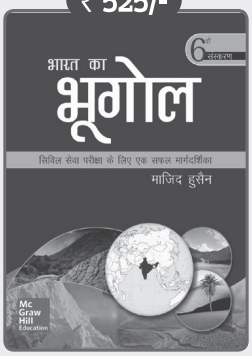

ISBN: 9789352605408

₹ 275/-

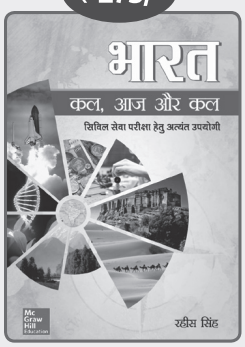

ISBN: 9789352604708

₹ 595/-

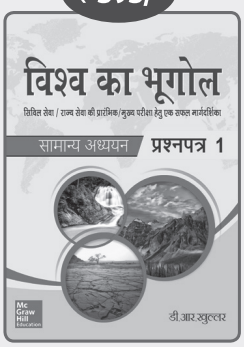

ISBN: 9789352602452

शीघ्र प्रकाशित

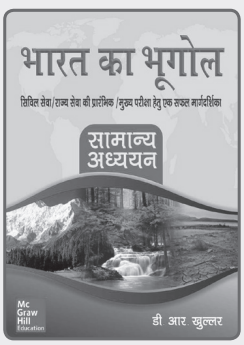

ISBN: 9789352605699

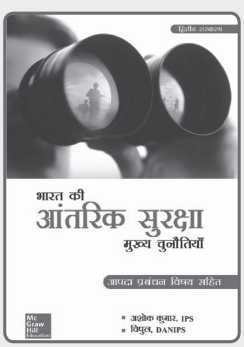

ISBN: 9789352606160

₹ 395/-

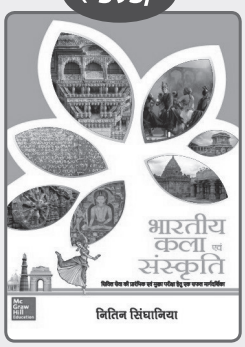

ISBN: 9789352602308

₹ 395/-

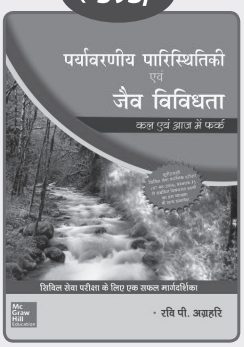

ISBN: 9789352602322

₹ 445/-

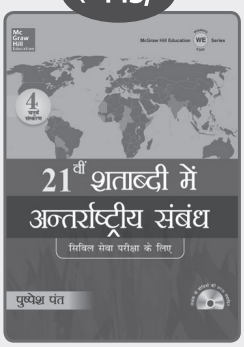

ISBN: 9789339214128

₹ 295/-

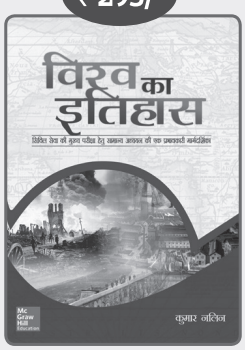

ISBN: 9789352602292

₹ 265/-

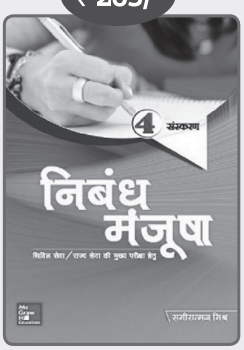

ISBN: 9789352601660

₹ 465/-

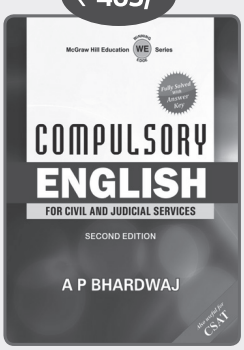

ISBN: 9781259064081

Prices are subject to change without prior notice.

मैक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बी-4, सैक्टर 63, जनपद गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201 301

SHIPPING FREE Above ₹ 500/-

टोल फ्री नं०: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

संपर्क करें@ /McGrawHillEducationIN /MHEducationIN /company/mcgraw-hill-education-india /McGrawHillEducationIndia

युवा सशक्तीकरण और योग

ईश्वर वी बसवरेड्डी

योग ऐसी चिकित्सा है जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करता है, शरीर को मजबूत बनाता है, मन को शांत करता है। व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध करता है, तनाव दूर करता है और श्वसन के सही तरीका सिखाता है। शारीरिक मुद्रा में सुधार करता है, हर परिस्थिति से मुकाबला करने का कौशल प्रदान करता है तथा दृढ़ संकल्प एवं एकाग्रता के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक श्रम युवाओं को वर्तमान के प्रति जागरूक करते हैं और शरीर-मन की निरंतरता में मौजूद भावनाओं के संबंध में उन्हें सचेत करने का प्रयास करते हैं

युवा सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों और युवाओं को अपने फैसले स्वयं लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके माध्यम से वे अपनी स्थिति को देख-समझकर, संसाधनों तक अपनी पहुंच में सुधार करते हैं और अपने विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार के माध्यम से अपनी चेतना का कायाकल्प करने का प्रयास करते हैं। युवा सशक्तीकरण का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। युवा सशक्तीकरण कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से युवा सशक्तीकरण प्राप्त किया जा सकता है।

युवा सशक्तीकरण युवा विकास से भिन्न है क्योंकि विकास व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि सशक्तीकरण उन उपायों से संबंधित होता है जो युवाओं और समुदायों के बीच स्वायत्तता और आत्मनिर्णय को बढ़ाने में मदद देते हैं जिससे ये समूह अपने अधिकार क्षेत्र में जिम्मेदारपूर्ण और अपने तरीके से अपने हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें।

युवा सशक्तीकरण के सिद्धांत के तीन अंग हैं: व्यक्तिगत सशक्तीकरण, संगठनात्मक सशक्तीकरण और सामुदायिक सशक्तीकरण।

व्यक्तिगत सशक्तीकरण: इसके तहत युवाओं या वयस्कों में कौशल को विकसित करते हुए और उनकी दक्षता में सुधार करते हुए संगठनों और समुदायों के कल्याण हेतु सहयोग करने के लिए जागरूकता विकसित की जाती है।

संगठनात्मक सशक्तीकरण: इसमें ऐसी संस्थाओं का सशक्तीकरण किया जाता है जो युवाओं या वयस्कों को अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती हैं और उनसे लाभ हासिल करती हैं, उन्हें सेवा प्रावधानों के विकल्प प्रदान करती हैं, साथ ही नीतिगत निर्णय लेते हुए उन्हें प्रभावित करती हैं।

सामुदायिक सशक्तीकरण: समुदाय की बेहतरी, जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले खतरों के निवारण तथा स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी के प्रयास द्वारा समुदायों का सशक्तीकरण किया जाता है।

युवा वर्ग संबंधी सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं

ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिनसे इंगित होता है कि हमारे समाज में युवा वर्ग व्यक्तिगत पसंद, पर्यावरणीय प्रभावों और जीवनशैली में बदलाव के कारण कई संचारी और गैर-संचारी विकारों से प्रभावित होते हैं। युवाओं की समस्याएं केवल सामाजिक और आर्थिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। पीड़ादायक संबंधों और अकेलेपन के कारण वे मादक पदार्थों और शराब के व्यसनी हो जाते हैं। युवाओं की अन्य समस्याओं में सहकर्मियों का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारी और काम का बोझ शामिल हैं। उचित परामर्श या देखभाल की कमी के चलते कई बार युवा अपने जीवन का अंत भी कर देते हैं। युवाओं की आम स्वास्थ्य समस्याएं निम्नलिखित हैं:

- अधिक वजन और मोटापा
- तनाव
- चिंता और अवसाद
- युवाओं में हिंसा
- आत्महत्या की प्रवृत्तियां
- तंबाकू का सेवन
- शराब और मादक पदार्थों की लत
- गैर-संचारी रोग (एनसीडी)

लेखक भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। ईमेल: ibasavaraddi@yahoo.co.in

युवा सशक्तीकरण के लिए योग

आसन और प्राणायाम विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करते हैं। इनसे शरीर की ताकत बढ़ती है, शरीर से विषाक्त पदार्थों का खात्मा होता है, देह और मन को आराम मिलता है, तनाव दूर होता है और सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच संतुलन कायम होता है। इस प्रकार विभिन्न गैर-संचारी रोग समाप्त होते हैं। इस प्रकार आसन और प्राणायाम निम्नलिखित में सहायता प्रदान करते हैं:

- तनाव और चिंता से राहत
- सकारात्मक ऊर्जा और मनोदशा को बढ़ावा देना
- रक्तचाप को सामान्य करने में सहायता
- मांसपेशियों को चुस्त करते हुए पाचन को दुरुस्त करना
- शांति और सुख की भावना उत्पन्न करना
- तनाव को दूर करना जिससे उसके गंभीर होने का खतरा कम होता है
- हृदय की गति और श्वास को मंद करना, रक्तचाप सामान्य करना
- ऑक्सीजन का अधिक कुशलता से प्रयोग
- अधिवृक्क ग्रंथियां (एडरेनल ग्लैंड्स) द्वारा कॉर्टिसोल कम बनाना
- प्रतिरोधक क्षमता में सुधार

तनाव दूर करने के लिए योग

तनाव से ऑटोमॉनिक नर्वस सिस्टम असंतुलित होता है। पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम कम काम करता है जबकि सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक काम करता है। तनाव तब महसूस होता है जब अनुभूत मांग और उस मांग को पूरा करने की क्षमता, इन दोनों के बीच तालमेल नहीं होता। इसमें बाहरी बाहरी स्थितियों के प्रति भावनात्मक और मानसिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं। जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, चाहे वह तनाव असली हो या अनुभूत, उसका नर्वस सिस्टम सिंपेथेटिक की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में एपिनेफ्राइन का स्राव कम होता है और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम में गिरावट होती है लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्राव सामान्य से अधिक होना जारी रहता है। ऐसे मामले में, कई बार व्यक्ति को यह महसूस भी नहीं होता कि वह तनावपूर्ण स्थिति में हैं।

मोटापा के उपचार के लिए सूर्य नमस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्य नमस्कार एक पूर्ण अभ्यास है क्योंकि इस अभ्यास का अंत:स्रावी और तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) पर एक अनूठा प्रभाव पड़ता है। चयापचय असंतुलन को दुरुस्त करने में यह मदद करता है जो मोटापे का कारण होते हैं। मोटापे के लिए प्राणायाम की भस्त्रिका, कपालभाती और सूर्यभेदन विधियों का सुझाव दिया जाता है जिनमें शरीर का संतुलन बनाया जाता है। ये चयापचय में संतुलन को बरकरार रखने में सहायता करती हैं।

योग से पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम संतुलित होता है। जब हमारे शरीर या मस्तिष्क को तनाव का खतरा होता है, चाहे वह सकारात्मक या नकारात्मक, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम या हमारी *आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली* सक्रिय हो जाती है। *फ्लाइट या फाइट* प्रतिक्रिया का परिणाम वासोकोनट्रक्शन होता है जिससे एक्सट्रिमिटीज और पाचन तंत्र में रक्त प्रवाह कम हो जाता है ताकि व्यक्ति जीवित रह सके।

यह भी पाया गया है कि कि योग से हाइपोथैलेमिक-पिट्यूटरी-एड्रेनल एक्सिस (एचपीए) और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम संतुलित होता है जिससे व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। योग से मस्तिष्क को आराम मिलता है और मन शांत रहता है जिससे रक्तचाप, धड़कन और श्वसन दर कम होते हैं क्योंकि तनाव के दौरान कॉरटिसोल और एसिटाइलकोलाइन का स्तर बढ़ जाता है और योग से इनके स्तर में कमी आती है। नतीजतन, यह मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, दबाव और अतिसंवेदनशीलता को कम करता है जो मनोदैहिक समस्याओं को बढ़ाते हैं। यह भी पाया गया है कि योग के कारण मैलाटोनिन के स्तर में वृद्धि होती है, मनोवैज्ञानिक और हृदय श्वसन में सुधार होता है।

योग से व्यसन से मुक्ति

योग ऐसी चिकित्सा है जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करता है, शरीर को मजबूत बनाता है, मन को शांत करता है। व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध करता है, तनाव दूर करता है और श्वसन के सही तरीका सिखाता है। शारीरिक मुद्रा में सुधार करता है, हर परिस्थिति से मुकाबला करने का कौशल प्रदान करता है तथा दृढ़ संकल्प एवं एकाग्रता के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक श्रम युवाओं को वर्तमान के प्रति जागरूक करते हैं और शरीर-मन की निरंतरता में मौजूद भावनाओं के संबंध में उन्हें सचेत करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी मुद्राएं होती हैं जैसे पीछे की तरफ झुकाव, जिनसे शरीर खुलता है और व्यक्ति को सोलर प्लेक्सेस एरिया में अनुभव होने वाली भावनाओं का एहसास होता है।

मोटापे से छुटकारा

योग में न केवल उचित आसनों का अभ्यास कराया जाता है और सांस लेने की तकनीक सिखायी जाती है, बल्कि इसमें संतुलित आहार पर भी जोर दिया जाता है।

कभी-कभी मोटे लोगों को जोड़ों के दर्द की परेशानी होती है। योग शरीर की मुद्रा को सुधारने के साथ जोड़ों के तनाव को कम करता है और वे अधिक वजन झेलने लायक बनते हैं। यह शरीर की ताकत और लचक तथा संतुलन को बढ़ाता है। शरीर तंदुरुस्त रहता है और मन शांत, तो व्यक्ति बेहतर महसूस करता है। नियमित योग करने से मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति पर अलग ही प्रभाव पड़ता है। योग मोटापा कम करने की अन्य तकनीकों की तुलना में स्थायी तरीका है। मोटापा के उपचार के लिए सूर्य नमस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्य नमस्कार एक पूर्ण अभ्यास है क्योंकि इस अभ्यास का अंत:स्रावी और तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) पर एक अनूठा प्रभाव पड़ता है। चयापचय असंतुलन को दुरुस्त करने में यह मदद करता है जो मोटापे का कारण होते हैं। मोटापे के लिए प्राणायाम की भस्त्रिका, कपालभाती और सूर्यभेदन विधियों का सुझाव दिया जाता है जिनमें शरीर का संतुलन बनाया जाता है। ये चयापचय में संतुलन को बरकरार रखने में सहायता करती हैं।

युवा और गैर संचारी रोग

युवावस्था जीवन का समय होता है जब एक व्यक्ति न बच्चा होता है और न ही पूर्ण वयस्क। ताजगी, उत्साह, भावनाओं का आलोड़न आदि युवावस्था के लक्षण हैं।

गैर-संचारी रोग में कई स्थितियां शामिल हैं जो व्यवहार और जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। भारत, विशेष रूप से युवा वर्ग, पोषण संबंधी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और यह उच्च रक्तचाप, तनाव, मधुमेह और फेफड़ों के बीमारियों जैसे गंभीर गैर-संचारी रोगों को बढ़ावा देता है।

गैर संचारी रोगों को दूर करने के लिए योग

आजकल की जीवनशैली गैर संचारी रोगों का मुख्य कारण है जिनमें तंबाकू का सेवन, गतिहीन जीवनशैली, नियमित व्यायाम की कमी, अस्वस्थकर आहार और गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव शामिल हैं। कई गैर संचारी रोगों में पेट में जबरदस्त जलन और तनाव पाये हैं और इसमें योग बेहद फायदेमंद पाया जाता है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि योग अभ्यास से शरीर पर अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं जिनमें रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और कार्डियोवस्कुलर सिस्टम को स्वस्थ बनाये रखना शामिल है। योग के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं क्योंकि इससे व्यक्ति में सतर्कता बढ़ती है।

योग के जरिए आप अपने आप से जुड़ते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपकी बीमारी क्यों और किस प्रकार शुरू हुई और आप उसके साथ काम कर सकते हैं। एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं। योग बताता है कि हम अपने आस-पास की दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, साथ ही विभिन्न परिदृश्यों और चुनौतियों से निपटने का तरीका भी सिखाता है। अपने मन को शांत करते हुए अपने आप से जुड़ने से व्यक्ति वर्तमान के निकट आता है। व्यक्ति का तनाव कम होता है, व्यस्त जीवन के दबाव कम होते हैं और गैर संचारी रोग हमारे शरीर से दूर भागते हैं। ❑

संदर्भ

- Zimmerman, Marc A. and Julian Rappaport. "Citizen Participation, Perceived Control, and Psychological Empowerment." American Journal of Community Psychology. Vol 16, No. 5, 1988.
- Zimmerman, Handbook, 2000.
- Ibid., Meredith Minkler, "Improving Health through Community Organization," Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Education. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1990.
- The solar plexus is located in the stomach area. In Yoga physiology there are seven chakras or energy centers in the body. These are thought to equate to levels of consciousness and our emotional capacities.

व्यापक प्रतिरक्षा कार्यक्रम के तहत न्यूमोकॉकल कन्ज्यूगेट वैक्सीन की शुरुआत

व्यापक प्रतिरक्षा कार्यक्रम (यू.आई.पी) के तहत न्यूमोकॉकल कंज्यूगेट वैक्सीन (पी.सी.वी.) की शुरुआत हाल ही में की गई।

पी.सी.वी. बच्चों को कई तरह की न्यूमोकॉकल बीमारियों मसलन निमोनिया, मैनिंजाइटिस से बचाता है। हाल ही में कार्यक्रम के पहले चरण के दौरान हिमाचल प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश के हिस्सों में लगभग 21 लाख बच्चों को यह वैक्सीन दिया गया। अगले वर्ष मध्य प्रदेश व राजस्थान में इस कार्यक्रम को शुरू कर इसे और आगे ले जाया जाएगा और तत्पश्चात देश के अन्य हिस्सों में चरणबद्ध रूप से इसे विस्तारित किया जाएगा।

भारत में पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु अन्य किसी संक्रामक बीमारी की तुलना में निमोनिया की वजह से अधिक होती है। यू.आइ.पी. के तहत सभी राज्यों में 2015 तक शुरू किया गया पंचसंयोजक (पेंटावेलेंट) वैक्सीन हेमोफिलस इंफ्लुएंजा टाइप बी निमोनिया से बचाता है। अब यूं. आई.पी के तहत शुरू पी.सी.वी न्यूमोकॉकल निमोनिया से होने वाली बाल-मृत्यु को कम करेगा। यह निमोनिया की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या भी कम करेगा और इस तरह परिवार के आर्थिक बोझ व देश के स्वास्थ्य लागत बोझ को भी कम करेगा।

न्यूमोकॉकल बीमारी भारत सहित विश्व भर में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण है जिसे वैक्सीन से रोका जा सकता है द्य भारत में इस आयु-समूह के भीतर होने वाली मृत्यु विश्व भर में होने वाली मृत्यु का 20 है। वर्ष 2010 में भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गंभीर निमोनिया मामलों से होने वाली मृत्यु के लगभग 20 प्रतिशत और निमोनिया संबंधी मृत्यु के 30 प्रतिश की वजह न्यूमोकॉकल निमोनिया है। अत: पी.सी.वी की वजह से देश में बीमारियों के बोझ में काफी हद तक कमी आएगी। ❑

IAS **IGNITED MINDS** PCS

IGNITING HUMAN MINDS · IGNITED MINDS

दर्शनशास्त्र, एथिक्स (G.S. Paper-IV) एवं निबंध के प्रशिक्षण का प्रामाणिक एवं विश्वसनीय संस्थान

Chief Mentor: Amit Kumar Singh

Our Upcoming Batches

दिल्ली केन्द्र

नया बैच प्रारम्भ	नया बैच प्रारम्भ
दर्शनशास्त्र	**ETHICS**
27 JUNE 4:00 PM	**29 JUNE 7:30 PM**

Allahabad Centre. Philosophy 19th June 6.30 PM

A -2, 1st Floor, Comm. Comp., Near Mukherjee Nagar, Delhi-09

PH. 011-27654704, 8744082373, 9643760414

स्वास्थ्य की कसौटी पर युवा

आशुतोष कुमार सिंह

देश के युवाओं में मोटापा, कुपोषण, अन्य पोषण संबंधी बीमारियां, एनीमिया, तंबाकू एवं शराब की लत, मानसिक समस्याएं लगातार बढ़ी है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि युवाओं को सेहत के प्रति सजग किया जाए। उनकी समस्याओं को कॉलेज, कार्यालय एवं घरेलु स्तर पर सुना जाए और उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया जाए। ऐसे में यह भी जरूरी है कि देश के युवा खुद भी अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15-29 आयु वर्ग के किशोर-वयस्क को युवा माना गया है। इस लिहाज से भारत में युवाओं की बड़ी आबादी निवास कर रही है। इसमें 15-29 आयु-वर्ग के जिम्मे राष्ट्र-निर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किशोरावस्था में युवा इंटर कॉलेज से निकलकर विश्वविद्यालय की दहलीज तक पहुंच चुका होता है। किशोरावस्था से निकलकर जैसे ही वो रोजगार की ओर अपना दिमाग लगाता है, उसके दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है। उसे कई तरह की परेशानियां नजर आने लगती है। उसे अब हर हाल में नौकरी दिखती है। (एक सामान्य ट्रेंड) ऐसे में जिनको रोजगार नहीं मिल पाता उनकी मन: स्थिति नकारात्मक भावों की ओर अग्रसर होने लगती है। इस स्थिति के कारण कई तरह की बीमारियों के गिरफ्त में युवा आ जाता है। इस आलेख में युवाओं की उपरोक्त मनोदशा को ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य के लेखा-जोखा पर हमलोग ध्यान केंद्रित करेंगे।

युवाओं में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं

ए. महेंद्रन ने अपने शोध पत्र (विजिबल एंड इनविजबल हेल्थ प्रोबल्मस ऑफ यूथ इन इंडिया-पेसिफिक बिजनेस रीव्यू इंटरनेशनल-वर्ष 8, अंक 4, अक्टूबर 2015) में उल्लेख किया है कि 10 से 30 फीसद युवा विभिन्न तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पोषण संबंधित समस्या, मधुमेय, तनाव, तपेदिक, धूम्रपान और शराब की लत, अवसाद, तनाव एवं अनिद्रा जैसी बीमारियों से वे जूझ रहे हैं। श्री महेन्द्रन अपने शोध में यह भी कहते हैं कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किया है लेकिन युवाओं को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम अभी तक सार्थक तरीके से नहीं बन पाया है।

जीवनशैली जनित बीमारियां

आज की शहरी कार्यशैली में पीठदर्द, मोटापा, अधकपारी, तनाव, अवसाद आदि बीमारियां तेजी से घर करती जा रही हैं। इसके पीछे युवाओं के काम करने, रहने और खाने-पीने का तरीका एक प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 10 से 24 आयु वर्ग की करीब 23 लाख युवा आबादी हर साल असामायिक मौत की शिकार हो जाती है। इसके साथ ही ऐसी युवा आबादी की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है, जो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, जिन्हें कभी प्रौढ़ावस्था की समस्या समझा जाता था।

हृदय रोगों से पीडित भारतीयों की बढ़ती तादाद के बीच जीवनशैली व खान-पान की आदतों में बदलाव आज की जरूरत बन गयी है। चिकित्सकों का कहना है कि युवाओं को समय रहते ही खानपान को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वरना अगले 10 सालों में देश की आबादी लगभग 20 फीसदी लोगों को हृदय से संबंधित बीमारी से ग्रसित होने की आशंका है। पहले जहां 30 से 40 वर्ष तक के बीच हृदय की समस्याएं आंकी जाती थीं, आज यह 20 वर्ष से कम उम्र के लोगों में भी होने लगी है। आगामी 5 से 10 वर्षों में भारतीय आबादी

लेखक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यकर्ता तथा समाचार-विचार पोर्टल www.swasthbharat.in के संपादक हैं। बालिका स्वास्थ्य जागरूकता पर 'स्वस्थ बालिका: स्वस्थ समाज' का संदेश लेकर हाल ही में देश के सभी राज्यों में लगभग 20,000 किलोमीटर की *स्वस्थ भारत यात्रा* पूरी की है। स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं में अनेक आलेख लिखने के अलावा वह कंट्रोल एमएमआरपी (मेडिसिन मैक्सिमम रिटेल प्राइस) तथा जेनरिक लाइए, पैसा बचाइए' जैसे अभियानों के माध्यम से दवा कीमतों व स्वास्थ्य सुविधाओं पर जन जागरूकता के लिए काम करते रहे हैं।। ईमेल: forhealthyindia@gmail.com

तालिका 1: व्यस्कों में पोषण की स्थिति (उम्र 15-49)

वर्ग	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे: चरण 4			चरण 3
	शहरी	ग्रामीण	कुल	कुल
महिला जिसका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सामान्य से कम है (बीएमआई <18.5 केजी/एम^2)14 (%)	15.5	26.7	22.9	35.5
पुरूष जिसका बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम है (बीएमआई < 18.5 केजी/एम2) (%)	15.3	23.0	20.2	34.2
महिला जो जिसका वजन सामान्य से ज्यादा है (बीएमआई ≥ 25.0 केजी/एम2)14 (%)	31.3	15.0	20.7	12.6
पुरूष जिसका वजन सामान्य से ज्यादा है (बीएमआई ≥ 25.0केजी/एम2) (%)	26.3	14.3	18.6	9.3

का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा इससे प्रभावित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 तक भारत में मौतों और विकलांगता की सबसे बड़ा वजह हृदय से संबंधित रोग ही होंगे। एक अनुमान के अनुसार, भारत में 10.2 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। पूरी दुनिया में हर साल 1.73 करोड़ लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से हो जाती है और यदि हालातों पर काबू नहीं किया गया तो 2020 तक हर तीसरे व्यक्ति की मौत हृदय रोग से होगी।

शारीरिक और मानसिक समस्याएं

मानव के स्वभाव पर उसके खान-पान का असर पड़ता है। वो कितना पोषणयुक्त भोजन लेता अथवा नहीं ले पाता है का असर उसके जीवन-चक्र पर रहे बिना नहीं रह सकता। आंकड़े बताते हैं कि छोटे कद का होने के पीछे पोषण का अभाव एक प्रमुख कारण है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा 2001-06 तक कराए गये सर्वे में यह बात निकल आई है कि 10-18 आयु वर्ग की आधी आबादी का पोषण आश्यकता से कम हुआ है। इस आंकड़े को सही साबित करते हुए एक और शोध में कहा गया कि 10-24 आयु-वर्ग के 56-.4 से 68.5 प्रतिशत लोगों में पोषण का अभाव पाया गया। इसी तरह एक विद्यालयी स्तर पर किये गये शोध से मालूम चला है कि 38.8 फीसद लड़के और 36.9 फीसद लड़कियां मानक से कम विकसित हैं। सामुदायिक स्तर पर किये गये एक शोध में बताया गया कि 51.7 फीसद किशोर का दैहिक विकास मानक से कम है। ग्रामीण भारत में अल्प पोषण के कारण एनीमिया का फैलाव खूब है, खासतौर से किशोरी माताओं में। जिसके कारण गर्भ गिरने की आशंका बढ़ जाती है, नवजात का वजन कम हो जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में स्पष्ट निर्देश हैं। साथ ही कई अन्य योजनाएं भी संचालित किये जा रहे हैं जिसके सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं।

सामान्य मानसिक स्वास्थ्य

वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में युवाओं के ऊपर करिअर बनाने एवं उसे स्थायी बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती ने युवाओं में तमाम तरह की मानसिक उलझनों को जन्म दिया है। कम से कम 20 फीसद युवा ऐसे हैं जो कभी न कभी अवसाद, मन-विचलन, आत्महत्या करने का मन जैसी स्थिति से गुजरे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। वहीं भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 1 लाख 36 हजार लोग अपनी जीवन लीला खुद से खत्म कर लेते हैं। एक आधिकारिक रपट के अनुसार 15-29 आयु वर्ग में आत्महत्या करने की प्रवृति लगातार बढ़ रही है। 2002 से 2011 तक का अध्ययन कर एक शोध में बताया गया है कि 3.73-3.96 फीसद की दर से प्रत्येक वर्ष युवाओं में यह प्रवृति बढ़ी है। शोध में यह भी बताया गया है कि भारत में आत्म हत्या करने वाले 40 फीसद लोग 30 वर्ष से कम के हैं।

मोटापा एवं अधिक वजन

अधिक वजन एवं मोटापा भी एक तरह से कुपोषण का ही प्रकार है। अपने देश में युवाओं में यह स्थिति बढ़ती जा रही है। 9 शोधों के आधार पर 2012 में तैयार की गयी रपट में यह बताया गया है कि 12.6 फीसद बच्चों का वजन ज्यादा पाया गया। 2001-2012 तक हुए अध्ययनों का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि 10-19 आयु वर्ग में ज्यादा वजन वाले 9.9 से 19.9 फीसद तक पाए गये। मोटापा एवं अधिक वजन की समस्या वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। सोनिया जगदेशन की रपट बताती है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों में बच्चों के मुकाबले किशोरों में मोटापा एवं अधिक वजन की समस्या ज्यादा है। भारतीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 (आईएफएचएस-4) की रपट में पोषण संबंधित आंकड़ों को दिया गया है। इस सर्वे के अनुसार 22.9 फीसद ऐसी महिलाएं हैं जिनका शरीर भार अनुपात (बीएमआई) सामान्य से कम है। शहरी महिलाओं में यह स्थिति 15.5 फीसद है तो ग्रामीण महिलाओं में यह 26.7 फीसद है। आईएफएचएस-3 के सर्वे में देश की 35.5 फीसद महिलाओं का बीएमआई सामान्य से कम था। वहीं आईएफएचएस-4 (2015-16) में 20.2 फीसद पुरूषों की बीएमआई सामान्य से कमतर पाई गयी। शहरी क्षेत्रों में 15.3 फीसद तो ग्रामीण क्षेत्र में 23.0 फीसद पुरूषों की बीएमआई सामान्य से कमतर पाई गयी। जबकी आईएफएचएस-3 (2005-6) सर्वे में 34.2 फीसद पुरूषों की बीएमआई सामान्य

तालिका 2: बच्चों एवं वयस्कों में एनीमिया की स्थिति

बच्चे (आयु: 6-59 महीना) जो एनेमिक हैं (<11.0 जी/डीएल) (%)	55.9	59.4	58.4	69.4
सामान्य महिला आयु 15-49 वर्ष जो एनेमिक है (<12.0 जी/डीएल) (%)	50.9	54.3	53.1	55.2
प्रिग्नेंट महिला 15-49 वर्ष जो एनेमिक है (<11.0जी/डीएल (%)	45.7	52.1	50.3	57.9
सभी महिलाएं 15-49 जो एनेमिक हैं	50.8	54.2	53.0	55.3
पुरूष 15-49 वर्ष जो एनेमिक है (<13.0 जी/डीएल) (%)	18.4	25.2	22.7	24.2

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 (2015-16)

से कमतर थी। (तालिका-1 देखें) अपने देश की 20.7 फीसद महिलाएं एवं 18.6 फीसद पुरूषों का वजन सामान्य से ज्यादा है। जबकि चरण 3 में ज्यादा वजन की महिलाएं 12.6 फीसद एवं पुरूष 9.3 फीसद थे। (तालिका 1 देखें)। इससे यह भी साफ हो गया है कि भारतीयों को अपने पारंपरिक भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

रक्ताल्पता

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 के अनुसार रक्ताल्पता एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आई है। 15-49 आयु वर्ग (नॉन प्रिगनेंट) की 53.1 फीसद रक्ताल्पता की शिकार महिलाओं में 50.9 फीसद शहरी एवं 54.3 फीसद ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। वहीं 22.7 फीसद पुरूष रक्ताल्पता (एनीमिया) के शिकार हैं। (देखें तालिका-2)

मधुमेह

बीमारियों की जड़ मानी जाने वाली मधुमेह की बीमारी मौजूदा समय में प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है हमारे देश में, खास तौर पर शहरों में इसका प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या चार करोड़ से अधिक है जो विश्व की कुल पीड़ितों की आबादी का 15 प्रतिशत है। यह रोग विश्व की 6.6 फीसदी जनसंख्या को अपने चपेट में ले चुकी है जिसमें युवाओं की एक अच्छी खासी तादाद है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने युवाओं में मधुमेह के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए 18 अप्रैल 2017 को कहा कि नये भारत के निर्माण में युवा शक्ति की असीम क्षमता को देखते हुए युवाओं में मधुमेह को नियंत्रित करने पर ध्यान देना राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

उच्च रक्तचाप

भारत के करीब 20 करोड़ वयस्कों को उच्च रक्तचाप है और विश्व भर में इससे पीड़ित लोगों की तादाद बढ़कर 1.13 अरब तक पहुंच गयी है। *इंपीरियल कॉलेज*, लंदन के वैज्ञानिकों की अगुवाई में किये गये अध्ययन में देखा गया कि दुनिया भर में पिछले 40 वर्षों में उच्च रक्तचाप के मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गयी है। द *लैंसेट जर्नल* में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि दुनिया भर में रक्तचाप से पीड़ित कुल लोगों में से आधे एशिया में रहते हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन में करीब 22.6 करोड़ लोगों को उच्च रक्तचाप है। अनुसंधानकर्ताओं ने हर देश में वर्ष 1975 से 2015 के बीच रक्तचाप में आये अंतर का अध्ययन किया। उन्होंने साथ ही पाया कि वर्ष 2015 में अधिकतर देशों में महिलाओं की तुलना में अधिकतर पुरुष उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं।

तालिका 3: वयस्कों (15-49 वर्ष) में तंबाकू एवं शराब का सेवन

महिला जिसने किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन किया है (%)	4.4	8.1	6.8	10.8
पुरुष जिसने किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन किया है (%)	38.9	48.0	44.5	57.0
महिला जिसने शराब का सेवन किया है (%)	0.7	1.5	1.2	2.2
पुरुष जिसने शराब का सेवन किया है (%)	28.7	29.5	29.2	31.9

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 फैक्टशीट

अध्ययन में करीब दो करोड़ लोगों के रक्तचाप के आंकड़ों को शामिल किया गया है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि उच्च आय वाले देशों में रक्तचाप में तेजी से गिरावट आयी है, वहीं कई निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों खासकर अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों में इसमें वृद्धि दर्ज की गयी है। खान-पान में आये बदलाव के कारण भी उच्चरक्तचाप की बढ़ता जा रहा है। निम्न उपायों पर ध्यान देकर इससे बचा जा सकता है।

स्वास्थ्य खराब करने वाली अन्य आदतें

तंबाकू सेवन-वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि किशोरावस्था में ही लड़कों को इसकी लत लग जाती है। वर्तमान में तकरीबन 15 करोड़ किशोर वैश्विक स्तर पर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण 4 के अनुसार भारत में 6.8 फीसद ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन किया है। वहीं 4.4 फीसद शहरी क्षेत्र एवं 8.1 फीसद ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने तंबाकू का सेवन किया है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चरण 3 के परिणाम से बेहतर है, तब 10.8 फीसद महिलाएं तंबाकू का सेवन करती थीं। इस सर्वे के अनुसार भारत का 44.5 फीसद पुरूष वर्ग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहा है। शहरी क्षेत्र में 38.9 फीसद जबकी ग्रामीण क्षेत्र में 48.0 फीसद पुरूष तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। पिछले सर्वे में भारत के 57 फीसदी पुरुष तंबाकू सेवन करते थे। इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि देश की 1.5 फीसद महिलाएं शराब का सेवन कर रही हैं, जिसमें 0.7 फीसद शहरी एवं 1.5 फीसद ग्रामीण महिलाएं हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-3 के अनुसार 2.2 फीसद महिला आबादी शराब का सेवन करती थीं। वही 29.2 फीसद पुरुष आबादी शराब का सेवन करता है, शहर में रहने वाले 28.7 एवं गांव में रहने वाले 29.2 फीसद पुरूष शराब का सेवन करते हैं। (विशेष जानकारी के लिए तालिका-3 देखें) युवाओं में शराब पीने की लत से तकरीबन 60 प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। इसका सीधा संबंध आपके हिंसायुक्त व्यवहार से भी है।

युवा स्वास्थ्य पर केन्द्रित योजनाएं

भारत में युवा शक्ति को स्वस्थ रखने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। समेकित बाल विकास योजना, जननी सुरक्षा योजना, सबला योजना की बात की जाए अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की, इन सभी का उद्देश्य है भारत की युवा शक्ति को स्वस्थ बनाना। इस दिशा में भारत सरकार ने 2017 में जहां नयी स्वास्थ्य नीति को लागू किया है वहीं मानसिक स्वास्थ्य विधेयक को भी संसद में पास करा लिया है। कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य की दिशा में सरकार बहुत ही संजीदगी से आगे बढ़ रही है। इस आलेख में योजनाओं के बजाएं नीतियों को समझने की ज्यादा कोशिश की जा रही है जिसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 31 पृष्ठों के अपने मसौदे में भारत को स्वस्थ रखने की अपने नीतियों को प्रस्तुत किया है। पृष्ठ 9 के अनु.3.2 में बचावात्वमक स्वास्थ्य नीति का उल्लेख किया गया है। इसमें सरकार ने कहा है कि

किस तरह लोग बीमार न पड़े इसके लिए काम करना जरूरी है।

इसी तरह सरकार ने नयी स्वास्थ्य नीति के अनु.4.2 में किशोर स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात कही है। इस दिशा में सरकार ने विद्यालयी पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और स्वच्छता को शामिल करने का विचार कर रही है। वहीं किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए प्रयत्नशील है। किशोरों को समूचित पोषण मिल सके, उनके मानसिक समस्याओं का निदान हो सके इस दिशा में सरकार चिंतनशील है। अनु.4.3 में कुपोषण एवं अन्य पोषक कमियों को दूर करने की बात कही गयी है। इसमें यह माना गया है कि पोषण के अभाव के कारण बीमारियों की बोझ बढ़ती जा रही है। खासतौर से एनीमिया एक प्रमुख बीमारी के रूप में सामने आई है। इससे निजात पाने के लिए सरकार स्कूली स्तर पर आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए की गोलियां वितरित कर रही है। वहीं अनु. 4.7 में मानसिक स्वास्थ्य एवं अनु.5 में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से निजात पाने के उपायों पर सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है।

मानसिक स्वास्थ्य नीति

मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2014 में मानसिक स्वास्थ्य नीति का शुभारंभ किया था। इसके शुभारंभ के अवसर पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा था कि, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना सरकार का विशेष लक्ष्य है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मिशन (एनयेचएएम) में पर्याप्त महत्व दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य सभी स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ बढ़ाना तथा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में नेतृत्व को सुदृढ़ करके मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक व्यापक पहुंच प्रदान करना है। यह नीति गरीबों के अनुकूल होगी क्योंकि वर्तमान में भारत में सिर्फ समाज के उच्च वर्ग को ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के महत्व पर चर्चा करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा "यह अवसर मानसिक अस्ववस्थ ता और उससे संबंधित भ्रामक अवधारणों पर जागरुकता बढ़ाने का है। हम एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जो मानसिक रोगियों के मानवाधिकारों का समर्थन करता हो। साथ ही, यह अवसर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों पर दोष मढ़ने के खिलाफ जागरुकता पैदा करने तथा अवसाद, सीजोफ्रेनिया, बाईपोलर सिंड्रोम आदि से पीड़ित व्याक्तियों के लक्षणों को स्पष्ट न करने और उपचारात्मक सुविधाएं प्रदान करने का है।" इसी कड़ी में इस वर्ष मार्च में सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विधेयक मंजूरी दे दी है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि मानसिक रोगियों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। इस बिल में आत्महत्या को अपराधमुक्त किया गया है।

स्वास्थ्य का अधिकार

स्वास्थ्य की दिशा में सरकार की सक्रियता को देखते हुए नागरिक समाज को यह आशा जगी है कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में जल्द ही प्रस्तुत किया जायेगा। नागरिक समाज की ओर से पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने की मांग उठती रही है। देखना यह है कि सरकार इस दिशा में जन आकांक्षाओं पर खरा कब उतरती है।

युवाओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु सुझाव

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के युवाओं में बीमारियां अपना पैर पसारने में सफल होती जा रही हैं। ऐसे में जरूरी है युवाओं की सेहत को लेकर एक नियोजित नीति बनाए जाने की। कुछ बिंदुओं पर विचार किये जाने की जरूरत है।

भौगोलिक आधार पर डाइट चार्ट: मनुष्य जिस भूगोल में रहता है, उसके अनुरूप उसका भोजन होना चाहिए। जब हम अपने पारंपरिक भोजन को छोड़कर आयातित भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मनो-चिकित्सकीय सहायता: आज का युवा मनोवैज्ञानिक रूप से कई रोगों के प्रभाव में है, जिसकी चर्चा ऊपर हमलोग कर चुके हैं। अत: युवाओं को सही समय पर मनोचिकित्सक की सहायता मिले इसके लिए नीति बनाने की जरूरत है। एक चीज और मनोचिकित्सा को लेकर फैले भ्रम को दूर किये जाने की भी जरूरत है, जिसमें मनोचिकित्सक को लोग पागलों का डॉक्टर समझ लेते हैं।

युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य नीति: किसी भी देश का युवा उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। ऐसे में देश के युवा सेहतमंद रहे इस पर विचार करने, कार्यक्रम बनाने और उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक अलग से स्वास्थ्य नीति बनाए जाने की जरूरत है।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि देश के युवाओं में मोटापा, कुपोषण, अन्य पोषण संबंधी बीमारियां, एनीमिया, तंबाकू एवं शराब की लत, मानसिक समस्याएं लगातार बढ़ी है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि युवाओं को सेहत के प्रति सजग किया जाए। उनकी समस्याओं को कॉलेज, कार्यालय एवं घरेलु स्तर पर सुना जाए और उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया जाए। ऐसे में यह भी जरूरी है कि देश के युवा खुद भी अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें। ❑

संदर्भ

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216492/#ref18,19,20,21,24
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216492/#ref23
3. Sonya Jagadesan,R.Harish, Priya.M, RanjitU;s Ranji Mohan A &Viswanatha M(2014) "Prevalence of Overweight and Obesity among school children and Adolescents in Chennai". Indian paediatrics, vol-51, pp544-550.
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216492/#ref62
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216492/#ref63
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216492/#ref63
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216492/#ref64
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216492/#ref67
9. http://24x7daily.com/index.php/2016/07/12/diabetes-as-an-epidemic-in-india-even-with-younger-generation/
10. http://www.univarta.com/news/india/story/845059.html
11. http://www.wahhindi.com/high-blood-pressure-in-india/
12. http://www.onlymyhealth.com/high-blood-pressure-ke-liye-gharelu-nuskhe-in-hindi-1353410489
13. http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=30802
14. http://www.jagranjosh.com/current-affairs/mental-health-care-bill-2017-an-analysis-1491907536-2
15. http://www.thehealthsite.com/hindi/tips-to-prevent-diabetes-in-hindi/
16. http://www.jansatta.com/sunday-magazine/jansatta-editorial-about-health/174765/
17. http://www.livehindustan.com/news//article1-story-366597.html

सशक्त युवा के लिए समन्वित नीतियां जरूरी

श्याम सुन्दर प्रसाद

देश को एक नयी दिशा देने तथा आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा युवाओं के मुद्दे और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए उनके उत्तरोतर विकास हेतु समय समय पर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर कार्य करती आयी हैं। मौजूदा सरकार ने तीन वर्षों में युवाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाओं का शुभारंभ किया है जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इन सब के बावजूद भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा केवल संख्या मात्र के तौर पर गिना जाता है। इसलिए एक ऐसी समग्र नीति की आवश्यकता है जो इन नंबर को संसाधनों में बदल दें

भारतीय युवा देश का भविष्य और वर्तमान दोनों है। इनके सशक्त कंधों पर ही देश की प्रगति का उत्तरदायित्व है। इसलिए सरकारें युवाओं के लिए बजट प्रावधानों में विशेष ध्यान रखती है। पिछले बजटों में समुचित वित्तीय प्रावधान होने के कारण गत 3 वर्षों में युवाओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है जिसका सकारात्मक प्रभाव उनके समग्र व्यक्तित्व में भी परिलक्षित हुआ है। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने तथा वैश्विक मंच पर वृहत छवि को रखने में आधुनिक भारतीय युवा वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में उठाए गये कुछ महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा इस आलेख में की जा रही है।

प्रौद्योगिक के विकास पर बल

सरकार ने रोजगारपरक तकनीक, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर दिया गया है। *कौशल विकास कार्यक्रम, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया* और *मेक इन इंडिया* जैसे कार्यक्रम आदि ने युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने तथा स्वरोजगार हेतु युवाओं को प्रेरित करने व उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का काम है। इसको सफल बनाने के लिए सरकार ने ऋण व्यवस्था और लाइसेंस व्यवस्था को बहुत सरल किया है। जिससे युवक स्वरोजगार के लिए प्रेरित हुए है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के *मेक इन इंडिया* पर जारी आंकड़ों को देखें तो पाते हैं कि *स्टार्ट अप वेव* ने पिछले 2 वर्षों में 20,000 से ज्यादा स्टार्ट अप तैयार किया है जिनके संस्थापक औसतन 31 वर्ष के युवा है। वर्ष 2016 में युवाओं का 55 प्रतिशत हिस्सा कॉर्पोरेटस के लिए काम करेंगे। भारतीय प्रशिक्षुओं की 36.8 प्रतिशत संख्या बढ़ी है। मई 2016 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की संख्या मई 2014 में 10,750 के मुकाबले बढ़कर 13,105 हो गयी हैं।

एफडीआई का तेजी से निवेश

सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहे 'रिटेल मार्केट' और 'मॉल की बाजार संस्कृति' का छोटे-छोटे शहरों में आने तथा 'सिंगल ब्रांड रिटेल' के साथ 'मल्टी ब्रांड रिटेल' में एफडीआई में सीधे निवेश की सरकार की अनुमति आदि ने आधुनिक लाखों युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ायी है। सरकार द्वारा एफडीआई के सुधार उपायों के कार्यान्वित रूप से भारत दुनिया का सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बन चुका है।

युवा कार्यक्रम का मूल्यांकन: एक दृष्टिकोण

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को अप्रैल 2008 में दो विभागों युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग में विभक्त किया गया। ये दोनों विभाग अपने-अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए विशेष योगदान दे रहे हैं। युवा कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषय जैसे- *युवा नीति, राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम* के मुख्य घटक / उप योजना नेहरु युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनयेसएस), स्वैच्छिक युवा संगठन, राष्ट्रीय युवा वाहिनी, युवा कल्याण गतिविधियां और राष्ट्रीय - अंतरराष्ट्रीय युवा सहयोग आदि आते हैं। खेल विभाग ने भी युवाओं के उन्नयन एवं विकास के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे युवाओं में अनुशासन के साथ देश के नाम को रोशन करने का जज्बा उत्पन्न हुआ है।

युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाए गये कार्यक्रमों ने युवा वर्ग को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास किया है। इन विभिन्न कार्यकमों का आयोजन भिन्न-भिन्न स्थानों पर किये गये है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत संख्या में युवाओं

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के श्याम लाल महाविद्यालय (प्रातः) में सहायक प्रोफेसर हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) तथा अन्य संस्थानों में भी अतिथि अध्यापक के तौर पर अध्यापन। ईमेल: shyamzrd@gmail.com

ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। सरकार द्वारा *राष्ट्रीय युवा नीति-2014* को देश के युवाओं के सशक्त बनाने की दृष्टि से लायी गयी है। यह नयी नीति युवा को 15-29 वर्ष की उम्र सीमा तक ही परिभाषित करती है। भारतीय जनसंख्या का तीसरा हिस्सा अर्थात् 35-40 प्रतिशत इस उम्र के युवा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) ने मंत्रालय के एक विचारक व संगठन के रूप में देश के युवाओं से संबंधित कार्यक्रमों जैसे - *शैक्षिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण कार्यक्रम* एवं *शोध कार्यक्रम* आदि में कार्यों को संपन्न किया है। सरकार ने *राष्ट्रीय सेवा योजना* के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों के माध्यम से विभिन्न समकालीन सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर युवाओं में जागरुकता पैदा करने के लिए पुरजोर कोशिश की है। विगत तीन वर्षों में ऐसा कोई मुद्दा/घटना एनयेसएस के कार्यों से अछूता नहीं दिखता है।

नेहरु युवा केंद्र संस्थान (एनवाईकेएस)

विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक एनवाईकेएस का उद्देश्य युवाओं को व्यक्तिगत और नेतृत्व गुणों का विकास और उन्हें राष्ट्रीय निर्माण की गतिविधियों में संलग्न रखना है। राजग सरकार के 2 वर्षों में 31 मार्च, 2016 तक इन संस्थानों द्वारा की गयी गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है:

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम

इनके कार्यक्रमों के संचालन के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा सरकारी / गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाते हैं। इसके अंतर्गत विगत दो वर्षों में प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो तालिका-1 और तालिका-2 में बताये गये हैं।

उपरोक्त दोनों तालिका 1 और 2 के अनुसार, इन आयोजित कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी व सहयोग से स्पष्ट है कि सरकार की मंशा युवाओं को सशक्त एवं उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाकर राष्ट्र-निर्माण में उनकी बेहतर भूमिका सुनिश्चित करना है। इन कार्यक्रमों से लाभांवित युवा न केवल अपने लिए उपयोगी है बल्कि दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए है। जरुरत इस बात की है कि इन कार्यक्रमों का विस्तार हो तथा प्रशिक्षित युवाओं को अपने क्षेत्र में एक ब्रांड दूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए।

इसके अलावा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों ने अपने स्तर पर भी युवाओं को सशक्त करने एवं उनके सतत विकास के लिए प्रयास किये हैं। गृह मामलों के मंत्रालय ने *जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम* का आयोजन जनजातियों के सांस्कृतिक विरासत के उन्नयन के उद्देश्य से किया है। इनके तहत 20 कार्यक्रमों के आयोजन में 4,472 युवाओं ने भाग लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर *जिला युवा सम्मेलन* का आयोजन 126 जिलों में किया। साथ ही इस मंत्रालय ने युवाओं के लिए सबसे बड़ी गलत लत जिसमें ड्रग्स का सेवन करना है, को खत्म करने के लिए पंजाब के 10 जिलों में *ड्रग्स निरोधक जागरुकता अभियान* चलाया। इतना ही नहीं, विगत 3 वर्षों में सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किये हैं। उनके कार्यक्रमों में ऐतिहासिक महापुरुषों को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में एक अच्छे उद्देश्य को जोड़ते हुए दिखायी देता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म वर्षगांठ पर *पुनर्जागरण कार्यक्रम* को लाकर शांति और सार्वभौमिक भाईचारा के उद्देश्य रखे गये। समय-समय पर सभी वर्गों के युवाओं की भागीदारी लक्ष्य प्राप्ति हेतु *स्वच्छ भारत मिशन* के अंतर्गत कार्य किये गये। कई स्तर पर *राष्ट्रीय युवा पुरस्कार* का वितरण किया गया है जो युवाओं के मनोबल को बढ़ाता है। अंतराष्ट्रीय युवा प्रतिनिधि-मंडल में भारतीय युवाओं ने जापान, नेपाल, चीन तथा बांग्लादेश आदि देशों में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित किया है। यह वर्तमान सरकार द्वारा युवाओं को गौरवांवित करने एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रयत्न किया गया है। युवाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म वर्षगांठ पर *राष्ट्रीय युवा महोत्सव* का आयोजन 12-16, जनवरी को किया जाता है।

19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, गुवाहाटी, असम, 2015 एवं 20वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, रायपुर, छतीसगढ़, 2016 तथा 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, रोहतक, हरियाणा में 12-16 जनवरी, 2017 को मनाया गया। इनमें केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों का सहयोग था। 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में लगभग 7000 युवाओं ने हिस्सा लिया। यह महोत्सव *युवाओं के लिए डिजिटल इंडिया* थीम पर आधारित थी।

वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं, कार्यक्रम एवं पहलें की है। अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास के लिए *नयी उड़ान योजना, नयी रोशनी योजना, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, उस्ताद योजना* (14 मई, 2015 को शुभारम्भ) एवं *मानस योजना* आदि चलायी है तथा इन्हें भरपूर वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। सरकार ने इन समुदाय के युवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए *नयी मंजिल योजना* (08 अगस्त, 2015 को शुभारंभ) के लिए वार्षिक बजट 2016-17 में योजनागत बजट 155 करोड़ रुपये मुहैया किया है। वर्तमान सरकार ने *सीखो और कमाओ योजना* को *स्किल इंडिया* और *मेक इन इंडिया* की प्राथमिकता के अनुरूप विस्तारित कर वार्षिक बजट 2016-17 के लिए 210 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इन सभी योजनाओं से अल्पसंख्यक युवा बहुत लाभांवित हुए हैं तथा इनके लिए कई उपलब्धियों के द्वार भी खुले हैं।

युवाओं के सशक्तीकरण में चुनौतियां

सरकार ने युवाओं को भारतीय सभ्यता

तालिका 1: एनवाईकेएस के विविध कार्यक्रम (2014-15, 2015-16)

आयोजित कार्यक्रम के नाम	उद्देश्य	कार्यक्रम	प्रतिभागी
युवा नेतृत्व और समुदाय विकास प्रशिक्षण	युवा वर्ग में क्षमता व राष्ट्रीय निर्माण करना	4,693	2,05,298
थीम बेस्ड जागरुकता और शिक्षा कार्यक्रम	स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि सामाजिक मुद्दों पर जागृति लाना	11,526	8,95,895
कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्रामीण युवाओं के व्यावसायिक कौशल का विकास करना	13,214	2,76,552
खेलों का संवर्धन	खेल सामग्री और प्रबंधन	6,875	7,50,215
लोक कला और संस्कृति संवर्धन	युवा कृतियों को बढ़ावा देना	1,114	2,15,694
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिनों का अनुपालन / प्रेक्षण	राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जागरुकता बढ़ाना	24,527	26,96,017
युवा क्लब विकास कार्यक्रम	युवा क्लबों को मजबूत करना	4,098	3,08,474
यूथ कंवेंशन और युवा कृति	ग्रामीण युवाओं का सशक्तीकरण	1,165	2,68,782

स्रोत: www.yas.in/sites/default/okenglish2016pdf/2014-15,2015-16, schemes, programmes and Initiatives

संस्कृति से जोड़ने के प्रयास में कई उपरोक्त योजनाएं शुरु की है। लेकिन युवा वर्ग पाश्चात्य फैशन, स्वछंदता, एकल परिवार की धारणा, प्रदर्शन-प्रभाव, अपराध व प्रवास आदि विकृत जीवन जीने में सारी ऊर्जा लगा रहा है। यह उन्हें विध्वंसात्मकता और राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर अग्रसर करता है। भारत का विकास *रोजगारविहीन* हो रहा है। तीन दशकों से एनयेसएसओ के *रोजगार-बेरोजगार सर्वे* (ईयूएस) ने कम और स्थायी बेरोजगारी दर का हवाला दिया है। यहां रोजगार और बेरोजगारी की दर का प्रतिशत 5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत है। वर्तमान का अब यह आलम है कि प्राइवेट कंपनियां धीरे-धीरे कर्मचारियों की छंटनी करनी शुरू कर दी। एक समय था जब दिल्ली मेट्रो परियोजना ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराया लेकिन अब हालात यह है कि मेट्रो के अधिकांश कार्य मशीनों से होने के कारण कर्मचारियों की भर्ती नहीं बल्कि छंटनी हो रही है। इसका जीता जागता हैरान करने वाला उदाहरण वेलकम मेट्रो स्टेशन के 8 टोकन काउन्टर का बंद होना है। अब यहां यात्री टिकट टोकन वेंडिंग मशीन से लेते हैं। ऐसा लगता है कि हर काम सेल्फ सर्विस के नियम पर होगा और यहां *सिटीजन एज ए कस्टमर* का प्रचलन है। इस व्याप्त व्यवस्था से एक बेरोजगार युवक अपने आप को कैसे सशक्त पा सकता है? रोजगारपरक व्यवस्था बहुत सारी समस्याओं का हल लेकर आती है। आज विभिन्न क्षेत्रों में युवक विभिन्न तरह के गलत गतिविधियों में संलग्न होते हुए देखे जा सकते हैं। चाहे जम्मू और कश्मीर के युवक हो या नक्सलवाद की राह पर चलते छत्तीसगढ़ जैसे नक्सलवाद या माओवाद प्रभावित राज्यों के युवक। हर युवक की एक ही समस्या है कि वह अपने कार्यबल को एक बेहतर दिशा नहीं दे पा रहा है। उसे कोई ऐसा कार्य नहीं मिल पा रहा है जिससे वह अपना और अपने परिवार का परवरिश बेहतर ढ़ंग से कर सके। इन भटके युवाओं को मुख्यधारा में लाने का सुदृढ़ तरीका है, उन्हें योग्यतानुसार कार्य मुहैया कराना और यह जिम्मेवारी सरकार और संपन्न बौद्धिक चिंतनशील समाज की है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तथा औद्योगिक मांग के अनुसार भारतीय युवा तैयार नहीं हैं। यहां की बेहाल शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा पद्धति तथा बुनियादी शिक्षा के अव्यवस्थित स्तर के कारण रोजगार के नये क्षेत्रों के आने पर भी युवाओं के पास प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां व्याप्त हैं। भारत की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, बढ़ता उपभोक्ता बाजार, मल्टी नेशनल कंपनियों का भारत में आना, एपीओ, बीपीओ कंपनियों की मांग आदि ने रोजगार के कई अवसर खोले है। जिसमें एक अलग तरह के युवाओं अर्थात् प्रोफेशनल्स युवाओं की मांग है। त्वरित निर्णय, अत्याधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित, परिस्थिति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य करने वाला, फटा-फट अंग्रेजी बोलने वाला स्मार्ट युवाओं की जरूरत है।

तालिका 2: एनवाईकेएस की विविध पहलें (2014-15, 2015-16)

आयोजित कार्यक्रम	उद्देश्य	कार्यक्रम	प्रतिभागी
राष्ट्रीय एकीकृत कैंप	सांस्कृतिक विरासत समझ विकसित करना	122	23, 591
युवा नेतृत्व व व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	ग्रामीण उत्तरदायित्व विकास करना	23	690
किशोरों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण	किशोरों के सशक्तीकरण करना	497	16,057
जोखिम कैंप	युवाओं को साहसी बनाना	286	7,009

स्रोतः www.yas.in/sites/default/okenglish2016pdf/2014-15,2015-16, schemes, programmes and Initiatives

भारत हर क्षेत्र में समृद्ध है लेकिन अधिकांश युवाओं का सरकारी नौकरियों की अपेक्षाएं ज्यादा रहती है। उच्च शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था प्रत्येक साल हजारों बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। पढ़े-लिखे योग्य डिग्रीधारी शिक्षक नियुक्तियों को लेकर अपने आप को कोस रहे है। आज के समय में शिक्षा को व्यापार की भांति उपयोग किया जाने लगा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अर्थव्यस्था के *रेट ऑफ रिटर्न* के सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। शैक्षणिक कार्यों में लागत से अधिक लाभ की कोशिश ही होती है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में बाजारवाद ने युवा वर्ग को मूल्यहीन, असृजन, अमानवीय, भ्रष्टाचारी और अविवेकी बना रहा है। वर्तमान चुनौतियां सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है।

युवा केंद्रित समग्र नीतियां जरूरी

भारत में युवा बहुस्तरीय चुनौतियों जैसे- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक रुढ़िवादिता और कुरीतियों आदि से रोज सामना कर रहा है। नीति आयोग द्वारा 23 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित *ड्राफ्ट थ्री ईयर विजन, स्ट्रेटजी एंड एक्शन एजेंडा 2017-18 टू 2019-20* में युवाओं के लिए ज्यादा सशक्तीकरण और गुणवतापूर्ण उच्च जीवन स्तर की आवश्यकता स्वीकार किया है। उनका मानना है कि संकटमय आर्थिक वृद्धि और खुला एवं उदारीकृत अर्थव्यवस्था के कारण उत्पादक कार्यबल का निर्माण करना पड़ेगा। व्यापार, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में उच्च उत्पादकता एवं अच्छे वेतन वाली नौकरी सृजित करनी होंगी। सरकार का प्रयास यह है कि 2022 तक किसानों के आय को दोगुना किया जाए। यह ग्रामीण युवाओं का कृषि से हुए मोहभंग को फिर उन्हें कृषि कार्यो की ओर खींच लाएगा। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिल सकता है। यह ध्यातव्य है कि कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित किये जा सकते हैं। वर्तमान सरकार को इन क्षेत्रों को अत्यधिक उत्पादक बनाने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। सरकार को तात्कालिक रूप से एनयेसएसओ या किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा देश में युवाओं की उम्र, योग्यता, रुचि, प्राथमिकता, समस्या आदि पर डाटाबेस तैयार करने या सर्वे करने की आवश्यकता है। इन प्राप्त आंकड़ों के अनुसार युवा वर्ग के लिए एक समग्र नीति बनायी जाए, जिसमें स्थानीय, क्षेत्रीय, भाषायी एवं जाति आधारित आदि विभिन्नताओं के लिए लचीलापन हो। इनके हर पहलू को देखने के लिए केवल एक मंत्रालय हो जो नोडल विभाग के रूप में भी कार्य करें। इसके अलावा अस्तित्व में चल रहे प्रत्येक नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन समीक्षा एवं उनका संवर्धन करना जरुरी है। प्रत्येक संस्था/संगठन/विभाग में नागरिक घोषणापत्र को पारदर्शी रूप से लागू किया जाए और कार्यो/गतिविधियों से संबंधित अधिकारीतंत्र/अधिकारियों का जवाबदेही मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था द्वारा तिमाही में हो। राष्ट्र बदल जाएगा, व्यवस्थाएं बदल जाएंगी और यह देश का युवा वर्ग ही करेगा, लेकिन युवा वर्ग को एक नयी दिशा देने वाली स्पष्ट नीति बननी चाहिए। ❑

संदर्भ

1. www.yas.nic.in
2. www.yas.in/sites/default/files/e-bookenglish2016pdf/
3. www.makeindia.com
4. Economic Survey Report 2016-17
5. https://drive.google.com/file/d/0B-Tv7_upCKANcjZUR2pVS0dQaHc/view
6. Union Budget 2015-16, 16-17, 17-18
7. http://www.indiaonlinepages.com/population/india-current-population.html
8. अमर उजाला, नयी दिल्ली, 12 जनवरी, 2017
9. Labour Bureau Report
10. www.labour.nic.in
11. http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Hindi-Booklet.pdf
12. http://niti.gov.in/writereaddata/files/coop/ActionPlan.pdf/ p. 2, 151-52

PATANJALI IAS

पढ़िये उनसे जिनकी **प्रामाणिकता** एवं **श्रेष्ठता** निर्विवाद है तथा जिनसे टॉपरों ने भी पढा है।

सामान्य अध्ययन

निःशुल्क कार्यशाला 21 May 11:30 AM

मुखर्जी नगर (पोस्ट ऑफिस के ऊपर)

दर्शनशास्त्र

सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय

- सबसे छोटा सिलेबस, लाखों तथ्यों को रटने से छुटकारा
- रिवीजन में आसान
- अंकदायी एवं सफलतादायी विषय
- G.S और निबंध में बहुत उपयोगी

निःशुल्क कार्यशाला
22 June 9:00 AM

भूगोल

(वैकल्पिक विषय)

श्री जे० शंकर

निःशुल्क कार्यशाला

18 May 6:00 PM

मुखर्जी नगर पोस्ट ऑफिस के ऊपर

RAS

Foundation

21 May 4:00 PM

IAS

Foundation

15 May 4:00 PM

Ph.: 9571456789

GWALIOR CENTRE

MPPSC 2017

फाउंडेशन बैच 20 May 4 PM

CDLP Creative Distance Learning Programme

रचनात्मक दूरस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम

घर बैठे करें IAS की तैयारी

इस रचनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, IAS की तैयारी के लिए देश के विख्यात **PATANJALI** संस्थान के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार सारगर्भित, प्रासंगिक, प्रामाणिक पाठ्य सामग्री घर बैठे मंगवाकर अपनी तैयारी की शुरूआत कर सकते है और उसे नई दिशा दे सकते हैं। यह सामग्री विशेष रूप से वैसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखगर तैयार की गई है जो IAS बनने की इच्छा तो रखते है परन्तु किसी कारणवश दिल्ली आने में असमर्थ है या समुचित मार्गदर्शन एवं सामगी की कमी से द्वंद्व की स्थिति में हैं। यह पाठ्य सामग्री सिविल सेवा के नवीन पाठ्यक्रम एवं बदलती हुई मांगों के अनुरूप है। साथ ही इसे समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, संस्थाओं समितिओं की रिपोर्टों, सुधारों, नवीन उभरती समस्याओं एवं समाधानों के माध्यम से अप-टू-डेट किया गया है। पाठ्य सामग्री के साथ-साथ विगत वर्षों के प्रश्नों का विषयवार संग्रह भी सम्मिलित है जिसके आधार पर आप पिछले वर्षों के विभिन्न खंडों से पूछे गए प्रश्नों की संख्या एवं उनकी प्रकृति (Nature) को जानकर अपनी तैयारी को सम्यक् दिशा (Right Direction) में आगे बढ़ा सकते हैं।

सामान्य अध्ययन (प्रा.+मुख्य परीक्षा)	सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा)	सामान्य अध्ययन +सीसैट	दर्शनशास्त्र (वैकल्पिक विषय)	भूगोल (वैकल्पिक विषय)
27+4 Booklets	24 Booklets	24+4+9 Booklets	8 Booklets	10 Booklets
Rs. 12000	Rs. 10000	Rs. 12000	Rs. 6000	Rs. 5000

E-Mail: iaspatanjali@gmail.com
website:iaspatanjali.com

DELHI CENTRE
202, 3rd Floor, Bhandari House
(above Post Office)Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 011-43557558, 9810172345

JAIPUR CENTRE
31, Satya Vihar, Lal Kothi, Near Jain
ENT Hospital, New Vidhan Sabha, Jaipur
Ph.: 9571456789, 9680677789

GWALIOR CENTRE
G-5, Chaurara Point,
Near Rawal Dass, Phool Bagh Chaurara,
Opp. SBI Bank, Gwalior (M.P.)
Ph:- 0751-4073458, 9584392158

युवा आकांक्षाओं के समक्ष चुनौतियां

ऋतु सारस्वत

युवा बल को युवा शक्ति में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले युवा को अपने स्वभाव को पहचानने का प्रशिक्षण देना होगा। स्वभाव के अनुरूप कार्य का चयन करने से पूरी क्षमता व संभावना का विकास हो सकता है। भीड़ का हिस्सा बन, अपनी आजीविका का चयन करने के स्थान पर अपने स्वभावानुरूप शिक्षा व तदनुरूप व्यवसाय का चयन आत्मसंतुष्टि का भाव देगा। स्वभाव से स्वावलंबन युवा आकांक्षाओं की पूर्ति का मूलमंत्र सिद्ध हो सकता है। वह कार्य या विषय जो रुचिकर हो, उसकी राह में आयी चुनौतियां भी दुष्कर प्रतीत नहीं होती

''बरगद के पेड़ की पूरी शक्ति उस पेड़ के बीजों की शक्ति के बराबर है। इस तरह से हम दोनों आप और मैं, समान हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिभाओं को अलग-अलग रूपों से प्रस्तुत करते हैं। कुछ बीज बरगद का पेड़ बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बीज पौधे के रूप में ही मर जाते हैं और कभी पेड़ नहीं बन पाते। निश्चित परिस्थितियों और पर्यावरणीय स्थितियों के कारण कई बीजों को नुकसान पहुंचता है और वे मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं, और नये बीजों को पेड़ बनने में मदद करते हैं। आपने देश के लिए कार्य किया है और अनेक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों व ज्ञानकर्मियों की मदद की है। क्या आप बता सकते हैं कि आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उनकी योग्यताएं बरबाद न हों या उनका विकास अपरिपक्वावस्था में ही अवरुद्ध न हो जाए, उन बरगद के बीजों की तरह, जो कभी पेड़ बन नहीं पाये'' यह पत्र टी. सरवनन नामक एक विद्यार्थी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को लिखा था। यह पत्र सिर्फ टी. सरवनन की जिज्ञासा, उत्कंठता और अभिलाषाओं के मध्य व्याप्त चुनौतियों को ढूंढने का प्रयास भर नहीं है, यह हर भारतीय युवा का प्रश्न है। अपनी सफलताओं के स्वप्न को बुनते हुए, असफलताओं के कठोर धरातल पर टकराने की पीड़ा और उसके अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ़ने की चेष्टा है।

भारत में दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी है। इसका सीधा-सा अर्थ है, यह देश ऊर्जा से भरपूर है फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या देश का युवा भी स्वयं के बारे में इतना ही उत्साहित, आत्मविश्वास से भरपूर और सफलताओं को छूने को तत्पर है? शायद नहीं, क्योंकि उसकी आकांक्षाओं के समक्ष अनेकानेक चुनौतियां हैं। इसमें किंचित् भी संदेह नहीं कि हर युवा विशिष्ट बनना चाहता है। हर व्यक्ति में विज्ञान, कला या समाज और दुनिया को बदल देने की क्षमता और आकांक्षा होती है परन्तु इन क्षमताओं पर प्रश्न चिह्न तब अंकित हो जाता है, जब अनुकूल परिस्थितियां न हों। वे अनुकूल परिस्थितियां कौन-सी हैं? इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

जीविका के प्रश्न

किसी भी देश के युवा के जीवन का सर्वप्रमुख और सर्वप्रथम प्रश्न, उसका जीविकोपार्जन होता है। इसमें अति धनाढ्य वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के युवाओं को अपवाद स्वरूप देखा जा सकता है। परंतु ऐसे युवाओं की संख्या बहुत कम है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि देश के युवाओं के सामने रोजगार प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। फरवरी 2017 में राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में योजना राज्यमंत्री ने कहा कि कुल बेरोजगारी दर पांच प्रतिशत है। केंद्र सरकार के रोजगार, सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या का बढ़ना चिंता का विषय है। एक

लेखिका बीते 18 वर्षों से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय से संबद्ध एक महाविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य कर रही हैं। इनके निर्देशन में कई शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि दी जा चुकी है। देश के प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठों में 450 से अधिक लेख प्रकाशित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार की 5 पुस्तकों में सहलेखिका। लोकसभा चैनल में विषय विशेषज्ञ के तौर पर वार्ताओं में प्रतिभागिता। ईमेल: saraswatritu@yahoo.co.in

और महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या आज की शिक्षा व्यवस्था, युवाओं की प्रतिभाओं को पहचानने में सक्षम है या फिर किताबी ज्ञान पर आधारित डिग्रियों की लंबी फेहरिस्त के बीच, देश के युवाओं में उस स्तर की प्रतिभा का अभाव है जितनी संबंधित नौकरियों के लिए चाहिए। खासकर सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान पारिस्थितिक तंत्र में रोजगार ढूंढ़ते युवाओं में प्रतिभाओं की भारी कमी है। हाल में जारी एक आंकड़े में दावा किया गया है कि इस देश के 95 प्रतिशत इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में नौकरी करने के लायक नहीं है। जब इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमाधारी युवाओं का यह हाल है, तो कल्पना की जा सकती है कि जो युवा शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाये या जिनके पास तकनीकी डिग्रियां नहीं हैं, उनका क्या हाल होगा? स्वाभाविक है युवा भारत की यह तस्वीर अच्छी नहीं कही जा सकती, इसलिए यह जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्यों, देश का युवा, उन स्वप्नों को पूरा नहीं कर पा रहा है जो वह अपने लिए देखता है।

युवा आकांक्षाएं व सामाजिक बदलाव

दरअसल हमारा सामाजिक पर्यावरण कुछ निश्चित परिपाटियों के मध्य ही सुगठित होता है, और उसके द्वारा सुनिश्चित पैमानों के आधार पर ही सफलता और असफलता की परिभाषा रची जाती है। स्वतंत्रता पूर्व वैदिक संस्कृति में या फिर मध्यकाल में देश के युवा वर्ग ने किन चुनौतियों का सामना किया इसके संबंध में, विभिन्न मंचों पर चर्चाएं होती रही हैं। परंतु विगत तीन दशकों में भारत का युवा किन चुनौतियों का सामना कर रहा है इसके गहन विमर्श की आवश्यकता को शायद अनुभव नहीं किया गया क्योंकि समाज की निश्चित परिपाटियों के विरुद्ध जाना कुचेष्टा माना गया। अगर हम 19वीं सदी के अंत तक आते-आते, युवा वर्ग की आकांक्षाओं का आंकलन करने का प्रयास करें तो पाएंगे कि उनकी आकांक्षाएं पल्लवित होने से पूर्व ही, दबा दी गयी। उन्हें परिवार और समाज के निश्चित दायरों के मध्य ही सफलता के पैमानों में से किसी एक का चुनाव करने की अनुमति दी गयी और अगर हम यह सोचते हैं कि आज इस दायरे में कहीं परिवर्तन आ गया है तो यह हमारा भ्रम मात्र है। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के चुनाव के मध्य, शायद ही कोई युवा कभी यह कहने का साहस जुटा पाया हो कि उसकी दिलचस्पी विज्ञान की इन शाखाओं में नहीं है। कला और संस्कृति को जानने, पढ़ने या अपने जीवन का उद्देश्य बनने का साहस कर पाना सहज नहीं रहा। क्योंकि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं महत्वपूर्ण यह है कि आप ऐसा क्या करें कि जिससे शीघ्र अतिशीघ्र आप को रोजगार मिल सके। अगर रोजगार प्राप्त करना ही शिक्षा व्यवस्था का अंग होता तो भी निराशा की स्थिति नहीं होती। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य तो यह है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं को भ्रमित कर दिया और संपूर्ण समाज ऐसे मिथकों के ढेर पर बैठ गया, जिसे दूर करना सहज नहीं है।

जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य, जीवन की असीम संभावना, समस्या और समाधान समझने के लिए गहन विचार शक्ति का होना अनिवार्य है। यह शक्ति हमें यथार्थ शिक्षा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा 'शिक्षा देते समय और भी एक महत्वपूर्ण विषय को हमें याद रखना होगा, हमें विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, उन्हें स्वयं ही गहन चिंतन करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए ताकि वे स्वयं विचार करना सीख जाएं।'

पहला मिथक यह कि शिक्षा के मायने डिग्रियां हासिल करना है। दूसरा मिथक यह है कि विज्ञान और उसकी विभिन्न शाखाओं से जुड़े विषय, प्रतिभा के उचित मानक है, तीसरा मिथक यह है कि साहित्य, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय प्रतिभाविहीन विद्यार्थियों का चुनाव होते हैं, चौथा मिथक यह है कि सफलता और आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रबंधन डिग्री जैसी उच्च स्तरीय, शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसे अनेक मिथकों के मध्य, युवाओं की आकांक्षाएं स्वयं ही भ्रमित होकर, आगे बढ़ने का साहस कर नहीं पाती। अगर वाकई उच्च स्तरीय शिक्षा के मानक सत्य होते तो, बेरोजगारों की एक लंबी फौज नहीं दिखायी देती। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में समझने के बजाय रटाया जाता है, और युवाओं को हुनर सिखाने और उनकी सोच बदलने की कोशिश नहीं की जाती। सच तो यह है देश के युवा ऐसी डिग्रियों के साथ बाहर निकल रहे हैं, जो उन्हें कुछ नहीं सिखाती। ऐसे दौर में इस शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है, जब नवाचार का महत्व बढ़ने के साथ तकनीक की गति भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में शिक्षा की कमजोर बुनियाद वाले लाखों छात्रों का भविष्य स्वाभाविक तौर पर उज्ज्वल नहीं हो सकता तो ऐसे में क्या?

जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य, जीवन की असीम संभावना, समस्या और समाधान समझने के लिए गहन विचार शक्ति का होना अनिवार्य है। यह शक्ति हमें यथार्थ शिक्षा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा 'शिक्षा देते समय और भी एक महत्वपूर्ण विषय को हमें याद रखना होगा, हमें विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, उन्हें स्वयं ही गहन चिंतन करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए ताकि वे स्वयं विचार करना सीख जाएं।' वर्तमान पीढ़ी सत्य को स्वीकारने में हिचक रही है। यह सत्य है कि जिस तादाद में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में रोजगार सृजित करना असंभव है। व्यवस्थाओं पर अंगुली उठाने के बजाय, यह आवश्यक हो जाता है कि स्वयं यह विचार किया जाए कि जिस राह को उन्होंने चुना है क्या वह उनके स्वभावगत है।

सामर्थ्य की पहचान जरूरी

युवा बल को युवा शक्ति में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले युवा को अपने स्वभाव को पहचानने का प्रशिक्षण देना होगा। स्वभाव के अनुरूप कार्य का चयन करने से पूरी क्षमता व संभावना का विकास हो सकता है। भीड़ का हिस्सा बन, अपनी आजीविका का चयन करने के स्थान पर अपने स्वभावानुरूप शिक्षा व तदनुरूप व्यवसाय का चयन आत्मसंतुष्टि का भाव देगा। स्वभाव से स्वाबलंबन युवा आकांक्षाओं की पूर्ति का मूलमंत्र सिद्ध हो सकता है। वह कार्य या विषय जो रुचिकर हो, उसकी राह में आयी चुनौतियां भी दुष्कर प्रतीत नहीं होती। परंपराओं का निर्वहन करने के प्रयास में रुचिकर विषयों का चुनाव न

करना स्वयं के लिए दु:खद होता है परंतु संपूर्ण व्यवस्था में भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। सच तो यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में, युवा आबादी को उपयोगी कौशल में प्रशिक्षित करना, फिर इनके लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराना तथा उद्योग कृषि व सेवा क्षेत्र में संतुलन स्थापित करना अपने आप में बड़ा ही दुष्कर कार्य है। उच्च शिक्षा में असंतुलित वृद्धि के कारण एक ओर हम बड़ी संख्या में तैयार हो रहे इंजीनियर्स (अभियंताओं) को उचित रोजगार नहीं दे पा रहे हैं वहीं दूसरी ओर अनेक आवश्यक कार्यों के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। एक आकलन के अनुसार स्नातक स्तर पर कला क्षेत्र में घटते प्रवेश के कारण आने वाले दशकों में पूरे विश्व में भाषा शिक्षकों की कमी होगी। तकनीकी क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव के कारण मूलभूत विज्ञान यथा भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए पर्याप्त संख्या में वैज्ञानिक नहीं मिल रहे हैं। इन वास्तविकताओं के साथ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां यह उत्पन्न होता है कि वे जो चित्रकला, भाषा या संगीत में रुचि रखते हैं, जिनके सपनों के ताने-बाने इनके आसपास बुन जाते हैं, उनके सामने जीविकोपार्जन का संकट, उन्हें उन पंक्तियों में सम्मिलित होने के लिए विवश कर देता है, जहां पहले ही लंबी कतारें हैं।

आर्थिक दबाव भी कम नहीं

आर्थिक विवशताएं, देश की युवा आबादी के एक बहुत बड़े भाग की चुनौती है, जिसके चलते वह उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विभेद एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अमीर-गरीब छात्रों के बीच बढ़ती इस खाई को यूनेस्को ने चिंताजनक करार दिया है। *ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग* रिपोर्ट का हवाला देते हुए यूनेस्को ने दुनिया के सभी देशों की सरकारों से गैप (अंतराल) को कम करने की अपील की है। यूनेस्कों ने एक सुझाव में बताया है कि सरकारी स्तर पर एक ऐसी एजेंसी हो जो छात्र सहायता से संबंधित सभी तरह की जरूरतों के बीच तालमेल स्थापित कर सकें। इन जरूरतों में शिक्षा ऋण, अनुदान और स्कॉलरशिप आदि हो सकते हैं। *ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग*, का मानना है कि छात्रों की बढ़ती संख्या के लिहाज़ से उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना सहज नहीं है पर नीतिगत व्यवस्था के जरिए सरकार इन चुनौतियों से पार पा सकती है। बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों से छात्रों को मिले ऋण की मासिक किश्त छात्रों की मासिक आय के 15 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। ऐसा होने पर छात्र न केवल पाठ्यक्रम पूरा कर पाएंगे बल्कि ऋणों की अदायगी करना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। इन नीतिगत विषयों पर चर्चा और उनके अमलीकरण के मध्य एक अंतराल और भी है और वह है स्वयं की पात्रता सिद्ध करना।

विषमता का विष मिटाना जरूरी

भारतीय सामाजिक परिवेश में यह दलित समुदाय से संबंधित छात्रों और लड़कियों के लिए बेहद ही चुनौती भरा लक्ष्य है क्योंकि असमानता की जड़ें आज भी इतनी गहरी हैं कि यह सहज स्वीकार ही नहीं किया जाता कि दलित युवा और छात्राएं प्रतिभाशाली हो सकती हैं। इन दोनों ही वर्गों के लिए कुछ निश्चित परिधियों के खाके खींच दिये गये हैं और अगर इन खाकों को पार करके, वे स्वयं को सिद्ध करने की चेष्टा भी करते हैं तो नकारात्मकता वातावरण में, उनके लिए यह बेहद कष्टकारी होता है।

गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल व्यक्तियों के बीच भी गणित में योग्यता को लेकर पूर्वाग्रह का स्तर वैसा ही है। समान रूप से योग्य होने के बावजूद जहां लड़के कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे नजर आये, वहीं लड़कियों का आत्मविश्वास कमजोर रहा' यह तथ्य शोध पत्रिका, फ्रांटियर्स इन साइकॉलोजी के ताजा अंक में प्रकाशित हुआ है।

डीआइसीसीआई के मुताबिक देश में दलित उद्यमों की संख्या वर्ष 2001-02 में 10.5 लाख थी, जो वर्ष 2006-07 में 28 लाख पार कर गयी थी। यह सालाना करीब 25 प्रतिशत से बढ़ रहा है। यहां तक कि उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले दलित युवाओं में जहां 187 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं अन्य जातियों में 119 प्रतिशत। पंजाब में, उच्च जातियों के गढ़ में गिन्नी माही अंबेडकर के संदेशों को पंजाबी लोकगीतों के माध्यम से पहुंच रही है। इसी तरह दलित गायकी परंपरा में पूजा का नाम भी धूम मचाए हुए है। यू-ट्यूब में इनके गानों को 50-50 लाख बार तक देखा जा चुका है।

सामाजिक पृष्ठभूमि में रची बसी विचारधाराओं ने इस कदर मकड़जाल फैला रखा है कि उसमें उलझकर, उससे बाहर सोचना संभव ही नहीं हो पाता। इसकी बानगी यह है कि अधिकतर छात्राएं विज्ञान और गणित विषय लेने से कतराती हैं क्योंकि शिक्षा के आरंभ से ही उन्हें परिवार, स्कूल और समाज द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है कि यह विषय उनके लिए बने ही नहीं हैं, उनकी बुद्धि और योग्यता, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन तक ही सीमित है जबकि निरंतर विभिन्न शोध यह इंगित करते रहे हैं कि स्त्री की बौद्धिक क्षमता पुरुष से किसी भी रूप में कमतर नहीं है। अमरीका की *फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी* के ताजा शोध में यह पाया गया कि अधिकतर लड़कियां खुद को लड़कों की अपेक्षा गणित में कमजोर मानती हैं जो उनका भ्रम है। इसी वजह से विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में वे बहुत कम उच्च शिक्षा लेती हैं। जहां तक गणित की बात है तो शोध में लड़कियों और लड़कों के बीच किसी तरह की असमानता से संबंधित कोई अंतर नहीं है। लैंगिक असमानता की पराकाष्ठा यही है कि स्त्री को बौद्धिक स्तर पर पुरुष से कमतर माना जाता है और यह सोच आम से लेकर खास सभी में व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल व्यक्तियों के बीच भी गणित में योग्यता को लेकर पूर्वाग्रह का स्तर वैसा ही है। समान रूप से योग्य होने के बावजूद जहां लड़के कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे नजर आये, वहीं लड़कियों का आत्मविश्वास कमजोर रहा। यह तथ्य शोध पत्रिका, *फ्रांटियर्स इन साइकॉलोजी* के ताजा अंक में प्रकाशित हुआ है।

दलित छात्रों की चुनौतियां, उनकी प्रतिभा से अधिक, उनके प्रति जागित भेदभाव से जुड़ी अधिक है। वर्ष 2013 में भारतीय विश्वविद्यालय पर *किंग्स कॉलेज लंदन* के एक अध्ययन में यह उल्लेखित है कि भारतीय उच्च संस्थानों में दलित छात्रों की योग्यता संशय के घेरे में रहती है और जाति के आधार

पर भेदभाव और उपहास से दलित छात्रों में यह भावना घर कर सकती है कि वे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए योग्य नहीं है।

भाषा की बाधा भी गंभीर

लैंगिक असमानता और जातिगत भेदभाव से लड़ता युवा वर्ग, अपनी आकांक्षाओं को कैसे पूरा करे, यह प्रश्न सहज सुलझता प्रतीत नहीं होता। इन चुनौतियों के जूझने के साथ देश का युवा, अपने ही देश में हिंदी भाषा की उच्च शिक्षा में अवहेलना के कारण, न केवल अपना आत्मविश्वास खो रहा है अपितु अपनी आकांक्षाओं की राह में यह उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती सिद्ध हो रही है। महात्मा गांधी ने कहा था- *यदि हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले तो कम से कम मुझे तो अच्छा ही लगेगा। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है लेकिन वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती...।* तकनीकी पुस्तकों से लेकर राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे तमाम विषयों की पुस्तकों की हिंदी भाषा में अनुपलब्धता के चलते देश के एक बड़े हिस्से को अपने विषय को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है वहीं उनकी रचनात्मकता भी इससे प्रभावित होती है।

वर्ष 2015 में मुंबई स्थित संस्थान *पुकार* द्वारा आठ उच्च शिक्षण संस्थानों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में हिंदी भाषा से स्कूली शिक्षा ग्रहण किये, विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि अंग्रेजी भाषी विद्यार्थियों द्वारा उनके उच्चारण को लेकर माहौल बनाया जाता है वहीं अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों ने माना कि उनकी दृष्टि में हिन्दी बोलने वाले, निम्न सामाजिक प्रस्थिति से ताल्लुक रखते हैं और अल्प ज्ञानी होते हैं।

हिंदी भाषा बोलने और अंग्रेजी ना बोल पाने वाले छात्रों को हेय दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति ने *शिक्षा* के उद्देश्यों पर ही प्रश्नचिह्न अंकित कर दिया है। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि अपने ही देश में *हिंदी मीडियम टाइप* जैसे उलाहने के साथ हिंदीभाषी छात्रों को अलग-थलग करने की प्रवृत्ति उच्च शिक्षा में बदस्तूर कायम है। क्या इससे बड़ी चुनौती किसी देश के लिए हो सकती है कि उसके ज्ञान की निर्भरता, उसकी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा ना होकर किसी अंतरराष्ट्रीय भाषा पर हो।

नवाचार को चाहिए राह

भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं के मध्य एक बड़ी चुनौती, बंधे-बंधाए मार्गों के विपरीत न जाने की भी है। ये इसका कारण परिवार और शिक्षा संस्थाओं में निरंतर दिया जाने वाला, वह मनोवैज्ञानिक दबाव है जो लीक से हटकर सोचने की अनुमति नहीं देता। हाल ही में, प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो कार्यक्रम *मन की बात* में कहा था कि युवाओं को कंफर्ट जोन (सुविधाजनक हालात) से बाहर निकलने, जीवन के नये अनुभव हासिल करने, नयी जगहें देखने, नये काम करने, नये हुनर सीखने की जरूरत है। पर क्या भारतीय युवा ऐसा करने का साहस जुटा पा रहा है? यह संभव नहीं दिखता क्योंकि वह किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचना चाहता है। लाभ और हानि का गणित उन्हें उन्हीं मार्गों की ओर प्रेरित करता है जो सहज हो और अर्थ अर्जन में सहायक हो। हमें यह स्वीकारना ही होगा कि सामान्य जन की नजर में विद्या चाहे जो भी हो *अर्थकारी* होनी चाहिए। शिक्षा की एक अविचारित उदार किस्म की प्रणाली अपनायी गयी, जिसमें बहुत से युवा सिर्फ इसलिए सम्मिलित होते हैं क्योंकि उनके समक्ष इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं होता है।

वर्तमान यथार्थ यह है कि न केवल ज्ञान देने और पाने में बल्कि ज्ञान सृजन में भी सामाजिक संदर्भों की निर्णायक भूमिका होती जा रही है। आज का बदलता सामाजिक संदर्भ उच्च शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को अनुबंधित किये हुए है और यही कारण है कि नवाचारों के मार्ग बेहद संकुचित हैं। हां, राहतभर इतनी सी है कि शनैः शनैः कुछ युवा *उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत* (अर्थात् उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ) के बोध को स्वीकारने लगे हैं। उनके स्वप्नों में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक, आत्मसंतुष्टि के भावों को तुष्ट करने का साहस है। किताबों की दुनिया से बाहर निकल वह नवीन सोच को विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत जो कभी कृषि देश माना जाता था, वर्ष 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या का मात्र 10 प्रतिशत कृषि में संलग्न है। परंतु बीते दशकों, देश का युवा, उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों को छोड़कर इससे जुड़ रहा है क्योंकि उसका मानना है कि भारतीय मूलरूप से किसान हैं और उन्हें अपनी इस स्वभावगत विशेषता का संरक्षण करना चाहिए। वर्ष 2013 में 24 वर्षीय, जैसलमेर के इंजीनियर ने सरकारी नौकरी छोड़कर, एलोवेरा की खेती शुरू की अब सालाना 1.5 करोड़ से 2 करोड़ कमा रहे हैं। वहीं 30 साल के आईटी पेशेवर अभिजीत फाल्के ने महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत के किसानों की तकदीर बदल दी। जनवरी 2012 में *आपुलकी सामाजिक संस्थान* बनाकर, कृषि उत्पादन में लागत कम करना, गुणवत्तापूर्ण कृषि के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना तथा किसानों की पैदावार को दलालों से बचाने के लिए 200 आईटी पेशेवर को अपने साथ जुड़ाने का काम किया। *सैन जॉस विश्वविद्यालय*, कैलिफोर्निया से इलेक्ट्रोनिक्स में मास्टर्स की डिग्री और फिर करोड़ों का कारोबार छोड़ राजस्थान के श्रीगंगानगर के रणदीप सिंह कंग ने जैविक खेती की और किसानों को जोड़ना शुरू किया। वह गोमूत्र की मदद से एक खास किस्म की जैविक खाद बना रहे हैं जिससे फसल की पैदावार बढ़ी है और पानी की खपत कम हुई है।

बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र ने दुनियाभर से ऐसे 50 स्टार्ट अप्स का चयन किया है जिन्होंने धरती की बड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए अलग नजरिया पेश किया हो। इस श्रेणी में देश के 18 वर्षीय स्कूली छात्र अनुभव वाधवा का नाम भी है जिसने *टायरलेस्ली* नाम से स्टार्ट अप की शुरुआत की है। *टायरलेस्ली* टायरों को जलाने से पैदा होने वाली पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्याओं से निपटने का इनोवेटिव समाधान तलाशने में जुटा है। पर्यावरण स्वच्छता की दिशा में इस कार्य के लिए अनुभव को *यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क* के यूथ सॉल्यूशंस रिपोर्ट के पहले संस्करण में स्थान मिला है। अनुभव का उदाहरण, यह बताने के लिए काफी है कि आकांक्षाओं और चुनौतियों के मध्य शिकायतें, व्यवस्था के दोषों को ढूंढने की प्रवृत्ति, आयु का व्यवधान, आर्थिक समस्या और ऐसी ही अनगनित दलीले हैं तो दूसरी ओर इन सबको दरकिनार करते हुए सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने का जुनून। चुनाव हमारा है कि हम आकांक्षाओं के व्यवधान को लेकर नकारात्मक हों, या अपने प्रयासों को लेकर सकारात्मक। ❑

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवा केंद्रित योजनाएं

शुभम वर्मा

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाएं आतंक और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संजीवनी का काम कर रही हैं। 'स्किल डेवलपमेंट' और 'रोशनी' जैसी योजनाओं के तहत जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सहायता प्रदान की जा रही है। पूर्वोत्तर के *कोहिमा* और *नामची* को स्मार्ट शहरों के लिए चुना गया है। कश्मीर के बारामूला में सुपर 30 संस्थान शुरू किया गया। हां, छत्तीसगढ़ में 'प्रयास' नाम से विद्यालय खोले गये। पूर्वोत्तर में मेडिकल, नर्सिंग, स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खोले गये हैं। गुवाहाटी में आईआईटी की नींव रखी गयी है। जम्मू-कश्मीर में 2 नये एम्स खोले जाएंगे वहीं पूर्वोत्तर के लिए स्वस्थ उत्तर पूर्व योजना शुरू की गयी है। इस तरह केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इन क्षेत्रों में विकास की बयार लने के लिए प्रयासरत है

आंकड़ों के अनुसार भारत कुछ ही वर्षों में दुनिया का सबसे युवा देश होगा। इसका मतलब है सबसे अधिक युवा भारत में होंगे तथा कई वर्षों तक भारत दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश बना रहेगा। आर्थिक विशेषज्ञ अपनी दूरदर्शी निगाहों से इसके कई फायदे देख रहे हैं मगर जिस तरह युवा फौज होने के फायदे हैं उसी तरह उसके कुछ अन्य पहलू भी हैं। जैसे कि यदि भारत के सभी युवा, उद्योग तथा रोजगार आदि में लग जाते हैं तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, मगर यदि यही युवा बेरोजगार रहते हैं, तो इनका रुझान गलत दिशा में मुड़ सकता है।

यहां गलत दिशा से अभिप्राय कश्मीर के अलगाववाद, छत्तीसगढ़-झारखंड के माओवाद तथा पूर्वोत्तर के उग्रवाद से है। हाल ही में सुकमा में 25 जवान नक्सली हमले के शिकार हो गये।[1] इसी तरह कश्मीर में पैसे देकर युवाओं से पत्थरबाजी करवाई जा रही है तथा उन्हें आतंकवाद के दलदल में फंसाया जा रहा है।[2] इसी तरह पूर्वोत्तर में असम के दौरे के दौरान शांतिप्रिय दलाई लामा को भी उल्फा के लोगों ने धमकी दी थी।[3] अफसोस की बात यह है के इन सभी घटनाओं में भारत के युवाओं का उपयोग भारत के ही खिलाफ किया गया। अब बात यह आती है कि यदि युवाओं के पास रोजगार तथा काम के साधन होते तो क्या वे इस गलत दिशा में जाते? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2017 के मुकाबले 2018 में बेरोजगारों की संख्या बढ़ने के रुझान हैं।[4] इनके भविष्य के विषय में सोचकर भारत सरकार ने बहुत से सार्थक प्रयास हाल ही के दिनों में शुरू किये हैं। साथ ही साथ उन प्रदेशों में जहां किसी कारणवश आवश्यक सुविधाएं तथा विकास नहीं पहुंच पाया था वहां भी सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिये विकास कार्य तथा रोजगार इत्यादि के कार्य शुरू कर दिए हैं। अधिकतर अलगाववाद, नक्सलवाद या आतंकवाद की घटनाएं छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर में सुनने को आती है अतः इन जगहों पर भारत सरकार ने क्या-क्या योजनाएं उग्रवाद से निपटने तथा युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए शुरू की हैं इस विषय पर इस आलेख में चर्चा की गयी है।

शिक्षा के क्षेत्र में

भारत सरकार देशभर में युवाओं को सही शिक्षा और समस्त आवश्यक संसाधन मुहैया करवाने का प्रयास कर रही है। इसी दिशा में जम्मू-कश्मीर में सरकार ने 02 नये एम्स खोलने तथा स्वास्थ्य स्थिति ठीक करने के लिए 4900 करोड़ रुपये दिए हैं।[5] यही नहीं जम्मू-कश्मीर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने जम्हूरियत और इंसानियत की बात करते हुए 80,000 करोड़ रुपये का फंड जम्मू-कश्मीर को देने की घोषणा की है।[6] अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से 2016 के बीच केंद्र सरकार द्वारा आवंटित फंड का 10 प्रतिशत फंड सिर्फ जम्मू-कश्मीर को दिया गया।[7] इस तरह भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में हालात को बदलने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है।

लेखक दिल्ली स्थित लोकनीति शोध केंद्र (पीपीआरसी) से संबद्ध हैं। नीतिगत मामलों पर शोध व लेखन में रुचि है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवे वेब पोर्टल में नियमित लेखन। ईमेल: theshubhamhindi@gmail.com

यही नहीं हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर के बारामूला में एक सुपर 30 संस्थान शुरू किया जिसमें 26 बच्चों ने दाखिला लिया जिनमें से 15 ने इस बार आई.आई.टी. की प्रवेश परीक्षा पास कर ली है।[8] यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह भारतीय सेना भी कश्मीर के युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए अपनी तरफ से उनसे जुड़ने तथा उन्हें पढ़ाने का प्रयास कर रही है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 35 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को 1000 करोड़ रुपये की राशि दी है। इसमें झारखंड को 457.12 करोड़, छत्तीसगढ़ 228.56 करोड़, बिहार को 171.42 करोड़, ओड़िशा को 57.14 करोड़ और महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना हर एक को 28.57 करोड़ रुपये की राशि नक्सल प्रभावित जिलों के हिसाब से दी गयी है।[9] यह सभी प्रयास इन क्षेत्रों को नक्सल मुक्त बनाने तथा यहां के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किये जा रहे हैं। इसी तरह रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों ने छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रयास नामक विद्यालय खोले हैं। इनमें माओवादी इलाकों के गरीब आदिवासियों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। इस बार इनमें से 27 आदिवासी बच्चों का आई.आई.टी. में चयन हुआ है।[10] छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इन सभी की तारीफ करते हुए, इन बच्चों को लैपटॉप उपहार स्वरूप दिये हैं तथा यह आदिवासियों में यह आशा जगायी है कि वो सब भी माओवाद के जहर से दूर होकर मुख्यधारा से अपने आपको जोड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर में भी प्रधानमंत्री ने 19 जनवरी, 2016 को इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आई.आई.आई.टी.), गुवाहाटी की नींव रखी तथा कई स्किल डेवलपमेंट, मेडिकल, नर्सिंग आदि के कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थान भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं की शिक्षा हेतु खोले गये।[11]

रोजगार के क्षेत्र में

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार एक बड़ी समस्या है तथा उससे भी बड़ी समस्या कौशल विकास की है। इन इलाकों में युवाओं को कौशल तथा हुनर देने के लिए 34 नक्सलवाद-माओवाद प्रभावित जिलों में भारत सरकार की *रोशनी* तथा *स्किल डेवलपमेंट* की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।[12] अब तक रोशनी योजना के तहत बिहार में 1085 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिसकी लागत 16.82 करोड़ रुपये लगी है। इसी तरह 8 *रोशनी* परियोजनाओं में झारखंड के अंदर 3956 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिसका खर्च 100.96 करोड़ रुपये था। इसी क्रम में बिहार और झारखंड को *स्किल डेवलपमेंट* के तहत क्रमशः 41.69 करोड़ तथा 69.48 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।[13]

पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ने नार्थ ईस्टर्न काउंसिल (एन.इ.सी.) के तहत कई *स्किल डेवलपमेंट* के कार्यक्रम शुरू किये हैं जिनमें कक्षा आठ से ऊपर के युवाओं के लिए ब्यूटीशियन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इत्यादि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ एन.इ.सी. ने पूर्वोत्तर के 80 युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करके विवेक विहार, दिल्ली के उच्च स्तरीय कौशल विकास केंद्र में आतिथ्य और रिटेल के प्रशिक्षण हेतु भेजा है। इसके बाद इन्हीं युवाओं को अपना व्यवसाय पूर्वोत्तर में खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तथा इसमें सरकार इनकी मदद कर रही है। इसी के साथ कई शिक्षण संस्थान जैसे, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ आर्किटेकचर एंड प्लानिंग, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, मेडिकल, नर्सिंग, सिविल एविएशन प्रशिक्षण आदि के संस्थान भी पूर्वोत्तर के राज्यों में खोले गये हैं। यही नहीं जब 20 सितंबर, 2016 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने देश में स्मार्ट शहरों की घोषणा की तो पूर्वोत्तर से नागालैंड के *कोहिमा* तथा सिक्किम के *नामची* शहर को चुना गया। इन शहरों को स्मार्ट शहर बनाने में जो रोजगार उत्पन्न होगा उसमें भी पूर्वोत्तर के काफी युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाए हैं।[14]

यही नहीं हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर के बारामूला में एक सुपर 30 संस्थान शुरू किया जिसमें 26 बच्चों ने दाखिला लिया जिनमें से 15 ने इस बार आई.आई.टी. की प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह भारतीय सेना भी कश्मीर के युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए अपनी तरफ से उनसे जुड़ने तथा उन्हें पढ़ाने का प्रयास कर रही है।

मिनिस्ट्री ऑफ डोनर (डेवलपमेंट ऑफ नार्थ ईस्ट रीजन) ने पूर्वोत्तर में नये व्यवसायों को बढ़ावा देने तथा युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने हेतु वेंचर कैपिटल की व्यवस्था की है। इसके लिए 100 करोड़ के फंड की व्यवस्था की गयी है। इसमें आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, पर्यटन इत्यादि के स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जाएगा तथा युवाओं के नये विचारों को व्यवसाय के रूप में ढालने में सरकार पूरी मदद करेगी।[15]

खेलों से संबंधित योजनाएं

खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय ने पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना की शुरुआत कुछ वर्ष पूर्व की थी। इस योजना में गांव-गांव में बच्चों को खेलों से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ब्लाक लेवल पर प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा काबिल युवाओं का चयन करके उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है।[16] आज कई युवा झारखंड तथा पूर्वोत्तर के क्षेत्र से खेलकर देश के लिए पदक जीत रहे हैं तथा दुनिया में भारत का नाम रौशन कर रहे हैं। यही नहीं खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे युवाओं को देश के लिए आदर्श के रूप में स्थापित करने के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है, इसी दिशा में कदम उठाते हुए मणिपुर की एम.सी. मेरिकॉम को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है।[17] इससे पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों का ना सिर्फ मनोबल बढ़ेगा बल्कि खिलाड़ियों को अपनी बात सरकार में रखने का मौका भी मिलेगा।

इसी तरह जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री ने रिलायंस फाउंडेशन के यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव को भी हरी झंडी दिखायी। यह कार्यक्रम भी *युवा एवं खेल मंत्रालय* के *खेलो इंडिया* से जुड़ा हुआ है तथा इसमें जम्मू-कश्मीर के 8 शहरों में छोटे लड़के और लड़कियों के अलग-अलग वर्गों में फुटबॉल मैच करवाए जायेंगे। इस तरह के कार्यक्रमों से बचपन से ही बच्चों में खेल के प्रति जागरुकता बढ़ती है तथा लड़कियों

को भी घर से बाहर निकलकर खेल में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है।[18] इस तरह जम्मू-कश्मीर में युवाओं को खेल से जोड़ने के कई प्रयास किये जा रहे हैं तथा वहां स्टेडियम तथा अन्य खेल के संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। कई शहरों में खेल स्पर्धाओं का आयोजन हो रहा है तथा केंद्र सरकार पिछले वर्ष खेलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये कश्मीर में खेलों को बढ़ाने के लिए दे चुकी है।[19]

नक्सल प्रभावित बस्तर (छत्तीसगढ़) में भी सरकार ने तीरंदाजी तथा शूटिंग की बड़ी अकादमियां खोलने का निर्णय लिया है जिससे यहां के बच्चे भी खेलों से जुड़ सकें तथा देश की मुख्यधारा में आकर अपना भविष्य सुधार सकें। इसके पीछे मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वहां के लोगों के हुनर को कारण बताया, उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चे तीर-कमान से बचपन से ही जुड़े होते हैं तथा इसे उठाना उनके लिए बहुत ही सहज होता है अतः इस इलाके में तीरंदाजी की अकादमी खुलने से इनके हुनर को और ज्यादा निखारा जा सकता है तथा बाद में ये बच्चे तीरंदाजी में देश के लिए पदक जीत सकते हैं।[20]

स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं

उग्रवाद तथा आतंकवाद प्रभावी इलाकों में तथा आदिवासी इलाकों में सरकार युवाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है तथा कई ऐसी योजनाएं इन इलाकों के लिए बनायी जा रही हैं जिससे युवाओं के स्वास्थ्य तथा रोजगार की स्थिति को इन इलाकों में सुधारा जा सके। प्रधानमंत्री ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के लिए 19000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जिनमें से 4900 करोड़ रुपया जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं पर खर्च होने वाला है जिसमें 2 एम्स बड़े शहरों में खोले जायेंगे तथा प्राथमिक उपचार केंद्र और बाकी अस्पतालों को भी और अधिक सुधारा जाएगा।[21]

उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए *स्वस्थ उत्तर पूर्व* योजना की शुरुआत की गयी है जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसमें कई प्राथमिक उपचार करने वाले चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा तथा पहले चरण में अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम में कार्य शुरू किया जाएगा उसके बाद बाकी राज्यों में भी इसे फैलाया जाएगा। इसमें चिकित्सक, सरकारी कर्मचारी, नर्स इत्यादि को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा सार्वजनिक-निजी के तालमेल से चिकित्सा तंत्र में भी सुधार किया जाएगा।[22]

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत सरकार तथा राज्य सरकारें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक तथा खेलों से लेकर रोजगार एवं उद्यमिता से युवाओं को जोड़ने का सराहनीय प्रयास कर रही हैं। इससे बहुत सी जगहों पर उग्रवाद, अलगाववाद तथा आतंकवाद में कमी आयी है। यही नहीं विमुद्रीकरण जैसे फैसलों से सरकार ने काले धन से पनपने वाले उग्रवाद पर भी बहुत हद तक रोक लगा दी है। हाल ही के दिनों में बहुत से नक्सलियों ने पैसे के अभाव में उग्रवाद का रास्ता छोड़ कर आत्मसमर्पण किया है।[23] कश्मीर में भी युवा अब खुलकर बोलने लगे हैं कि वो अपनी मर्जी से पत्थर नहीं फेकते बल्कि बेरोजगारी के कारण उनसे पैसे देकर तथा डरा धमकाकर पत्थर फिकवाने तथा आतंक फैलाने के काम करवाए जाते हैं।[24] इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों में भी नागा पीस एकॉर्ड (नागा शांति समझौता) के तहत वहां के अलगाववादियों ने भी हथियार छोड़कर सरकार के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है।[25] यह सभी कुछ संभव हुआ है सरकार की प्रभावी योजनाओं तथा कड़े फैसलों के कारण, इसी दिशा में सरकार को अब उन सुदूर इलाकों में पहुंचना चाहिए जहां पिछले 65 वर्षों में सरकारें किसी कारणवश नहीं पहुंच सकी ताकि वहां के युवाओं से संवाद कायम हो सके, तथा भारत के हर युवा को स्वास्थ्य, रोजगार तथा मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। संवाद के अभाव के कारण ही अलगाववादी तथा उग्रवादी तत्व युवाओं को भड़काने में कामयाब हो जाते हैं यदि उचित संवाद सरकार तथा जनता में बना रहे तो भारत के युवा देश को विश्व शक्ति के रूप में पुनः स्थापित कर सकते हैं। ❑

सन्दर्भ

1. http://indiatoday.intoday.in/story/naxalites-attack-crpf-camp-chhattisgarh-sukma-jawans/1/936827.html
2. http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-4362020/Kashmiri-stone-pelters-admit-paid-film.html
3. http://www.hindustantimes.com/india-news/ulfa-i-warns-dalai-lama-against-making-anti-china-comments-during-assam-visit/story-87X6h64PxMuJHtvBeglk3H.html
4. http://timesofindia.indiatimes.com/india/unemployment-in-india-to-increase-marginally-in-2017-18-un-report/articleshow/56512962.cms
5. http://www.thehindu.com/news/national/prime-minister-narendra-modi-announces-rs80000cr-package-for-jk/article7854735.ece
6. http://www.thehindu.com/news/national/prime-minister-narendra-modi-announces-rs80000cr-package-for-jk/article7854735.ece
7. http://www.thehindu.com/news/national/other-states/JampK-gets-10-of-Central-funds-with-only-1-of-population/article14506264.ece
8. http://www.hindustantimes.com/education/15-kashmir-students-coached-by-us-cracked-jee-main-2016-army/story-MlHd4Ij1s3vY6W5eg7faQI.html
9. http://indiatoday.intoday.in/story/rs-1000-crore-grant-to-35-worst-naxal-affected-districts-in-7/1/564003.html
10. http://www.hindustantimes.com/india-news/chhattisgarh-s-prayas-initiative-helps-27-tribal-students-script-iit-success-story/story-4Rjtn0awxhuFu2N51zkA6N.html
11. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155853
12. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116427
13. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116427
14. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155853
15. http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/nedfi-and-ministry-of-doner-to-set-up-rs-100-crore-venture-fund-for-the-north-eastern-region/articleshow/53743582.cms
16. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=123456
17. http://indianexpress.com/article/sports/sport-others/mary-kom-juggling-life-as-boxer-and-rajya-sabha-mp-4520762/
18. http://jammulinksnews.com/newsdetail/100210/Jammu-Links-News-Sports_can_be_a_means_for_national_integration_Modi?fromNewsdog=1&utm_source=NewsDog
19. http://www.indiatvnews.com/news/india/modi-government-plans-to-engage-kashmiri-youths-through-sports-53833.html
20. http://www.financialexpress.com/india-news/sports-academies-to-explore-young-talent-in-naxal-hit-bastar/379210/
21. http://www.deccanchronicle.com/nation/cuUkent-affairs/270417/modi-govt-releases-rs-19000-crore-for-development-of-jk.html
22. http://www.business-standard.com/article/news-ians/swasth-uttar-purva-initiative-to-boost-healthcare-in-ne-117032300024_1.html
23. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Demonetisation-leads-to-largest-Maoist-suUkenders/articleshow/55675983.cms
24. http://indiatoday.intoday.in/story/jammu-and-kashmir-stone-pelters-hizbul-mujahideen-burhan-wani/1/915751.html
25. http://indianexpress.com/article/explained/simply-put-towards-accord-step-by-step/

MIT-SOG

UNESCO Chair for Human Rights, Democracy, Peace & Tolerance World Peace Centre (Alandi) Pune, India

Educated Politicians Are Making A Difference...

OPT for a career in Politics!

Inviting applications from bright graduates for

MASTER'S PROGRAM IN GOVERNMENT (MPG)

One-year Post Graduate Program

You can be ..

- **Elected Representative** For better Governance
- **Political Analyst** To measure whether Policies are helpful
- **Constituency Manager** For effective policy execution from people perspective
- **Campaign Manager** For clean & Effective Campaigns

In Politics, not all leaders are corrupt. Most of them are clean. Join Politics to Make a Difference!

Rahul V. Karad, Founder

ADMISSIONS OPEN

Batch Commences, AUGUST 1, 2017

Apply online at : **www.mitsog.org**

MAEER's

MIT SCHOOL OF GOVERNMENT | Estd.: Sept. 2005 | PUNE | INDIA

First ever Leadership Institute in India & Asia for a Career in Politics

9850897039, 7720061611

9146038947

POLITICS AS THE BEST CAREER OPTION!

India needs leaders who are dynamic, proactive, capable and knowledgeable. All professions including Medicine, Engineering, Pharmacy, Management, Law etc. employ educated & skilled people in their respective fields. Then why not in Politics, which is as crucial as it concerns the wellbeing of nation and its populace at large. We have under graduate and post graduate programs to address the challenges of other sectors but none for those who envision to enter into politics in a professional way. When we look at the present political scenario, we all feel that India needs Leaders who have a fair idea about what is happening and what they need to do when they take over the mantle. But how do they go about it? Like getting proper guidance, training, knowledge whereby they can form their own perspective, and giving better guidance when leading the country and its citizens. Today's political environment demands knowledge & skills- like Foreign Policy, Political Economy, International relations, Public Policy, Constitution, Five Tier Structure and grass root politics required to win the elections, Election Management, Constituency Development etc.

The political leaders in their active public life are concerned mostly with Social Work focusing on policies related to betterment of the masses. They require trained/skilled manpower to assist them in this endeavor in the following areas- Political Analyst, Political Strategist, Election Consultants, Constituency Managers, Public Relation officer, Social Media analyst, Brand consultants etc.

All these positions require good analytical, research, managerial, leadership & communication skills along with good decision making power. Many professionals work for government and make excellent money, enjoy security in their positions. Think tanks and private firms also provide job opportunities, although the pay in such cases can vary, depending on the grants received and the group's political affiliations. These professionals represent the country in international forums, indulging in debates of grave importance, having meetings with international leaders, passing of bills in parliament etc. They assist to resolve the internal problems and issues as well as we need to make good relation with the other nation.

As professionals work for a corporate organization to enhance its brand equity, a healthy balance sheet and a good customer feedback, politicians are striving hard for their respective political parties and constituency. MIT School of Government, Pune established in 2005, is the only institute in the country to provide experiential learning and training to the young, dynamic leaders of India to take up challenging positions and leadership roles in the democratic fabric of the nation.

युवा शक्ति और विज्ञान

मनीष मोहन गोरे

सुश्रुत, चरक, कणाद, पतंजलि, आर्यभट्ट, वाराहमिरिह, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन और भास्कर जैसे मनीषियों ने जिस वैज्ञानिक परिपाटी की नींव रखी उसे आज सीएसआईआर, इसरो और डीआरडीओ जैसी संस्थाएं आगे बढ़ा रही है। वर्तमान सरकार भी देश की युवा शक्ति को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में शोध के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंस्पायर, किरण व क्यूरी जैसी सार्थक योजनाएं चला रही है। इंस्पायर और राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस जैसी योजनाएं युवाओं में वैज्ञानिक शोध की उत्कंठा को बढ़ाने का काम कर रही है

विज्ञान प्रकृति के रहस्यों को समझने का एक तरीका या जरिया होता है और वैज्ञानिक, विज्ञान के व्याकरण की एक निश्चित परिपाटी के सहारे प्रकृति की घटनाओं को अनावृत्त करते हैं। प्रौद्योगिकी विज्ञान के सिद्धांतों का व्यावहारिक पक्ष होता है जिसके द्वारा मानव जीवन को सहूलियत मिलती है। बाहर से तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जटिल व गंभीर जान पड़ते हैं मगर सिक्के के दूसरी ओर सरलता और आनंद से भरा पहलू विद्यमान है। बताने-समझाने वाला अगर गतिविधि या जीवन से जोड़कर इसे बताएगा तो विज्ञान एक आनंद से भरे विषय के रूप में सामने आयेगा। अधिगम के इस मुहाने पर शिक्षक की भूमिका अहम होती है। साल 2005 में *नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च* के डा. राजेश शुक्ला ने भारत के तमाम स्कूलों में सर्वेक्षण के बाद अपनी इंडिया साइंस रिपोर्ट में इस तथ्य को उजागर किया था कि प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद अधिकांश बच्चे आगे की पढ़ाई में विज्ञान लेने से इसलिए हिचकते हैं क्योंकि शिक्षकों ने उनमें विज्ञान को लेकर रुचि नहीं जगाई और इससे बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई से डर लगने लगा। यही वजह रही कि आधुनिक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अध्ययन-अनुसंधान के प्रति युवाओं में खासी दिलचस्पी नहीं हो सकी।

वैसे इस मुद्दे की समीक्षा करने पर यह ज्ञात होता है कि भारत का अतीत विज्ञान और तकनीक में समृद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मोहन जोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में उस युग के अवशेषों से यह उजागर होता है कि वे शहर सुनियोजित थे। इनमें जल आपूर्ति, जल-मल निकास और भवन निर्माण में वैज्ञानिकता के स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलते हैं। सुश्रुत, चरक, कणाद, पतंजलि, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन और भास्कर जैसे भारत के विज्ञान अग्रदूतों के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है। हमारे देश में विज्ञान का स्वर्ण युग 400 ईसा पूर्व से लेकर सातवीं शताब्दी तक था। मौर्य, शक, कुशाण और गुप्त साम्राज्यों में विज्ञान की खूब उन्नति हुई। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय इसी अवधि की देन हैं। वह युग गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में यहां अभूतपूर्व प्रगति का साक्षी बना। शून्य की परिकल्पना इसी युग में अस्तित्व में आयी। मध्य युग में जहांगीर की प्रकृति, वनस्पति विज्ञान और बागवानी में और सवाई जयसिंह द्वितीय की खगोल विज्ञान में रुचि भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरक रही है।

वहीं आजादी से पहले के युग में व्यक्तिगत और संस्थागत स्तरों पर वैज्ञानिक अवदान के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय प्रयास हुए। असंख्य विख्यात और अल्पज्ञात वैज्ञानिकों ने आधुनिक भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव रखी। चंद्रशेखर वेंकटरामन कलकत्ता में प्रशासनिक सेवा करते थे। कार्यालय के रास्ते में *इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस* नामक विज्ञान अध्ययन और लोकप्रियकरण की संस्था पड़ती थी। रामन उस संस्था में आने-जाने लगे और वैज्ञानिक शोध में रुचि के कारण उससे जुड़ गये। पराधीन देश में रामन को विज्ञान का पहला नोबल पुरस्कार मिला जिससे देश का गौरव बढ़ा। हालांकि यह पुरस्कार लेते हुए जब रामन को भारतीय ध्वज के नीचे बैठाया गया तो उन्हें यह सोचकर रोना आ गया कि उनका देश पराधीन है। दूसरा विचार मंथन का विषय है कि पराधीनता के दौर में नोबल जैसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान पाने वाला देश आजादी के बाद कोई वैज्ञानिक स्वाधीनता में रहते हुए नोबल क्यों नहीं ला पाया जबकि फंड और संसाधनों की कोई कमी अब नहीं है लेकिन तब थी इसलिए रामन को अपने शोध के संबंध में कुछ हजार रुपयों के लिए एक उद्योगपति से गुजारिश करनी पड़ी थी।

लेखक विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में सेवारत हैं और 1995 से विभिन्न संचार माध्यमों के लिए लोकप्रिय विज्ञान लेखन कर रहे हैं। ईमेल : mmgore@vigyanprasar.gov.in

उसी दौर में देश के अनेक हिस्सों में बच्चों और युवाओं के मन में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करने के लिए अनेक व्यक्ति तथा संस्थाएं काम कर रही थीं। इनमें से एक थे पंजाब के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रुचिराम साहनी (प्रसिद्ध भारतीय पुरावनस्पति वैज्ञानिक बीरबल साहनी के पिता) जो अपने नियमित अध्यापन में वैज्ञानिक उपकरणों की कमी से व्यथित रहते थे। मगर विपरीत परिस्थितियों से उन्होंने हार न मानी। स्वयं के बनाये यंत्रों का सहारा लेकर उन्होंने विद्यार्थियों को प्रयोग करके विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने का उल्लेखनीय प्रयास किया। इतना ही नहीं, कॉलेज से अलग हटकर भी वे गली-मोहल्लों में वैज्ञानिक प्रयोग और उनकी रोचक व्याख्या करते थे। विज्ञान से जुड़े इन जन व्याख्यान को सुनने में युवाओं के अलावा आम लोगों को भी बहुत आनंद आता था। रुचि राम के ये वैज्ञानिक व्याख्यान इस कदर लोकप्रिय हुए कि लोग एक आने दो आने का टिकट लेकर उन्हें सुनने के लिए आने लगे। विज्ञान के इस गुमनाम सिपाही के इस महत्वपूर्ण योगदान को शायद कोई जान भी न पाता, अगर डीएसटी (भारत सरकार) की विज्ञान संचार से जुड़ी राष्ट्रीय संस्था विज्ञान प्रसार के निदेशक नरेंद्र कुमार सहगल और वहां के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुबोध महंती ने विशेष प्रयास न किये होते। पंजाब जाकर उन्होंने इस विस्मृत वैज्ञानिक एवं विज्ञान संचारक के जीवन और कार्यों की खोजबीन की तथा एक पुस्तक (मेमोआयर्स आफ रुचि राम साहनी: पायनियर ऑफ साइंस पापुलराइजेशन इन पंजाब) को युवाओं की प्रेरणा के लिए प्रकाशित किया। इस तरह के छिटपुट प्रयास पूरे देश में चल रहे थे लेकिन इनका समाज और युवाओं पर व्यापक असर नहीं हो सका क्योंकि यह सब कुछ एकजुट होकर नहीं हो रहा था।

सीएसआईआर: प्रतिभाओं की प्रयोगशाला

1947 में देश की आजादी के बाद धीरे-धीरे सरकारी संस्थाओं का जाल बिछाकर युवाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान की भावना उत्प्रेरित करने का प्रयास शुरू किया गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही *वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)* की। वर्तमान में पूरे देश में फैली 37 प्रयोगशालाओं के इस समूह की स्थापना 1942 में की गयी थी।

सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान, मेटलर्जी, रसायन विज्ञान, पुरावनस्पति विज्ञान, खनन, पेट्रोलियम, चमड़ा, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और पर्यावरण विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान किये जाते हैं। सीएसआईआर भारत में युवाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म मुहैया कराता है। इन प्रयोगशालाओं में करीब 20 हजार वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं और बीसवीं सदी के आखिरी दशक तक सीएसआईआर ने कुल 1376 प्रौद्योगिकियों/नॉलेजबेस विकसित कर लिये थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में शोध करने वाले वैज्ञानिकों के लिए सीएसआईआर का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करना एक बड़े सम्मान की बात मानी जाती है। इसमें पांच लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि के अतिरिक्त विजेता वैज्ञानिक को उसके 65 वर्ष की उम्र तक रु. पंद्रह हजार की प्रोत्साहन राशि प्रति माह प्रदान की जाती है। देश के युवा वैज्ञानिक यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने के लिए अपने अनुसंधान की गुणवत्ता में कोई कसर नहीं छोड़ते।

दुनियाभर में सीएसआईआर की प्रसिद्धि

वैज्ञानिक और तकनीकी शोध की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त साइंस साइटेशन इंडेक्स (एससीआई) शोध जर्नलों में सीएसआईआर के वैज्ञानिक उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। वर्ष 2013 से लेकर 2015 के दौरान इन शोध पत्रों की संख्या और प्रति शोध पत्र इम्पैक्ट फैक्टर निम्न प्रकार है:

वर्ष	शोध पत्र
2013	5086
2014	6092
2015	5797

हाल के वर्षों में, सीएसआईआर ने मानव संसाधन और खास तौर पर युवाओं में वैज्ञानिक शोध प्रवृत्ति के विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। इस दिशा में पहल करते हुए सीएसआईआर के साथ वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में 8000 से अधिक रिसर्च फैलो, 159 वरिष्ठ अनुसंधन एसोशिएट्स और विभिन्न विश्वविद्यालयों की 1000 से अधिक अनुसंधान योजनायें संबद्ध हैं जिन्हें देश का अग्रणी प्रयोगशाला समूह समुचित सहयोग प्रदान कर रहा है। इसमें सर्वाधिक संख्या युवा शोधार्थियों की है।

ग्रेविटेशनल वेव संबंधी *सर्न* के बृहद वैज्ञानिक अनुसंधान में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका, चंद्रयान, मंगलयान और भारत द्वारा 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के नये कीर्तिमान से *भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)* का बड़ा सपना साकार हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान और इससे अनुप्रयुक्त शाखाओं में शोध का यह राष्ट्रीय मंच है तथा जो युवा इसरो में वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, उनके लिए वहां आने के अवसर उपलब्ध हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल, भौतिकी, जलवायु विज्ञान जैसे विषय में योग्यता रखने वाले होनहार अभ्यर्थी इसरो से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार रक्षा *अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)* भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन एक महत्वपूर्ण इकाई है जो रक्षा प्रणालियों के डिजाइन और विकास का कार्य करता है। यहां पर देश की तीनों सेनाओं के लिए हथियार प्रणाली और उपकरणों का निर्माण किया जाता है। डीआरडीओ में भी वैज्ञानिक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर खुलते हैं।

सीएसआईआर और डीआरडीओ के अलावा भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग में युवाओं के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को अपना करियर बनाने के अनेक सुअवसर हैं। इन विभागों के लक्ष्य और विशेष कार्यक्रमों के लिहाज से यहां शोध के अवसर आते हैं इसलिए युवाओं को अपनी विशेषज्ञता/निपुणता के अनुसार इन वैज्ञानिक विभागों में आवेदन करना चाहिए।

युवा व वैज्ञानिक शोध

देश की युवा शक्ति को विज्ञान और तकनीक के विविध क्षेत्रों में शोध के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों और विभागों की ओर से अनेक सार्थक योजनाएं चलायी जाती रही हैं। युवाओं के मन में वैज्ञानिक शोध में अपने करियर निर्माण के लिए ये योजनाएं उत्प्रेरक का काम करती हैं।

किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों तथा कॉलेज स्तर पर स्नातक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका संयोजन भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु करती है। यह योजना अपने संक्षिप्ताक्षर *केवीपीवाई* के नाम से अधिक लोकप्रिय है। इसके अंतर्गत बच्चों और युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा औषधि के क्षेत्रों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इस छात्रवृत्ति योजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने प्रारंभ किया था। इस योजना का मुख्य मकसद प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूलभूत विज्ञान की शाखाओं में अनुसंधान करियर निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है। इस विधि से चयनित केवीपीवाई अभ्यर्थी को पूर्व-पीएचडी स्तरों तक छात्रवृत्ति एवं आकस्मिक अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें देश के प्रतिष्ठित शोध संस्थानों और अकादमियों में ग्रीष्मकालीन शिविरों में भी शामिल किया जाता है।

वर्ष 2015-16 में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की राष्ट्रीय परीक्षा में कुल लगभग एक लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें से ग्यारहवीं कक्षा के 881, बारहवीं के 1554

और मूलभूत विज्ञान स्नातक प्रथम वर्ष के 96 विद्यार्थियों का चयन किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति के लिए किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की बेंगलुरु स्थित संस्था जवाहरलाल नेहरु सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर) विज्ञान के विद्यार्थियों को विज्ञान के अध्ययन और शोध की ओर आकर्षित करने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम (स्टूडेंट बडी प्रोग्राम) आयोजित करता है। इसके अंतर्गत जवाहर नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को जेएनसीएएसआर की प्रयोगशालाओं में चल रहे शोध के बारे में आंखों देखा हाल बताया जाता है। इस प्रेरणादायी प्रयास में अभी तक लगभग 800 से भी ज्यादा विद्यार्थी हिस्सा ले चुके हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की एक और स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार स्कूल और स्कूल के बाहर दोनों प्रकार के बच्चों को विज्ञान शिक्षण और शोध की धारा से जोड़ने के अनेक प्रयास कर रही है। विपनेट साइंस क्लब इसी तरह का एक अनोखा अभियान है जिसके अंतर्गत पूरे देश में कुल 12500 विज्ञान क्लब सक्रिय हैं। प्रत्येक वर्ष विज्ञान प्रसार विद्यार्थियों को विज्ञान की जानकारी रोचक ढंग से समझाने के लिए मई के महीने में समर साइंस फेस्टिवल और साइंस फ्यूजन कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें बच्चों को हैंड्स ऑन गतिविधि, रोबोटिक्स, फूड, हाइजिन, ओरिगैमी, नेचर वाच, नाइट स्काई वाचिंग, साइंस फिल्म शो के जरिये स्कूली परिपाटी से अलग करके सीखो वाले तरीके से विज्ञान की बारीकियों को बताया जाता है। इस कार्यक्रम में अभी तक 3000 से ज्यादा बच्चे हिस्सा ले चुके हैं।

महिला वैज्ञानिक योजना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने बालिकाओं (महिलाओं) को वैज्ञानिक शोध से जोड़ने के लिए *महिला वैज्ञानिक योजना* की शुरुआत की जिसमें महिलाओं ने आशातीत रुचि दिखायी। विभाग ने वर्ष 2014 में इस योजना का नया नामकरण करके इसे *किरण* (नॉलेज इंवोल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नरचरिंग) बना दिया। इस योजना के माध्यम से विज्ञान में शिक्षित महिलाओं को शोध के साथ-साथ स्वरोजगार से भी जोड़ा जाता है। *किरण* योजना की एक और शाखा बनायी गयी है जिसे *क्यूरी* (कॉसोलिडेरान ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सिलेंस इन वूमेन यूनिवर्सिटी) जो विश्वविद्यालय स्तर पर मेधावी छात्राओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में प्रशिक्षण देकर उन्हें आगे शोध की तरफ उन्मुख करती है।

महिलाओं को वैज्ञानिक शोध की ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण महिला वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं। यह जुड़ाव संख्या के अलावा गुणात्मक दृष्टि से भी अहम है। वर्ष 2014 से लेकर 2017 के तीन वर्षों के दौरान जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक और गणितीय विज्ञान, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विज्ञान जैसी विज्ञान की धाराओं के अंतर्गत इस योजना हेतु कुल 3095 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 646 को वित्तीय सहायता दी गयी है।

इंस्पायर योजना/राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस

युवा प्रतिभाओं को विज्ञान में शोध की ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की एक और अहम योजना है *इंस्पायर* (इनोवेशन इन साइंस पर्स्युट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च)। इस योजना का मुख्य मकसद युवाओं को विज्ञान के अध्ययन से जोड़कर उन्हें शोध की दिशा में प्रोत्साहित करना है ताकि वे आगे चलकर देश के वैज्ञानिक शोध आधार को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सकें।

इंस्पायर इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत विज्ञान के विद्यार्थियों को साइंस कैंप में आमंत्रित कर भारत और विदेश के प्रख्यात वैज्ञानिकों (नोबेल विजेता सहित) से संवाद का अवसर प्रदान किया जाता है। 2016-17 तक ऐसे कुल 204 साइंस कैंप आयोजित किये जा चुके हैं जिनमें 35050 विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की है।

2016-17 में इंस्पायर की उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 16388 विद्यार्थियों को मूलभूत विज्ञान की शाखाओं में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति दी गयी।

इंस्पायर योजना के अंतर्गत अभी तक 13. 86 लाख इंस्पायर पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इसमें से लगभग 47 प्रतिशत विजेता लड़कियां हैं और 26 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं।

10-11 दिसंबर 2016 को डीएसटी द्वारा सीएसआईआर-एनपीएल (नयी दिल्ली) में आयोजित इंस्पायर पुरस्कार समारोह में पूरे देश से कुल 560 छात्र-छात्राओं को पुरस्कार के लिए चुना गया। इस कार्यक्रम में डॉ. हर्षवर्धन, माननीय मंत्री, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा बच्चों द्वारा विकसित शीर्ष 60 नवाचारी परियोजनाओं को सम्मानित किया गया।

इंस्पायर के समांतर ही बाल मन में विज्ञान और इसके प्रयोगों के जरिये शोध की प्रवृत्ति उत्पन्न करने का एक और दूसरा अनोखा मंच है *राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस*। इस सोच का आगाज सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के ग्वालियर साइंस सेंटर नामक एक एनजीओ में हुआ था जिसे बाद में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार) ने अपना लिया। आज इस नवाचारी कार्यक्रम को लगभग दो दशक पूरे हो गये हैं। इसके अंतर्गत जिला और राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस से छंटनी होते हुए युवा वैज्ञानिक इसकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं। दस से लेकर सत्रह वर्ष की आयु सीमा वाले बच्चे और किशोर इस वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये वैज्ञानिक थीम विशेष पर माइक्रो लेवल पर शोध परियोजनाओं का निर्माण करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिये बच्चों और किशोरों में खोजी प्रवृत्ति और वैज्ञानिक सोच का उन्मेष होता है। इसमें प्रति वर्ष हजारों की संख्या में बच्चे हिस्सा लेते हैं।

तालिका 1: महिला वैज्ञानिक योजना आवेदन

विषय	2014-15	2015-16	2016-17
जीव विज्ञान	749	410	763
रसायन विज्ञान	118	92	167
भौतिक और गणितीय विज्ञान	61	96	104
पृथ्वी और वायुमंडल विज्ञान	69	26	46
अभियांत्रिकी	95	105	194

युवाओं में शोध की जबरदस्त उत्कंठा

इंस्पायर और *राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस* जैसी नवाचारी विज्ञान शोध की उत्प्रेरक योजनाओं की अपार सफलता को देखकर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक शोध को लेकर बेहद उत्कंठा है। उन्हें केवल उचित प्लेटफार्म और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बुनियादी स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को विज्ञान में रुचि पैदा करने की कोशिश सबसे जरूरी है और इसमें प्राथमिक शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसा कि इस लेख के आरंभ में बताया गया है कि शिक्षकों की लापरवाही के चलते बच्चे विज्ञान में रुचि नहीं लेते और उसकी पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं। इस तरह विज्ञान से बच्चे उचित शिक्षण के अभाव में विमुख हो रहे हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर तक अगर विद्यार्थी बेरुखी से पढ़कर विज्ञान में शोध करने पहुंचे भी तो देश और समाज को उस शोध से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। युवाओं को विज्ञान में रुचि जगाने की दिशा में विज्ञान संचार से जुड़ी गतिविधियां भी प्रेरक साबित होती हैं। जैसे विज्ञान लेखकों द्वारा लिखी वैज्ञानिकों की प्रेरक जीवनियां पढ़कर युवा उनके जैसा वैज्ञानिक बनने की सोचता है। हमारे देश को यदि रामन, भाभा, रामन्ना और कोठारी चाहिए तो युवाओं को प्रेरणा देने तथा उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि विकसित करने वाली योजनाओं तथा कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित करना होगा। ❑

You Deserve the Best...

IAS GS World PCS

Committed to Excellence

ISO 9001 : 2008 Certified

Distance Learning Programme

30 Booklets ₹ 12,500/-

सामान्य अध्ययन

(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

M.D.: Niraj SIngh | IAS : 2017-18 | Divyasen Singh (Co-ordinator)

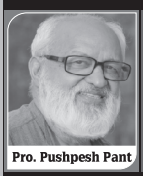

सामान्य अध्ययन

दिल्ली केन्द्र

नि:शुल्क कार्यशाला

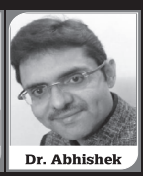

10 JUNE 27

11:45 AM | 06:30 PM

वैकल्पिक विषय

इतिहास By मणिकांत सिंह

भूगोल By आलोक रंजन

राजनीति विज्ञान By वी.के. त्रिपाठी

इलाहाबाद केन्द्र

06 JUNE 8:00 AM

Complete Prepration for IAS/PCS GS Foundation Batch

20 JUNE 5:00 PM

लखनऊ केन्द्र

सामान्य अध्ययन

Gateway Batch/ UP Special

05 JUNE 28

08:00 AM | 06:00 PM

जयपुर केन्द्र

Complete prepration for IAS/RAS Foundation Batch

20 JUNE 8 AM / 5 PM

DELHI CENTRE	ALLAHABAD CENTRE	LUCKNOW CENTRE	JAIPUR CENTRE
705, 2nd Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Ph.: 011-27658013, 7042772062/63	GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad Ph.: 0532-2266079, 8726027579	A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow Ph. : 0522-4003197, 8756450894	Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr, Near Mahesh Ngr Police Station, Jaipur Ph. :7340020323, 7340020324

http://www.gsworldias.com | http://facebook.com/gsworld1 | 9654349902

जीएसटी: परिवर्तन का वाहक

डी एस मलिक

अब जीएसटी के बारे में और इसके प्रभावों के बारे में किसी भी प्रकार की शंका/भ्रम एवं संदेह दूर करने के लिए हितधारकों तथा आम जनता को जागरूक बनाने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने पर मुख्य जोर रहेगा। छोटे कारोबारियों एवं व्यापारियों को जीएसटी तथा उससे संबंधित विधानों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी और यह भी समझाना होगा कि उन्हें कर रिटर्न ऑनलाइन कैसे दाखिल करना है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कैसे करना है। सरकार अप्रत्यक्ष कर के इस बड़े सुधार को 1 जुलाई, 2017 से लागू करने के लिए अब पूरी तरह कृतसंकल्प तथा आशान्वित है

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का बीज 28 फरवरी, 2006 के ऐतिहासिक बजट भाषण में बोया गया, जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री ने देश में जीएसटी लागू करने के लिए 1 अप्रैल, 2010 का दिन निर्धारित किया। उसके बाद से देश में जीएसटी लागू करने के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं, जिनकी परिणति 122वें संविधान संशोधन का विधेयक पेश होने के साथ दिसंबर, 2014 में हुई है।

जीएसटी क्यों?

आम बहसों में यह बात हमेशा सुनायी पड़ती है कि जीएसटी लागू करने की क्या जरूरत है? इस प्रश्न के उत्तर में हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर के वर्तमान ढांचे को समझना आवश्यक है। फिलहाल केंद्र सरकार विनिर्माण पर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क), सेवाओं की आपूर्ति पर (सेवा कर), दो राज्यों के बीच वस्तुओं की बिक्री पर (केंद्र द्वारा लगाये जाने वाले केंद्रीय बिक्री कर को इकट्ठा करके राज्य अपने पास रखते हैं) और राज्य सरकार खुदरा बिक्री पर (वैट) तथा राज्य में वस्तुओं के प्रवेश पर (प्रवेश कर) कर लगाती है। साथ ही विलासिता कर और खरीद कर आदि भी लगाए जाते हैं। यह स्पष्ट है कि एक ही आपूर्ति श्रृंखला पर विभिन्न प्रकार के कर लगाये जा रहे हैं।

इससे उपभोक्ताओं पर करों का कई गुना बोझ पड़ता है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा वसूले गये करों को राज्य सरकार द्वारा वसूले गये करों के एवज में माफ नहीं किया जाता। यहां तक कि राज्य सरकारें जिन निर्धारित करों को वसूलती हैं, उन्हें वसूले जाने वाले अन्य करों के भुगतान के बदले माफ नहीं करती। इसके अलावा देश में वैट के विविध कानून, कर की दरों में विषमताएं और कर की अलग-अलग प्रणालियां देश को अलग-अलग आर्थिक दायरों में बांट देती हैं। चुंगी, प्रवेश कर, चेक चौकियों जैसे शुल्क एवं गैर-शुल्क अवरोध बनाने से देशभर में व्यापार के मुक्त प्रवाह में रोड़े आते हैं। इसके अलावा करों की भारी संख्या करदाताओं के लिए बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि ढेर सारे रिटर्न, भुगतान आदि करने पड़ते हैं।

क्या है जीएसटी?

पहले बताये गये सभी अप्रत्यक्ष करों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कहलाने वाले इकलौते कर में मिला देने का प्रस्ताव है, जो कर विनिर्माण अथवा आयात से शुरू होने वाली और खुदरा के अंतिम स्तर तक जाने वाली आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर वसूला जाएगा। इसलिए वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर अभी केंद्र अथवा राज्य सरकारें जो भी कर लगाती हैं, वे कर जीएसटी में समा जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार जीएसटी दोहरा कर होगा, जिसमें केंद्र सरकार केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) लगाएगी और वसूलेगी तथा राज्य सरकारें राज्य के भीतर होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही पर राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) लगाएगीं और वसूलेगीं। केंद्र दो राज्यों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) भी लगाएगा और वसूलेगा। इस तरह जीएसटी करों का एकीकरण करने वाला है, जो फिलहाल केंद्र तथा राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों को मिला देगा और देश के आर्थिक

लेखक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय में अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) हैं तथा वित्त एवं कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के लिए मीडिया एवं प्रचार के प्रभारी हैं। ईमेल: dprfinance@gmail.com

एकीकरण को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगा।

इस कर सुधार से एकल राष्ट्रीय बाजार, समान कर आधार एवं केंद्र तथा राज्यों के लिए समान कर कानूनों का सृजन होगा। जीएसटी इस बात का उदाहरण है कि हमारे संविधान में निर्धारित किया गया सरकार का संघीय ढांचा वास्तव में जमीनी स्तर पर किस तरह आजमाया जा सकता है।

जीएसटी की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि आपूर्ति के प्रत्येक चरण में आपूर्ति के पिछले चरण के दौरान दिये गये कर के एवज में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इससे भारी भरकम अथवा दोहरे कराधान से निपटने में बहुत मदद मिलेगी। कर में इस सुधार को सूचना प्रौद्योगिकी के गहन उपयोग (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क अथवा जीएसटीएन) के जरिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कर के बोझ में अत्यधिक पारदर्शिता आयेगी, केंद्र तथा राज्य के कर प्रशासनों में जवाबदेही आयेगी और करदाताओं को कम खर्च पर अनुपालन के स्तर बढ़ाने में मदद भी मिल जाएगी। अध्ययनों से पता चलता है कि जीएसटी लागू होने से आर्थिक वृद्धि को तुरंत गति मिलेगी और इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर में 1 से 2 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

जीएसटी से केंद्र को लाभ

- भारत में एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने में सहायक होगा, जिससे विदेशी निवेश और *मेक इन इंडिया* अभियान को बल मिलेगा।
- करों का बोझ कम होगा क्योंकि आपूर्ति के प्रत्येक चरण पर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं में *इनपुट टैक्स क्रेडिट* मिल जाएगा।
- सभी राज्यों में केंद्र तथा राज्य के बीच कर कानूनों, प्रक्रियाओं एवं दरों में तालमेल स्थापित होगा।
- अनुपालन में तेजी आयेगी क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन भरे जाएंगे, इनपुट क्रेडिट का सत्यापन भी ऑनलाइन होगा और आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक पड़ाव पर हुए लेनदेन का कागजी प्रमाण रखा जाएगा।
- एसजीएसटी और आईजीएसटी की समान दरें होने से पड़ोसी राज्यों के बीच दरों का अंतर नहीं रहेगा और राज्यों के भीतर एवं बाहर बिक्री करने में भी दरों का अंतर नहीं रहेगा, जिससे कर चोरी करने का कोई लाभ नहीं होगा।
- करदाताओं के पंजीकरण और करों की वापसी (रिफंड) की एक समान प्रक्रिया, कर रिटर्न के एक समान प्रारूप, एक समान कर आधार, वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्गीकरण की साझा व्यवस्था से कराधान प्रणाली में अधिक निश्चितता आयेगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग से करदाता एवं कर अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क कम हो जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार कम करने में बहुत मदद मिलेगी।
- इससे निर्यात एवं विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, अधिक रोजगार का सृजन होगा और इस प्रकार लाभप्रद रोजगार के साथ जीडीपी में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक वृद्धि भी तेज होगी।
- अंततः अधिक रोजगार एवं अधिक वित्तीय संसाधनों के सृजन द्वारा इससे गरीबी दूर करने में सहायता होगी।

कर में इस सुधार को सूचना प्रौद्योगिकी के गहन उपयोग (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क अथवा जीएसटीएन) के जरिये सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कर के बोझ में अत्यधिक पारदर्शिता आयेगी, केंद्र तथा राज्य के कर प्रशासनों में जवाबदेही आयेगी और करदाताओं को कम खर्च पर अनुपालन के स्तर बढ़ाने में मदद भी मिल जाएगी।

व्यापार एवं उद्योग को लाभ

- कम छूट के साथ अधिक सरल कर प्रणाली।
- हमारी वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में होने वाले करों के दोहराव में कमी, जिससे सरलीकरण होगा और समानता आयेगी।
- काम के अनुबंध, सॉफ्टवेयर, आतिथ्य जैसे कुछ निश्चित क्षेत्रों में दोहरे कराधान की समाप्ति।
- करों का बोझ कम होगा क्योंकि आपूर्ति के प्रत्येक चरण पर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं में *इनपुट टैक्स क्रेडिट* मिल जाएगा। अनुपालन का खर्च कम होगा।
- विभिन्न प्रकार के करों के लिए अनेक रिकॉर्ड नहीं रखने होंगे।
- रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए संसाधनों तथा कर्मचारियों में कम निवेश करना होगा।
- करों, विशेषकर निर्यात पर लगने वाले करों को बेहतर ढंग से निष्प्रभावी किया जाएगा, जिससे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो जाएंगे और भारत से होने वाले निर्यात को बल मिलेगा।
- पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, कर भुगतान जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सरल एवं स्वचालित प्रक्रियाएं।
- वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर औसत कर बोझ घटने की अपेक्षा, जिससे खपत बढ़ेगी और परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे भारत में औद्योगिक विनिर्माण को बढ़त मिलेगी।

उपभोक्ताओं को लाभ

- विनिर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं के बीच *इनपुट टैक्स क्रेडिट* के निर्बाध प्रवाह के कारण वस्तुओं का अंतिम मूल्य पारदर्शी रहने की संभावना है। ढेर सारे कर नहीं लगने के कारण भविष्य में जींसो तथा वस्तुओं के मूल्य में कमी आयेगी।
- छोटे खुदरा विक्रेताओं के अपेक्षाकृत बड़े वर्ग को या तो कर से छूट मिल जाएगी अथवा एक विशेष योजना के अंतर्गत उन पर कर की दर बहुत कम होगी, जिससे उनसे खरीददारी करना उपभोक्ताओं के लिए सस्ता पड़ेगा।
- अधिक रोजगार एवं अधिक वित्तीय संसाधन तैयार होने से गरीबी दूर होगी।

राज्यों को लाभ

- कर आधार में विस्तार होगा क्योंकि राज्य विनिर्माण से लेकर खुदरा तक पूरी आपूर्ति शृंखला से कर वसूल सकेंगे।
- अभी तक केंद्र सरकार ही सेवाओं पर

कर वसूलती थी, लेकिन अब इसका अधिकार राज्यों को भी मिलने से राजस्व में वृद्धि होगी और राज्यों को अर्थव्यवस्था के इस सबसे तेज विकास कर रहे क्षेत्र का उपयोग करने का अवसर मिल जाएगा।

- जीएसटी गंतव्य (अंतिम बाजार) पर आधारित उपभोग कर है, जिसका लाभ उपभोग करने वाले राज्यों को मिलेगा।
- देश में निवेश का समूचा वातावरण सुधरेगा, जिसका स्वाभाविक लाभ राज्यों को विकास के रूप में प्राप्त होगा।
- एसजीएसटी और आईजीएसटी की समान दरें होने से पड़ोसी राज्यों के बीच दरों का अंतर नहीं रहेगा और राज्यों के भीतर एवं बाहर बिक्री करने में भी दरों का अंतर नहीं रहेगा, जिससे कर चोरी करने का कोई लाभ नहीं होगा।
- अनुपालन का स्तर बढ़ने से राज्यों के राजस्व संग्रह में होने वाली वृद्धि में करदाताओं का भी अच्छा योगदान रहेगा।

वर्तमान स्थिति

- इस ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार को लागू करने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक (122वां संशोधन) लाया गया और उसे 3 अगस्त, 2016 को राज्यसभा एवं 8 अगस्त, 2016 को लोकसभा ने पारित कर दिया।
- उपरोक्त विधेयक को 15 से अधिक राज्यों ने भी अनुमोदित कर दिया और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति ने 8 सितंबर, 2016 को संविधान संशोधन (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 को मंजूरी दे दी।
- उसके बाद से जीएसटी परिषद को संवैधानिक निकाय बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जो जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगी।
- भारत सरकार ने 16 सितंबर, 2016 को एक अधिसूचना जारी कर उपरोक्त विधेयक की सभी धाराओं को लागू कर दिया, जिससे जीएसटी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ हो गयी। अधिसूचना में जीएसटी को लागू करने के लिए एक वर्ष तक की अर्थात् 15 सितंबर, 2017 तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

जीएसटी परिषद की बैठकें

संवैधानिक (122वां संशोधन) विधेयक के अंतर्गत निर्णय करने वाली सर्वोच्च संस्था जीएसटी परिषद ने अपने गठन के बाद से 13 बार बैठक की हैं और परिषद की विभिन्न बैठकों में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं:

- जीएसटी परिषद में कार्रवाई के नियम।
- जीएसटी के क्रियान्वयन की समय सारणी।
- 20 लाख रुपये तक के कारोबार पर राज्य जीएसटी नहीं लगाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 279ए में बताये गये विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 10 लाख रुपये तक के कारोबार पर जीएसटी नहीं लगेगा।
- कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिए 50 लाख रुपये की सीमा होगी। सेवा प्रदाताओं एवं कुछ अन्य को कंपोजिशन योजना से बाहर रखा जाएगा। जीएसटी के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि का मुआवजा 5 वर्ष तक देने के लिए राज्यों के राजस्व का आधार वर्ष 2015-16 होगा और उसमें प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत वृद्धि मानी जाएगी।
- पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न, रिफंड, बिल एवं डेबिट/क्रेडिट नोट आदि पर जीएसटी नियमों के मसौदे को यह मानते हुए मंजूरी मिल गयी कि हितधारकों अथवा विधि विभाग की उचित सलाह के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की अनुमति से मामूली परिवर्तन किये जा सकेंगे।
- अभी लागू किसी भी कर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर से छूट पा रही सभी इकाइयों को जीएसटी व्यवस्था में कर चुकाना पड़ेगा और किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन योजना जारी रखने का निर्णय संबंधित राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार लेगी। यदि राज्य अथवा केंद्र सरकार किसी वर्तमान छूट/प्रोत्साहन योजना को जारी रखने का निर्णय लेती है तो उसे प्रतिपूर्ति प्रणाली के तहत संचालित किया जाएगा।
- कर की चार दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत निर्धारित की गयी हैं। उनके अतिरिक्त छूट वाली वस्तुओं की एक श्रेणी होगी और लग्जरी कार, एयरेटेड पेय, पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों जैसी कुछ वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की अधिकतम जीएसटी दर के बाद उपकर भी लगाया जाएगा।
- लोकसभा ने 29 मार्च, 2017 को और राज्यसभा ने 6 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक, 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक, 2017, केंद्र शासित प्रदेश (विधान मंडल से रहित) वस्तु एवं सेवा कर (यूटी जीएसटी) विधेयक, 2017 तथा वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017 पारित कर दिये हैं। जीएसटी परिषद ने 31 मार्च, 2017 को निम्नलिखित जीएसटी नियमों के मसौदों को मंजूरी दे दी है और अब उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है।
  - पंजीकरण के नियम।
  - रिटर्न के नियम।
  - बिल (बीजक) संबंधी नियम।
  - भुगतान के नियम।
  - रिफंड के नियम।
  - इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम।
  - मूल्यांकन (वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण) के नियम।
  - परिवर्ती (बीच की अवधि के लिए) नियम।
  - कंपोजिशन के नियम।

जीएसटी के क्रियान्वयन की राह में निम्नलिखित चुनौतियां हैं

- 1 जुलाई, 2017 तक जीएसटी लागू करने की अवधि बहुत चुनौतीपूर्ण है।
- राज्य विधानमंडलों द्वारा मसौदा कानूनों को मंजूरी।
- विशेषकर राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा एवं कर प्रणाली का तकनीकी उन्नयन।
- व्यापार एवं उद्योग के लिए आईटी प्रणाली का उन्नयन। ❑

नये प्रकाशन

राष्ट्रपति भवन शृंखला: प्रकाशन विभाग की अभिनव प्रस्तुति

गत तीन वर्षों के दौरान, प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रपति कार्यालय व राष्ट्रपति संपदा के विभिन्न पहलुओं को समेटकर, पाठकों को राष्ट्रपति भवन की रहस्यात्मक झांकी दिखाते हुए तथा एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामाजिक थाती को संजोते हुए उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकों की शृंखला प्रकाशित की है। कुल 17 पुस्तकों की यह शृंखला (जिनमें से एक प्रकाशनाधीन है) भावी पीढ़ी के लिए काफी उपयोगी और विवरणात्मक हैं।

राष्ट्रपति भवन शृंखला के प्रकाशन की शुरुआत 2014-2017 के दौरान पुस्तकों के विमोचन की पूर्वनिर्धारित समय-सीमा के साथ 2014 में हुई थी। प्रकाशित खंडों का विमोचन विगत तीन वर्षों के दौरान 25 जुलाई (राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रणव मुखर्जी के पदारोहण की तिथि) तथा 11 दिसंबर (माननीय राष्ट्रपति का जन्मदिन) को संपन्न कार्यक्रमों के दौरान किया गया। माननीय उपराष्ट्रपति तथा माननीय प्रधानमंत्री ने इन समारोहों के दौरान राष्ट्रपति को पुस्तकों की पहली प्रति भेंट की। इस सम्मानित शृंखला की पुस्तकों के शीर्षक निम्नवत हैं:

1. अबॉड अंडर द डॉम (स्टेट गेस्ट्स एट रायसिना हिल: 1947-67)
2. लाइफ एट राष्ट्रपति भवन
3. विंग्ड वंडर्स ऑफ राष्ट्रपति भवन
4. द फर्स्ट गार्डन ऑफ द रिपब्लिक: नेचर इन द प्रेसिडेंट्स एस्टेट
5. ए वर्क ऑफ ब्यूटी: आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द राष्ट्रपति भवन
6. आर्ट्स एंड इंटीरियर्स ऑफ द राष्ट्रपति भवन
7. राइट ऑफ द लाइन: द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड
8. द प्रेसिडेंशियल रीट्रीट्स ऑफ इंडिया
9. अराउंड इंडियाज फर्स्ट टेबल: डाइनिंग एंड एंटरटेनिंग ऐट द राष्ट्रपति भवन
10. इन्द्रधनुष: वॉल्यूम-1
11. इन्द्रधनुष: वॉल्यूम-2
12. डिस्कवर द मैग्निफिशेंट वर्ल्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन (बच्चों के लिए)
13. राष्ट्रपति भवन: फ्रोम राज टू स्वराज